ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 23 | दिसंबर 2023 / Issue 01 | मूल्य : ₹ 70

dhyeyaias.com

डीपफेक: साइबर अपराध की नई उभरती चुनौती

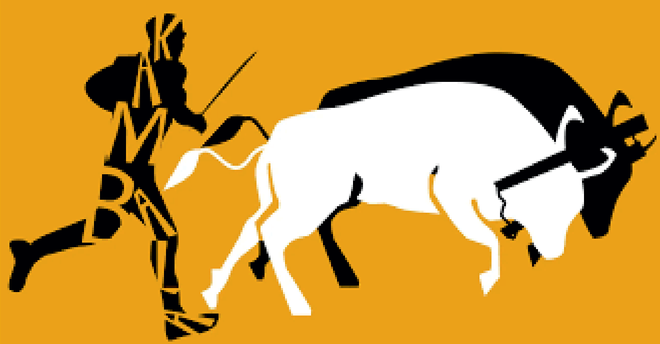

मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता

म्यांमार की आंतरिक स्थिति का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 के निहितार्थ

भारत में धारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास: चुनौतियां और संभावनाएं

वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती और सक्रिय होता एनजीटी

नेत्र और नैटग्रिड जैसे सर्विलांस सिस्टम का औचित्य तथा सर्वोच्च न्यायालय

प्रीलिम्स स्पेशल 2024: कला एवं संस्कृति

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

PERFECT 7

Complete fortnightly magazine for **UPSC** and **PCS** exams

Fortnightly Current Affairs Magazine

ध्येयIAS
most trusted since 2003
परफेक्ट 7
यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक पत्रिका

*Available Fortnightly in **Hindi** & **English***

Features :

- Upto date current affairs.
- 7 Editorials by experts.
- 42 Power packed articles focus on Pre cum mains .
- 7 Concept based Brain Boosters.
- Compact & relevant information.
- Special focus on info-graphics, data and maps.
- Pre focussed static and current MCQs.
- Places in news with map.
- Short articles and one liners for prelims.
- Special content for Prelims & Mains.
- Special section for state PCS current affairs.

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
70	24	1680	1320

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
70	12	840	720

**Postal charges extra*

For More info : **9369227134** | *perfect7magazine@gmail.com*

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

संस्थापक : विनय सिंह
प्रबंध निदेशक : क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक : विजय सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग : ऋषिका, प्रमोद
: प्रत्यूषा, पूर्णाशी
: रत्नेश, अर्पित
: तपस्या, अर्शदीप
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : नितिन अस्थाना
: शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग एवं डेवलेपमेंट : अरूण मिश्र
: पुनीष जैन
सोशल मीडिया : केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग : प्रियांक
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

समसामयिकी लेख

1. मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता 5-6
2. नेत्र और नैटग्रिड जैसे सर्विलांस सिस्टम का औचित्य तथा सर्वोच्च न्यायालय 7-8
3. म्यांमार की आंतरिक स्थिति का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव 9-10
4. डीपफेक: साइबर अपराध की नई उभरती चुनौती 11-12
5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 के निहितार्थ 13-14
6. भारत में धारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास: चुनौतियां और संभावनाएं 15-16
7. वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती और सक्रिय होता एनजीटी 17-18

- राष्ट्रीय 19-23
- अंतर्राष्ट्रीय 24-28
- पर्यावरण 29-32
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 33-37
- आर्थिकी 38-42
- विविध 43-47
- ब्रेन-बूस्टर 48-54

प्री स्पेशल

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 56-59
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में 60
- चर्चा में रहे प्रमुख स्थल 61
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 62-64
- कला एवं संस्कृति 65-78

मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता

मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर स्थिति में होना एक अमूल्य परिसंपत्ति से कम नहीं होता है। बेहतर मनः स्थिति होने पर व्यक्ति सृजनात्मक गतिविधियों को दिशा दे सकता है और बौद्धिक संपदा को सृजित कर सकता है, लेकिन भारत सहित पूरी दुनिया में जिस तरह से मानसिक तनाव एवं अवसाद के चलते मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं वह व्यक्ति, परिवार, समाज व अर्थव्यवस्था सभी के लिए चिंता का विषय बन रही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्यस्थल पर अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ भी हो रहे हैं। मानसिक बीमारियों ने ड्रग एडिक्शन को भी बढ़ावा दिया है जिससे मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति आज अकेलेपन का शिकार हो गए हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में लोनलीनेस यानी अकेलेपन को एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के रूप में घोषित किया है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक इंटरनेशनल कमीशन लॉन्च किया जिसका नेतृत्व अमेरिकी सर्जन जनरल डॉ विवेक मूर्ति ने किया। इस आयोग को अफ्रीकी यूनियन के युवा दूत से भी सहायता मिली। विशेषज्ञों के दल ने कहा है कि लोनलीनेस का मृत्युकारी प्रभाव एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 महामारी के बाद जिस तरीके से लोगों के व्यवसाय, बिजनेस प्रभावित हुए हैं, उसने भी अकेलेपन को एक बीमारी के रूप में बढ़ाया है। कोविड महामारी के चलते सामाजिक संपर्कों में कमी आई है, इसलिए समाज से कटाव की स्थिति भी देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने यहां तक कहा है कि स्कूल, कालेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी इस स्थिति का शिकार हुए हैं। डब्ल्यूएचओ ने इन्हीं गंभीर स्थितियों को देखते हुए 'डब्ल्यूएचओ कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन' को लॉन्च किया है जिसमें 11 सदस्य हैं। वैश्विक स्तर पर लोगों के मध्य सामाजिक अंतरसंपर्को को बढ़ावा देने के साथ लोनलीलेस जैसे गंभीर स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए यह आयोग अनुसंधान भी कर रहा है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां:

- इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइकियाट्री में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर चौथा व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्या जैसे चिंता, तनाव, अवसाद आदि से ग्रस्त हैं, वहीं यूनिसेफ की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 14 प्रतिशत बच्चे अवसाद की गिरफ्त में हैं। लगातार बढ़ रही इस समस्या के समाधान के लिए हम सभी को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सजग होने की जरूरत है।
- मानसिक रोग के कारण भारत पर पड़ने वाले बोझ को लेकर भारतीय चिकित्सा शोध परिषद (आईसीएमआर) ने 2017 में पहली बार इस पर व्यापक अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला है कि 4.57 करोड़ लोग आम मानसिक विकार अवसाद और 4.49 करोड़ लोग बेचैनी से पीड़ित हैं। हर सातवां भारतीय किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। अवसाद, बेचैनी, सिजोफ्रिनिया, द्विध्रुवीय रोग (Bipolar Disease), आचरण संबंधी रोग और ऑटिज्म आदि मानसिक रोग के प्रकार हैं। इनमें डिप्रेशन (अवसाद), एंग्जाइटी (चिंता) और सिजोफ्रेनिया (Schizophrenia) से लोग सबसे ज्यादा परेशान होते रहे हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी सबसे सामान्य रूप से मिलने वाली समस्याएं हैं। इन दोनों का असर भारत में बढ़ता दिख रहा है, जबकि महिलाओं और दक्षिण भारतीय राज्यों में इनका असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है।

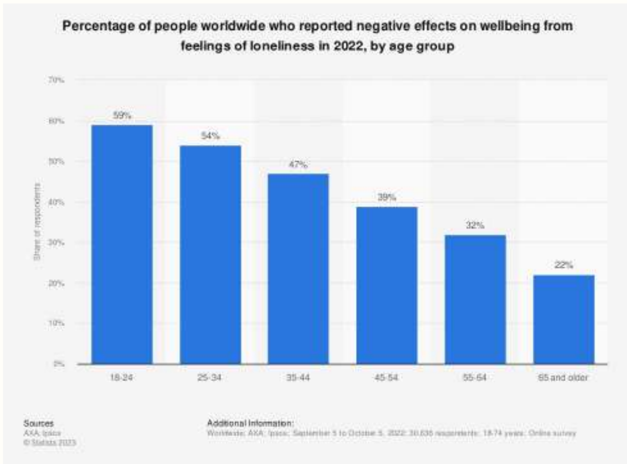

भारत में मानसिक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने हेतु उपाय:

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमः** भारत सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा सबके लिये न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एमएमएचपी) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर अग्रसर होना था। इस कार्यक्रम के मुख्यतः 3 घटक हैं जिसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज, उसका समावेशी पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य संवर्द्धन और रोकथाम शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अलावा 10 अक्टूबर, 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई तथा भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया। इसने मानसिक

स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का स्थान लिया।

- **टेली मानस हेल्पलाइन:** पूरे देश में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) हेल्पलाइन ने अक्टूबर 2022 में अपने लॉन्च के बाद से एक लाख से अधिक कॉल प्राप्त करके एक संतोषजनक उपलब्धि अर्जित किया है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर 2022 को भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरूआत के बाद से ही इस सेवा का उद्देश्य एक डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना रहा है जिससे मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढावा मिला है। कोविड महामारी को देखते हुए एक डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इसका उद्देश्य देश के सबसे दूर-दराज हिस्से में भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को 24 घंटे उपलब्ध कराना है। ये सेवाएं सभी व्यक्तियों के लिए टोल फ्री नंबर 14416/1800-89-14416 के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं।

- भारत का राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से राष्ट्र के मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हर घर और हर व्यक्ति तक निःशुल्क पहुंच सकें तथा समाज के सबसे कमजोर, वंचित और अंजान तबके को लक्षित करके लाभ प्रदान कर सकें। इन 6 महीने में टेली मानस एक लाख के आंकड़ों को पार कर गया है और इसने पूरे भारत में एक मजबूत डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क का निर्माण करने के अंतिम लक्ष्य को हासिल करने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
- **738 जिलों में एनएमएचपी के कार्यान्वयन को मंजूरी:** देश में किफायती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के घटक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की निरंतर देखभाल व सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं।
- **आयुष्मान भारत के दायरे में मानसिक स्वास्थ्य:** आयुष्मान भारत-एचडब्ल्यूसी योजना के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल तथा मादक द्रव्यों के उपयोग संबंधी विकारों (एमएनएस) पर प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- **निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा 'ई-संजीवनी :** ई-संजीवनीएबी एचडब्ल्यूसी (जोकि डॉक्टर-से-डॉक्टर के बीच एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है) को लगभग 21,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों और लगभग 30 राज्यों के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में स्थित 1900 से अधिक हब में स्पोक्स के तौर पर लागू किया गया है। डॉक्टर-से-डॉक्टर के बीच के इस टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने 32 लाख से अधिक रोगियों की सेवा की है। रक्षा मंत्रालय ने भी 'ई-संजीवनी' ओपीडी पर एक राष्ट्रीय ओपीडी का आयोजन किया है, जहां रक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाए गए 100 से अधिक अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ देशभर के मरीजों की सेवा करते हैं। 'ई - संजीवनी' ने 2021 में 70 लाख परामर्श पूरे करने की उपलब्धि हासिल की थी।
- 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने विश्व के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को यथार्थवादी बनाने के लिये वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि मानसिक बीमारियों से एक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण से ही निपटा जा सकता है जिसके लिए जरूरी विधायी, संस्थागत उपायों के साथ हेल्थकेयर तंत्र को कुशल, मानवीय तथा संवेदनशील बनाना होगा।

नेत्र और नैटग्रिड जैसे सर्विलांस सिस्टम का औचित्य तथा सर्वोच्च न्यायालय

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है जिसमें कुछ सर्विलांस सिस्टम जैसे नेटग्रिड, नेत्र और सीएमएस से जुड़ी जनहित याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करने की मांग की गई है। अभी वर्तमान में यह पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पीआईएल हस्तांतरण की याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन नामक एनजीओ और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने की है। इन दोनों ही संगठनों का कहना है कि नेटग्रिड, नेत्र और सीएमएस केंद्र सरकार तथा राज्य विधि प्रवर्तनकारी अभिकरणों को बड़ी मात्रा में सभी दूरसंचार को इंटरसेप्ट तथा मॉनिटर करने करने की क्षमता देते हैं। इससे लोगों के पर्सनल डेटा का विश्लेषण करने का भी मौका मिल सकता है जो अनुचित है। इससे पहले 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार सर्विलांस सिस्टम जैसे नेटग्रिड, नेत्र और सीएमएस के जरिए लोगों का डेटा संग्रहण करना बंद करे क्योंकि इन तीनों निगरानी प्रणालियों से नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। उल्लेखनीय है कि निजता के अधिकार को मूल अधिकार भी घोषित किया जा चुका है।

- एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मत है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नैटग्रिड), नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस (नेत्र) और सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएस) के जरिए संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का लक्ष्य है, वहीं कुछ लोगों व संगठनों के द्वारा इसका दुरुपयोग करके लोगों के राइट टू प्राइवेसी को उल्लंघन करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ नेत्र के जरिए ऑनलाइन गतिविधियों पर निगाह रखी जा सकती है, लोगों के संदिग्ध ईमेल तथा निजी सन्देश को ट्रैक किया जा सकता है, वहीं सीएमएस के जरिए फोन वार्ताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। केंद्र सरकार का मानना है की नेत्र और सीएमएस के जरिए आतंकवादी गतिविधियों पर निगाह रखते हुए सूचना इकट्ठा किया जा सकेगा। कौन आतंकवादी किस आतंकी से संपर्क कर रहा है? उनके बीच क्या बातें हो रही हैं? अलगाववादियों के बीच आपस में कौन से मैसेज साझा किए जा रहे हैं? भारत सरकार विरोधी क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? इन सब की जानकारी कुछ सर्विलांस सिस्टमों को विकसित करके की जा सकती है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों का मत है कि इनका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भी किया जा सकता है।
- सितंबर, 2019 में देश के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि वह देश में काफी समय से लंबित पड़े राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड) को अधिकतम मार्च, 2020 तक गठित करके कार्यशील बना देगा, लेकिन पुनः देश की संसद में स्पष्ट किया गया कि इसे 31 दिसंबर, 2020 तक कार्यशील बनाया जाएगा। कोविड महामारी के चलते इसमें और विलंब हुआ। वास्तव में खुफिया जानकारी किसी भी देश में आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता करने में अहम भूमिका निभाती रही है। राष्ट्र, समाज एवं कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा करने वाले राष्ट्रविरोधी और समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के उन्मूलन अथवा उसके नियंत्रण के लिए देश में सुदृढ़ आसूचना तंत्र का होना जरूरी है। देश की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले आतंकवादियों, अपराधियों तथा उनके षड्यंत्रों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। भारत में 26 नवंबर, 2008 को विधि दिवस (अब संविधान दिवस) पर मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने भारत में कानून व्यवस्था पर घातक प्रहार किया था। इस घटना के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसी राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड हो जिसके पास देश की सुरक्षा से जुड़ी सभी खुफिया जानकारी एकत्रित हो। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर वर्ष 2009 में तत्कालीन भारत सरकार ने नैटग्रिड के रूप में एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड) के गठन का निर्णय किया था। अमेरिकी संदिग्ध आतंकी डेविड हेडली की रीयल टाइम इंफॉर्मेशन के अभाव में पहचान न हो पाना मुंबई आतंकी हमलों के दौरान एक चूक मानी गई थी। यदि 2006 से 2009 के बीच डेविड हेडली के कई दफे भारत आने की सूचना खुफिया स्तर पर मिल जाती और उसे निरुद्ध किया जाना संभव हो पाता, तो शायद मुंबई आतंकी हमले को रोका जा सकता था या उससे हुयी क्षति कम हो सकती थी।
- हेडली ने उस वक्त पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा को आतंकी हमलों के लक्षित स्थलों के वीडियो और अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई थी। इस हमले में 166 लोगों की जानें गई थीं जिसके बाद 8 अप्रैल, 2010 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3400 करोड़ रुपए की लागत वाली नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नैटग्रिड) के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन वर्ष 2012 के बाद इस दिशा में प्रगति धीमी हो गई। 10 जून, 2016 को इस संबंध में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव द्वारा इस परियोजना के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया था। इसके उपरांत नैटग्रिड को कार्यशील बनाने की आवश्यकता पर बल देना शुरू हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सितंबर, 2019 में इस प्रोजेक्ट के प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय के सूत्रों से स्पष्ट हुआ है कि इस प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इसके दो सेंटर होंगे जिसमें पहला, बैंगलुरू में डाटा रिकवरी सेंटर होगा और दूसरा दिल्ली में

मुख्यालय होगा।

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की कार्यप्रणालीः

- नैटग्रिड का मूल लक्ष्य देश की सुरक्षा के समक्ष उपस्थित खतरों और उन्हें उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन एकत्रित करके इनके खिलाफ कार्यवाही करने में सहायक बनना है। यह देश के सुरक्षा बलों, आसूचना तंत्रों और विधि प्रवर्तनकारी निकायों के सहायक के रूप में भी कार्य कर सकेगा। खुफिया इनपुट का विश्लेषण करने के लिए नेटग्रिड के पास देश में आने वाले और यहां से दूसरे देश जाने वाले हर देशी-विदेशी व्यक्ति का पूरा डाटा उपलब्ध होगा। बैंकिंग व वित्तीय लेनदेन, इमिग्रेशन, कार्ड से खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल व फोन कॉल, सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंटरनेट सर्च, व्यक्तिगत करदाता, हवाई यात्रियों और रेल यात्रियों का रियल टाइम डाटा, माओवादियों-नक्सलियों की गतिविधियों, जाली मुद्रा गिरोह, नारकोटिक ड्रग्स से जुड़ी जानकारी आदि तक भी नेटग्रिड की पहुंच होगी। इसकी मदद से सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध हरकत पर 24 घंटे नजर रख सकेंगी। नेटग्रिड सभी तरह के डाटा का एनालिसिस करके उसे खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाएगा जिसके बाद नेटग्रिड सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविध पर अलर्ट करेगा।
- नेटग्रिड का डाटा देश की 11 सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम मिलेगा। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, केंद्रीय सचिवालय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस तथा नारकोटिक्स कंट्रल ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी शामिल हैं।
- नैटग्रिड की रूपरेखा जिस तरह से नए प्रावधानों के साथ तय की गई है, उससे कई राज्यों को आपत्ति है। उनको लगता है कि जो भी संवेदनशील आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, उन पर देश के 11 प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा अभिकरणों का ही अधिकार होगा जिससे केंद्र सरकार की स्थिति ही इस मामले में मजबूत होगी और राज्य सरकारों के अधिकार प्रभावित होंगे। गृह मंत्रालय का कहना है कि नेटग्रिड के पास देश के सभी वर्ग के नागरिक का डाटा मौजूद रहेगा। ऐसे में इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बेहद महत्त्वपूर्ण है। लिहाजा राज्यों की सुरक्षा इकाईयों को सीधे डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। राज्य की जांच व सुरक्षा एजेंसियों को उन 11 केंद्रीय एजेंसियों की मदद से डाटा प्राप्त करना होगा जिन्हें नेटग्रिड में एक्सेस दिया गया है।
- आयकर विभाग से लगभग 8 करोड़ करदाताओं का डाटा हासिल करने की प्रक्रिया को नेटग्रिड प्रबंधन ने अंतिम रूप दे दिया है, जबकि घरेलू हवाई यात्रियों का डाटा हासिल करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशक सहित सभी एयरलाइंस के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। पहले चरण में नेटग्रिड से 11 एजेंसियों और 21 सेवा प्रदाताओं का डाटा जोड़ा जाएगा। भविष्य में करीब 1000 अन्य संगठनों का गोपनीय डाटा नेटग्रिड से जोड़ने की योजना है। फिलहाल बैंकिंग लेनदेन और इमिग्रेशन का डाटा नेटग्रिड पर रियल टाइम मैकेनिज्म के तहत सुरक्षा एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सकारात्मक अर्थों में देखें तो देश में आतंकवाद, संगठित अपराध, नक्सलवाद, माओवाद, उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में उग्रवादी गुटों की अलगाववादी गतिविधियों तथा तस्करी करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की दृष्टि से नैटग्रिड जैसे संगठन को गठित करना काफी हद तक ठीक भी लगता है, लेकिन इसके साथ ही व्यक्ति के मूल अधिकारों खासकर निजता के अधिकार की सुरक्षा, संघीय संरचना के आदर्शों के तहत राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखने, गोपनीय आंकड़ों के दुरुपयोग की संभावना को रोकने का आश्वासन देने जैसे संदर्भों को भी केंद्र सरकार को ध्यान में रखकर नैटग्रिड को मूर्तमान स्वरूप देना ठीक रहेगा।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL
DHYEYA TV QR
BATEN UP KI QR
Follow the below mentioned instructions :
Scan the above QR Code on your phone. | Click on the link. | Subscribe to our channel. | Get updated on Current Affairs & UP Specific News.

म्यांमार की आंतरिक स्थिति का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव

म्यांमार का सत्ताधारी दल मिलिट्री जुंटा इस समय देश में गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहा है। कई फ्रंट से म्यांमार के हिंसक नृजातीय उग्रवादी समूहों और विद्रोही गुटों ने म्यांमार की सैन्य सरकार के जवानों तथा उनके ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के विद्रोहियों (करेन, काचिन व अराकान) ने एक एलायंस तैयार करके म्यांमार की वर्तमान सैन्य सरकार को हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इन सभी का उद्देश्य अब जुंटा शासन को खत्म करके अपना नियंत्रण स्थापित करना है। इन नृजातीय विद्रोही समूहों ने पिछले माह म्यांमार के उत्तरी शान राज्य के मिलिट्री पोस्ट पर भीषण हमले किए थे जिसकी सीमा चीन से लगती है। इस हमले के दौरान सरकारी नियंत्रण से विद्रोही गुटों ने कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में भी ले लिया था। इन विद्रोहियों ने 'ऑपरेशन 1027' के तहत हिंसक कार्यवाही की थी। थ्री ब्रदरहुड एलायंस (जो मिलिट्री जुंटा के खिलाफ हिंसक हमलों के लिए जिम्मेदार है) का कहना है कि वह आत्म सुरक्षा और आत्म निर्धारण अधिकार के तहत म्यांमार सेना के हवाई हमलों का प्रतिकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका कहना है कि दमनकारी सैन्य तानाशाही को म्यांमार से हटाना उनका मुख्य उद्देश्य है।

- भारत और म्यांमार के संबंध एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति में दिख रहे हैं। म्यांमार में जिस तरह से तनाव और संघर्ष की स्थिति बढ़ी हुई है, उसको देखते हुए भारत को अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके कहना पड़ा है कि वे म्यांमार की यात्रा करने से बचें। इसके अतिरिक्त जो भारतीय म्यांमार में पहले से ही रह रहे हैं, उन्हें सावधानी बरतने की भी सलाह भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इन बातों को स्पष्ट किया है।

म्यांमार का नृजातीय संघर्ष चिंता का विषय:

- म्यांमार का वर्तमान नृजातीय संघर्ष भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यह इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में म्यांमार के नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल के काउंसलर ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत को म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के प्रति वन साइडेड पॉलिसी रखते हुए उससे ही तालमेल बिठाने का काम नहीं करना चाहिए। भारत को म्यांमार के एथनिक माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी स्पष्ट स्टैंड रखना चाहिए जिससे सैन्य सरकार पर दबाव पड़ें। दरअसल नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल निर्वासित नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का सलाहकारी निकाय है। फरवरी, 2021 में म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को वहां की सेना के उखाड़ फेंकने के बाद ही इस काउंसिल का गठन हुआ था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सैन्य सरकार के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल से सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने पर ही बल दिया है। भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और चीन म्यांमार गठजोड़ में वृद्धि के संभावित प्रभाव से अवगत है।
- दरअसल भारत का सोचना यह भी रहा है कि अगर किसी देश का प्रमुख नेतृत्व सहयोगी रुख नहीं अपनाता है, तो अवैध प्रव्रजन (रोहिंग्या व कुकी -चिन) बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में विदेशी षड्यंत्र और अलगाववादी ताकतों के बीच गठजोड़ को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए सैन्य सरकार को विश्वास में लेना भारत ने जरूरी समझा है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य सरकार ने म्यांमार के नृजातीय अल्पसंख्यक समूहों के मानवाधिकार का घोर उल्लंघन किया है, प्रेस और मीडिया के अधिकारों पर पाबंदी लगाई, एथनिक माइनॉरिटी के विरोध प्रदर्शन को बुरी तरह कुचला, नृजातीय समुदायों को उनके सभी बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जिसके चलते म्यांमार में एथनिक टेररिज्म को बढ़ावा मिला है। इसके चलते करेन विद्रोहियों ने करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी का गठन किया और करेन नेशनल यूनियन बनाया। इसी प्रकार काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी तथा काचिन इंडिपेंडेंस आर्गेनाइजेशन भी म्यांमार की सैन्य सरकार से लड़ रही है। इसके विद्रोहियों ने पूर्वोत्तर भारत के अलगाववादी और उग्रवादी समूहों को कई अवसरों पर प्रशिक्षण दिया है।
- इससे समझा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद, अलगाववाद और विप्लवकारी (इंसर्जेंसी) की गतिविधियों में म्यांमार की भूमिका कितनी संवेदनशील रही है? हाल में जब से थ्री ब्रदरहुड एलायंस से जुड़े हिंसक एथनिक विद्रोही समूहों ने म्यांमार के सैन्य कर्मियों के मिलिट्री पोस्ट पर हमले करने शुरू किए हैं, तब से भारत की सीमा से लगे हुए ऐसे सैन्य शिविरों से म्यांमार के सैनिक विद्रोहियों से जान बचाकर भारत के भूक्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं।
- म्यांमार के चिन स्टेट जो भारत-म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है, वहां तुईबुअल में मिलट्री कैंप को चिन नेशनल डिफेंस फोर्स ने तहस नहस कर दिया। जब इस विद्रोही समूह का हमला हुआ, तब म्यांमार के 29 सैनिक मिजोरम में प्रवेश कर गए जिसके बाद इन सैनिकों को भारत के प्रतिरक्षा प्राधिकारियों ने मणिपुर के मोरेह एयरलिफ्ट किया। भारत-म्यांमार बॉर्डर पर विद्रोहियों के लगातार हमले के बाद से 74 से अधिक म्यांमारी

सैनिक पूर्वोत्तर भारत में आ चुके हैं। अब मुद्दा ये है कि भारत सरकार इन सैनिकों के साथ कैसा बर्ताव करती है? उस पर म्यांमार के विद्रोही गुटों की निगाह है। अगर उन्हें यह लगता है कि भारत सैनिकों की सुरक्षा के लिए ज्यादा संवेदनशील है, तो म्यांमार के विद्रोही गुट भड़क सकते हैं जो पूर्वोत्तर के अलगावादी गुटों के साथ मिलकर भारत विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं, ड्रग्स तस्करी और हथियार तस्करी को बढ़ा सकते हैं जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

उत्तर-पूर्वी भारत की सुरक्षा और म्यांमार की वर्तमान स्थिति:

- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग (जो नागालैंड के सबसे हिंसक अलगाववादी और उग्रवादी संगठनो में एक है) ने म्यांमार में रहने वाले विद्रोहियों तथा उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले विद्रोहियों के साथ मिलकर भारत सरकार और उत्तर-पूर्वी राज्यों के सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न किया। इस गुट ने म्यांमार के टागा क्षेत्र में भारत विरोधी अभियानों को संपन्न करने का काम किया है। म्यांमार की धरती पर इनके टेरर और ट्रेनिंग कैंप चलते रहे हैं जिनमें श्वेलो कैंप प्रमुख रहा है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने म्यांमार के अराकान साल्वेशन आर्मी के विद्रोहियों और काचिन पृथकतावादियों के साथ मिलकर म्यांमार में भारत की ऊर्जा परियोजनाओं तथा विकास परियोजनाओं को निशाना बनाने की योजना बनाई। ये विद्रोही कलादान मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट और अन्य संयंत्रों को नष्ट करने की रणनीति बनाते पाए गए। इन सबसे निपटने के लिए म्यांमार और भारत की संयुक्त सेना ने फरवरी-मार्च 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक-3 (जिसे ऑपरेशन सनराइज भी नाम दिया गया) के माध्यम से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), नगा विद्रोही समूहों और अराकान साल्वेशन आर्मी के टागा स्थित आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग ने अपने कैडर को टागा में कैम्प खोलने और म्यांमार की सेना के खिलाफ जवाबी कार्यवाही के आदेश भी दिए। उन्होंने म्यांमार के कोकी क्षेत्र में भी कैम्प खोलने का निर्णय लिया। इन सब कार्यों को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) कई उत्तर पूर्वी विद्रोही संगठनों के लिंक के साथ अंजाम दे रहा है जिसमें उल्फा (आई), एनडीएफबी और केएलओ, पीएलए, एनएलएफटी शामिल हैं।
- विभिन्न एनएससीएन समूह भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रचते रहे हैं जिसको नाकाम किया जाना जरूरी है। इसी क्रम में म्यांमार के सैगिंग क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एनएससीएन (के) और अन्य समूहों की तलाश में विशेष म्यांमार सेना इकाईयां तलाशी अभियान चलाने में लगी थीं। विद्रोही समूह अराकान सेना मिजोरम के लोंग्थलाई जिले के कई इलाकों में शिविर लगाए हुए हैं जो कलादान परियोजना के लिए खतरा हैं। कलादान मल्टी-मॉडल परिवहन परियोजना को भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। इन कारणों से भारत को म्यांमार के साथ संबंधों को सहयोगपूर्ण बनाने की जरूरत रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी और भारत-म्यांमार संबंध:

- एक अन्य प्रमुख मुद्दा जो भारत और म्यांमार के द्विपक्षीय संबंधों में खलल डालता रहा है, वह है नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा। चूंकि म्यांमार नार्कोटिक ड्रग्स की तस्करी वाला क्षेत्र स्वर्णिम त्रिभुज का हिस्सा है जो चार उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा करता है, इसलिए म्यांमार के साथ भारत के संबंध बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। मणिपुर के उखरूल, चंदेल, चूरचंद्रपुर, सेनापति और थामेंगलांग जिलों में अवैध अफीम की खेती तथा कोकीन, हेरोइन, एमफेटामाइन ड्रग्स की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। ड्रग मुक्त पूर्वोत्तर और म्यांमार दोनों देशों की साझी जिम्मेदारी है। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया का 80 प्रतिशत हेरोइन उत्पादन करता है जो वैश्विक आपूर्ति के 60 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। चीन और म्यांमार के ड्रगलॉर्ड्स को एक दूसरे का सहयोग समर्थन समय समय पर मिलता रहा है, लेकिन सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि भारत-म्यांमार की सीमा पर कई हेरोइन लैब्स सक्रिय हैं। मिजोरम में म्यांमार के रास्ते से एंफेटामाइन, याबा टैबलेट्स, क्रेजी ड्रग्स, पार्टी ड्रग्स की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त भी काफी बढ़ चुकी है जो उत्तर पूर्वी भारत के युवा मानव संसाधन को क्षति पहुंचा रही है। नार्कोटिक ड्रग्स के इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, सिलचर, दीमापुर में पहुंचने के बाद इसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बंगलुरू को डिस्पैच कर दिया जाता है।
- हाल के समय में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित मोरेह पर करोड़ों रूपए मूल्य के अवैध ड्रग्स को सुरक्षा बलों द्वारा जब्त किया गया है। ऐसे कई उदाहरण अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के संबध में आए दिन मिलते रहते हैं जिससे इस व्यापार की बढ़ती विभीषिका का पता चलता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ड्रग तस्करी दोनों देशों के लिए एक गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि इससे आतंक, उग्रवादी, विप्लवकारी, पृथकतावादी गतिविधियों और उन्हें करने वाले समूहों का वित्त पोषण संभव होता है। इसलिए यह दोनों देशों के लिए आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ प्रादेशिक अखंडता का भी मुद्दा है जिसके समाधान के लिए भारत और म्यांमार ने अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित कर रखा है। इसके अलावा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय उग्रवादी अलगाववादी समूहों को चीन से भी वित्तीय सहायता तथा हथियार आपूर्ति के रूप में सहायता मिल रही है, ऐसे में भारत विरोधी नेटवर्क्स को तोड़ने में म्यांमार का सहयोग अपेक्षित है।

डीपफेकः साइबर अपराध की नई उभरती चुनौती

डीपफेक दुनिया भर में लोकतंत्र और सामाजिक संस्थानों के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से डीपफेक सामग्री के प्रसार ने इस चुनौती को बढ़ा दिया है। डीपफेक किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट और उसे डिफेम करने के साथ पैसा कमाने का जरिया बनता जा रहा है। इससे व्यक्ति के मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा और बिजनेस आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। डीपफेक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक भय के रूप में उभरा है, वैसे ही जैसे दशकों से साइबर स्टाकिंग या साइबर बुलिंग के मामले देखे जाते रहे हैं। डीपफेक अपने प्रकृति और कार्यवाही में अन्य साइबर अपराधों से थोड़ा भिन्न है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों को साइबर अपराध का भुक्तभोगी बनाया जा रहा है।

- हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्रियों और उद्यमियों को यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री को भी डीपफेक वीडियो का निशाना बनाया गया। बॉलीवुड अभिनेत्रियों में रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ, काजोल और आलिया भट्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल का शिकार होना पड़ा है। सारा तेंदुलकर और बिजनेसमैन रतन टाटा जैसी हस्तियां भी डीपफेक का शिकार बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल अश्लील कंटेंट ने चिंता बढ़ा दी है।

डीपफेक वीडियो क्या है?

- डीपफेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल मीडिया पर ऑडियो, वीडियो और इमेज की एडिटिंग से छेड़छाड़ का तरीका है। डीपफेक ऑडियो और वीडियो दोनों रूप में हो सकता है। डीपफेक जनरेटर ऐप्स भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। डीपफेक को मूल रूप से एक अति वास्तविक डिजिटल झूठेपन (Digital Falsification) के रूप में देखा जाता है। इसमें वीडियो, आडियो या इमेज के साथ डिजिटल स्तर पर ऐसी छेड़छाड़ होती है जिससे चीजें वास्तविक रूप में प्रतीत होने लगती हैं। डीपफेक से न केवल व्यक्तियों को बल्कि संस्थाओं को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि किसी भी चर्चित महिला या पुरुष के डीपफेक अश्लील वीडियो को एक बड़ा वर्ग जो असाक्षर है, सही मान बैठता है और संबंधित पुरुष, महिला या उसके संस्थान या व्यवसाय के बारे में गलत धारणा बना लेता है। शिक्षित और डिजिटली साक्षर लोग तो एआई जेनरेटेड डीपफेक वीडियो और उसके मकसद को समझ सकते हैं, लेकिन एक कम पढ़े लिखे व जागरूकता से वंचित व्यक्ति के लिए ऐसे डिजिटल/ इंटरनेट अपराधों को समझना आसान नहीं होता है। आज जिस तरह से कमोडिटी क्लाउड कम्प्यूटिंग, पब्लिक रिसर्च एआई एल्गोरिथम, प्रचुर डेटा और विस्तृत मीडिया तक आसान पहुंच बन गई है। उसके चलते डीपफेक जैसी चुनौतियों का उभरना भी आसान हो गया है। सिंथेटिक मीडिया कंटेंट के रूप में ही डीपफेक उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया या डीपफेक कुछ क्षेत्रों में गलत तरीकों से बड़ा मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जैसे एजुकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, क्रिमिनल फोरेंसिक और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तथा इनसे जुड़े डेटा की सरल उपलब्धता ने डीपफेक का काम आसान कर दिया है। डीपफेक इसलिए चुनौती है क्योंकि यह किसी के प्रति सम्मान को समाप्त करता है, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या पब्लिक को धोखा देते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास का क्षरण कर सकता है।

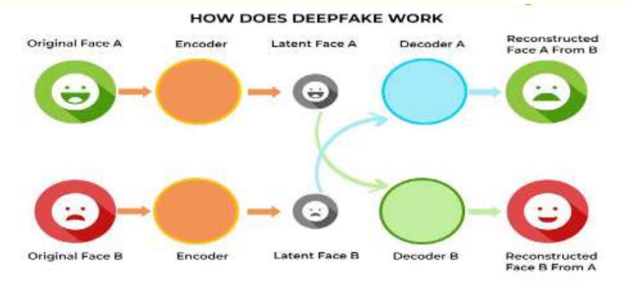

- डीपफेक को एक स्पेशल मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग में कंप्यूटर को दो वीडियोज या फोटो दिए जाते हैं जिन्हें देखकर वह खुद ही दोनों वीडियो या फोटो को एक ही जैसा बनाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे बच्चा किसी चीज की नकल करता है। इस तरह के फोटो के लिए वीडियोज में हिडेन लेयर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही देखा जाता है। संक्षेप में कहें तो डीपफेक, रियल इमेज-वीडियोज को बेहतर करके रियल फेक फोटो-वीडियोज में बदलने की एक प्रक्रिया है। डीपफेक फोटो-वीडियोज फेक होते हुए भी रियल नजर आते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो डीपफेक एक एडिटेड वीडियो होता है जिसमें किसी अन्य के चेहरे को किसी अन्य के चेहरे से बदल दिया जाता है। डीपफेक वीडियोज इतने सटीक होते हैं कि आप इन्हें आसानी से पहचान नहीं सकते। किसी भी इंसान का डीपफेक वीडियो बनाया जा सकता है। डीपफेक वीडियो बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग की भी मदद ली जाती है।
- डीपफेक दो नेटवर्क की मदद से बनता है जिनमें एक इनकोडर और दूसरा डीकोडर नेटवर्क होता है। इनकोडर नेटवर्क सोर्स कंटेंट (असली वीडियो) को एनालाइज करता है और फिर डाटा को डीकोडर नेटवर्क को भेजता है। उसके बाद फाइनल आउटपुट निकलता है जो कि हूबहू असली जैसा होता है, लेकिन वास्तव में वह फेक होता है। इसके लिए सिर्फ एक वीडियो की जरूरत होती है। डीपफेक के लिए कई वेबसाइट्स और एप हैं जहां लोग डीपफेक वीडियोज बना रहे हैं। इस तरह के फोटो-वीडियोज को पहचानना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है।

इन्हें पहचानने के लिए वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखना होता है। खासतौर पर चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों की मूवमेंट और बॉडी स्टाइल पर ध्यान देकर इसकी सत्यता को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा बॉडी कलर से भी आप इन्हें पहचान सकते हैं। आमतौर पर ऐसे वीडियोज में चेहरे और बॉडी का कलर मैच नहीं करता है। इसके अलावा लिप सिंकिंग से भी इस तरह के वीडियोज की पहचान की जा सकती है। ऐसे वीडियोज को आप लोकेशन और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस से भी पहचान सकते हैं। इसके अलावा अपनी समझ से भी आप यह तय कर सकते हैं कि यह वीडियो असली है या नहीं। उदाहरण के तौर पर यह जाहिर सी बात है कि बराक ओबामा का भोजपुरी गाने पर डांस का वीडियो फर्जी है।

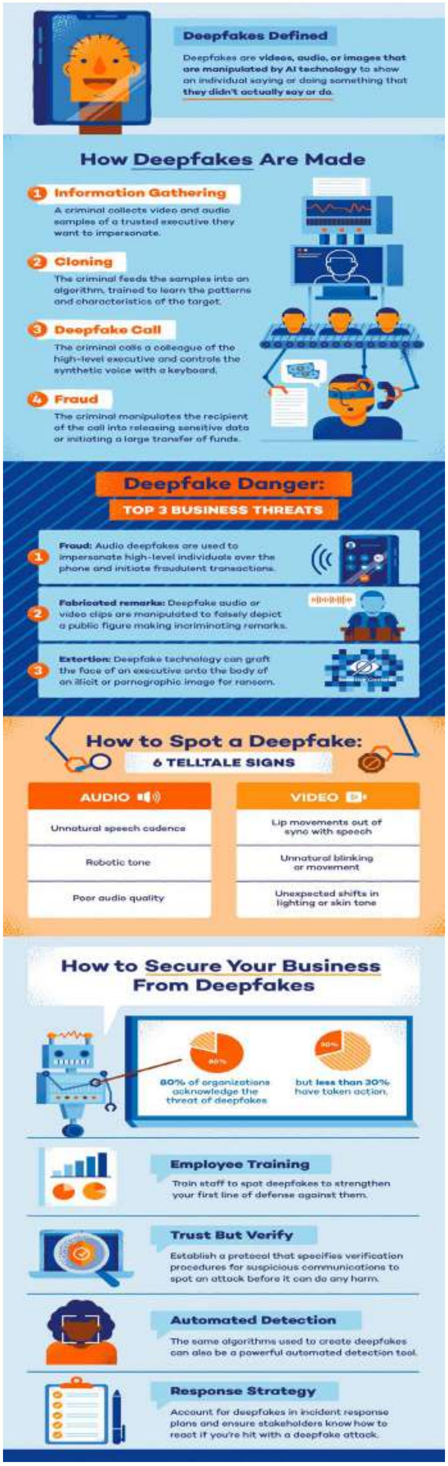

डीपफेक वीडियो बनाने पर सजाः

- वैसे भारत में डीपफेक को संबोधित करने के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं हैं, परन्तु यदि कोई भी व्यक्ति मजाक में किसी का डीपफेक वीडियोज बनाता है और शेयर करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की कई धारा और आई टी एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। इसके अंतर्गत भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी की छवि खराब होती है, तो डीपफेक बनाने वाले के खिलाफ मानहानि का भी मामला बन सकता है। इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ भी आईटी नियमों के तहत कार्यवाही हो सकती है। शिकायत के बाद 36 घंटे के अंदर सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह के कंटेंट को हटाना आवश्यक होता है।

डिजिटल इंडिया संवाद सत्र में डीपफेक से निपटने पर चर्चाः

- हाल ही में डिजिटल इंडिया संवाद सत्र का आयोजन किया गया जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री द्वारा सुरक्षित एवं विश्वसनीय इंटरनेट तथा सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को डिजिटल नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता दोहराई गई है। डीपफेक खतरों के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डीपफेक के संदर्भ में चिंताओं को जाहिर करने के बाद, सभी प्लेटफॉर्म और मध्यवर्ती अपने सामुदायिक दिशानिर्देशों को आईटी नियमों के साथ एकीकृत करने पर सहमत हुए हैं। इस क्रम में वे विशेष रूप से 11 प्रकार की सामग्री को लक्षित करते हैं जो डीपफेक सहित उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाते हैं।
- डिजिटल इंडिया संवाद सत्र में सभी मध्यवर्ती इस बात पर सहमत हुए हैं कि मौजूदा कानून और नियम, यहां तक कि जब हम नए कानूनों एवं विनियमों पर चर्चा करते हैं, तो वे उन्हें डीपफेक से निर्णायक रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि नवंबर माह के अंत तक वे सभी शर्तों और विचारों को सुनिश्चित करेंगे तथा उपयोगकर्ताओं के साथ अनुबंध आईटी नियमों में निर्धारित 11 प्रकार की सामग्री से उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल भी डीपफेक के मुद्दे और सुरक्षित तथा विश्वसनीय इंटरनेट के लिए खतरों व चुनौतियों पर प्रकाश डाला था जिसको लेकर अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय काफी संवेदनशील हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि जल्द ही 'नियम 7' अधिकारी की नियुक्ति होगी जो मध्यवर्तियों द्वारा कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। डिजिटल नागरिकों के पास सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट का अधिकार है जो इसे मध्यवर्ती प्रदान करने के लिए जवाबदेह हैं। केंद्र सरकार ने डीपफेक और गलत सूचना जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मध्यवर्तियों के साथ निरंतर सहयोग का आग्रह किया है। अभी भी डीपफेक से बचने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, विशेष रूप से गलत सूचना व सट्टेबाजी के विज्ञापन, अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों और धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स के विज्ञापनों के क्षेत्र में। ये सभी ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा बने हुए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 के निहितार्थ

इंग्लैंड के बैलेचले पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुरक्षा शिखर सम्मेलन, 2023 का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों के निदान के उद्देश्य से किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान विश्व की एक उभरती हुई तकनीकी है। हालांकि यह उभरती हुई तकनीकी विभिन्न तरह की चुनौतियों को भी जन्म दे रही है।

वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग एक ऐसी चुनौती बन चुका है जिसके निदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत तथा यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा पर आधारित पहला शिखर सम्मेलन था। इसका आयोजन इंग्लैंड के बैलेचले पार्क में किया गया। शिखर सम्मेलन के निष्कर्ष के आधार पर बैलेचले पार्क घोषणा (Bletchley Park Declaration) पर हस्ताक्षर किए गए।

क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण है।
- एआई के विशिष्ट अनुप्रयोगों में विशेषज्ञ प्रणाली, भाषा प्रसंस्करण, स्पीच रिकग्नीशन और मशीन विजन शामिल हैं।
- एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में लेबल किए गए प्रशिक्षण डेटा को अंतर्ग्रहण करके काम करते हैं, सहसंबंधों और पैटर्न के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं तथा भविष्य की दशाओं के बारे में इस पैटर्न का उपयोग करते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियाँ:

निर्विवाद रूप से यह सत्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा मानवीय जीवनशैली तथा कार्यशैली के तरीकों मे व्यापक परिवर्तन आने वाला है, परंतु इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ जा सकता है:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से डीपफेक एवं डीपन्यूड जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी जो अत्यंत भयावह स्थिति को जन्म दे सकती हैं।
- डीपफेक एवं डीपन्यूड के अनुप्रयोगों से व्यक्ति की गरिमा, निजता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का हनन होगा।
- फ्रंटियर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन जेनरेटर AI मॉडल) मांग के आधार पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो जैसे यथार्थवादी एवं विश्वसनीय आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम है। ये कॉपीराइट की समस्या, आतंकवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समस्याएं इत्यादि को बढ़ावा दे सकती हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इस तकनीक के उपयोग से फैक्ट्री, कारखानों एवं बैंकों के हजारों लोगों की नौकरी जा सकती है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2025 तक 50% से अधिक नौकरियों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव दिखना शुरू होगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अतिशय उपयोग से मनुष्य की रचनात्मक शक्ति को समाप्त होने का भी खतरा है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने हुए हथियारों का युद्ध में प्रयोग करने से सम्पूर्ण मानव जाति को संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस तकनीक के प्रयोग से बने शस्त्र सम्पूर्ण मानवता का विनाश करने की क्षमता रखते हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि स्वयं की बुद्धिमत्ता वाला रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगें, तो मानवता के लिये खतरा पैदा हो सकता है। इसका एक बेहतर उदाहरण आप रोबोट फिल्म में देख सकते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में जिस स्तर का विकास होता जा रहा है, उस स्तर पर अपनी तरह की नई चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए वॉइस रिकग्नाइजेशन वाली मशीनों में यूजर की प्राइवेसी सार्वजनिक हो जाने का खतरा बना रहता है।
- भावना या नैतिक मूल्य मशीनों में मौजूद नहीं होता है, इसीलिए वह सही और गलत काम में अंतर नहीं कर पाता है।
- विपरीत परिस्थितियाँ होने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से युक्त मशीनें निर्णय लेने मे सक्षम नहीं होंगी।

Human intelligence vs artificial intelligence

	WEIGHT	SPACE	PROCESSOR SPEED	ENERGY EFFICIENCY
(brain)	3 pounds (1.4kg)	1/6 basketball (80 cubic inches or 1,300 cm³)	Up to 1,000,000 million operations per second	20 watts
(chip)	150 tons	Basketball court (cabinets over 4,350 square feet, or 400 m²)	93,000 trillion operations per second	10 million watts

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियों के निदान हेतु बैलेचले पार्क डिक्लेरेशन:

- विश्व के प्रमुख एआई नेतृत्वकर्ता देशों के मध्य फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न चुनौतियों से निदान हेतु यह पहला वैश्विक समझौता है। इसके साथ ही इस डिक्लेरेशन में देशों के मध्य अधिक मतभेद नहीं हुए जो अपने आप में यह दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन की ही तरह फ्रंटियर एआई की चुनौती एक

वैश्विक समस्या हो सकती है।

- यह घोषणा पत्र मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता तथा क्षमता को स्वीकार करता है, परंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (विशेष रूप से फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की पहचान करके उसे दूर करने का भी प्रयास करता है।
- फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन जनरेटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मांग के अनुसार टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो वीडियो जैसे यथार्थवादी एवं विश्वसनीय आउटपुट को उत्पन्न करने में सक्षम है।
- यह सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न जोखिमों का निदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ-साथ वैश्विक कंपनियों, नागरिक समाज, शिक्षाविद, राजनेता, अभिनेता इत्यादि के सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता को संदर्भित करता है।
- यह घोषणा पत्र एक नियमित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सुरक्षा सम्मेलन के स्थापना की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। यह शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से फ्रंटियर एआई सुरक्षा पर सहयोग हेतु एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
- ध्यातव्य है कि अगले वर्ष इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस द्वारा की जाएगी।

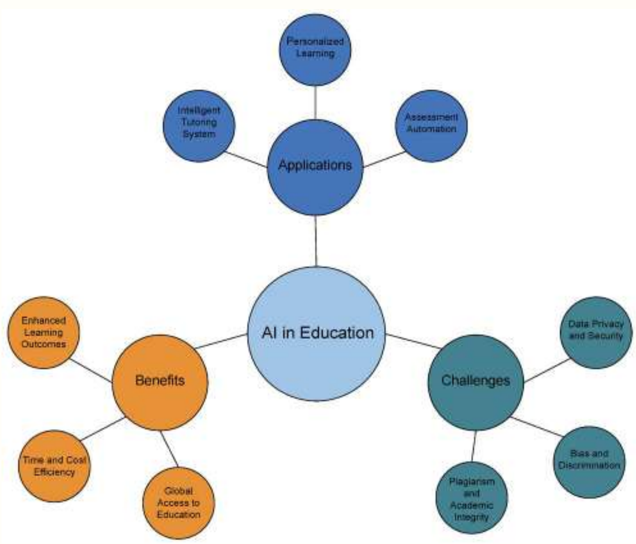

भारत तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, 2023:

भारत की तरफ से केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत के एआई संबंधित विजन को अपने उद्बोधन में सामने रखा जो निम्नवत है:

- भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विनियमन न करने की अपनी नीति से हटकर, जोखिम-आधारित, उपयोगकर्ता- हानि के दृष्टिकोण के आधार पर सक्रिय रूप से नीति निर्माण की तरफ बढ़ रहा है।
- भारत का उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग भारत के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता तथा यूजर के नुकसान का प्रभावी ढंग से समाधान करने एवं जोखिमों को कम करने को महत्त्व देना है।
- भारत ने 'फ्रंटियर एआई दुरुपयोग से वैश्विक सुरक्षा के लिए जोखिम' पर विशेष रूप से फोकस किया है।
- भारत ने 'एआई फॉर गुड' की थीम को अपना उद्देश्य मानकर उत्तरदायी AI उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए 'नैतिक' AI उपकरणों के विस्तार हेतु एक वैश्विक ढाँचे का आह्वान किया।
- भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नियामक निकाय की स्थापना की आवश्यकता को प्रदर्शित किया है।
- भारत ने AI के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नियामक निकाय स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
- भारत जल्द ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक बेहतर नियामकीय फ्रैमवर्क बनाने की दिशा में प्रयास करेगा।

बैलेचले पार्क डिक्लरेशन की संभावित प्रासंगिकता:

- यह शिखर सम्मेलन फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्य चुनौतियों को एक वैश्विक चुनौती के रूप में मानता है।
- बैलेचले पार्क का ऐतिहासिक महत्त्व भी है क्योंकि यह द्वितीय विश्वयुद्ध के कोड-ब्रेकिंग ऑपरेशन का आधार था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता एआई की चुनौतियों को कितनी अधिक गंभीरता से ले रहे हैं?
- यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संप्रभू देशों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों, प्रभावशाली व्यक्तियों इत्यादि को एआई के दुरुपयोग के विरुद्ध एकत्रित होने का आह्वान करता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान देकर ही भविष्य की आवश्यकता एवं उसे प्राप्त करने की विधियों को समझ पायेंगे जिससे हम कालांतर में चुनौतियों को समाप्त कर सकें तभी 'एआई फॉर गुड' के वास्तविक सिद्धांत की तरफ बढ़ना लाभदायक होगा।

निष्कर्ष:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक दोधारी तलवार है। यह जितना ही मानव कल्याण में उपयोगी हो सकती है, उतनी ही मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी। यह निर्णय सभी लोगों को मिलकर करना है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बेहतर ढ़ंग से किया जा सकें। हालांकि इस शिखर सम्मेलन से यह स्पष्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती है जिसका निदान करना आवश्यक है।

भारत में धारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासः चुनौतियां और संभावनाएं

'अतुल्य भारत' ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 'डब्ल्यूटीएम' 2023 में शानदार सफलता के साथ अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की जिससे वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित डब्ल्यूटीएम 2023 ने 'अतुल्य भारत' को बढ़ावा देने पर समर्पित एवं देश के विविध पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया।

सतत पर्यटन क्या है?

सतत पर्यटन से तात्पर्य पर्यटन विकास के अंतर्गत पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं के बीच एक उपयुक्त संतुलन स्थापित करना है जो जैव विविधता के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति पर इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है ताकि यह आय, रोजगार और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे।

सतत पर्यटनः समय की आवश्यकता

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनः** वर्तमान समय में यात्रा के दौरान होने वाला उत्सर्जन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में से एक है। पर्यटन क्षेत्र में ग्रीनहाउस उत्सर्जन में विमानों का योगदान 40% है। विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के अनुसार, पर्यटक परिवहन के तीन मुख्य साधनों 'हवाई, सड़क और रेल' का उपयोग करके यात्रा करते हैं जिसमें हवाई क्षेत्र सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान करता है। कुल मिलाकर CO_2 उत्सर्जन में परिवहन का योगदान 75% है।
- **पानी का अत्यधिक उपयोगः** पर्यटक होटलों, पूलों और स्पा में बड़ी मात्रा में पानी का उपभोग करते हैं जो स्थानीय जल आपूर्ति के लिए हानिकारक होता जा रहा है।
- **जैव विविधता का नुकसानः** पर्यटन से निवास स्थान का विनाश, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान होता है।
- **स्थानीय आबादी का विस्थापनः** पर्यटन स्थानीय आबादी के विस्थापन का कारण बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूमि दुर्लभ है।

भारत में सतत पर्यटन के अवसरः

अपने विविध परिदृश्यों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारत में टिकाऊ पर्यटन के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर हैंः

- **इको-पर्यटनः** संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों तथा पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन पहल का विकास और प्रचार करना।
- **आर्थिक अवसरः** स्थानीय कुटीर उद्योग जैसे- जूट बैग, क्षेत्रीय हस्तशिल्प, वन-आधारित उत्पाद और जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- **सांस्कृतिक अनुभवः** समुदाय-आधारित पर्यटन, स्थानीय कारीगरों का समर्थन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और पारंपरिक शिल्प के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना।
- **ऐतिहासिक संरक्षणः** जिम्मेदार आगंतुक व्यवहार को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए विरासत पर्यटन में स्थायी प्रथाओं को लागू करना।
- **स्वच्छ ऊर्जा पहलः** उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को होटल और परिवहन जैसे पर्यटन बुनियादी ढांचे में एकीकृत करना।
- **अपशिष्ट प्रबंधनः** पर्यटन स्थलों में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना, पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और पर्यटन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।
- **परिवहन स्थिरताः** यात्रा के दौरान कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल जैसे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करना।
- पर्यटन, एडवेंचर, कृषि, शिक्षा और चिकित्सा पर्यटन जैसे कई क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यदि सतत तरीके से किया जाए तो वे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी 8 और एसडीजी 12) तथा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहन के साथ-साथ आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकते हैं।

केस स्टडी

एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे 1953 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। यह असंभव उपलब्धि थी जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद शुरू हुयी पर्यटकों की आवाजाही से एवरेस्ट कूड़े से भर गया जिसे 'दुनिया का सबसे ऊंचा कचरा डंप' कहा जाने लगा। यहां हर साल लगभग 100,000 आगंतुक आते हैं और अनुमानित औसत कचरा प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम निकलता है जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर दबाव डालता है। यह दुनिया भर में हर दिन होने वाली घटनाओं और इसके ग्रह पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की कल्पना करने का एक उदाहरण मात्र है।

सतत पर्यटन की चुनौतियाँः

- **बुनियादी ढांचे के मुद्देः** अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जैसे- अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं और सतत परिवहन विकल्प, सतत पर्यटन प्रथाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं।
- **अत्यधिक भीड़ः** लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर अक्सर भीड़भाड़ होती है जिससे पर्यावरण का क्षरण होता है। इससे अपशिष्ट में वृद्धि होती है और स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
- **जागरूकता की कमीः** स्थायी पर्यटन प्रथाओं के संबंध में अक्सर पर्यटकों और स्थानीय समुदायों दोनों के बीच जागरूकता की कमी होती है जिससे जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **आर्थिक दबावः** अल्पकालिक आर्थिक लाभ को दीर्घकालिक

स्थिरता पर प्राथमिकता मिल सकती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत का शोषण करने वाली प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन कई पर्यटन स्थलों के लिए खतरा पैदा करता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और समग्र जैव विविधता प्रभावित होता है।
- **सांस्कृतिक असंवेदनशीलता:** पर्यटन कभी-कभी स्थानीय संस्कृतियों के विपणन का कारण बन सकता है जिसमें आगंतुक ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो मेजबान समुदाय की परंपराओं और मूल्यों का अनादर करते हैं।
- **नीति और विनियमन:** असंगत या अपर्याप्त नियम और प्रवर्तन तंत्र अक्सर स्थायी पर्यटन प्रथाओं की स्थापना में बाधा डालते हैं।
- **पर्यटन पर निर्भरता:** कुछ क्षेत्र (जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर हैं) पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी निकायों, स्थानीय समुदायों, व्यवसायों और पर्यटकों को शामिल करके एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। प्रभावी नीतियों को लागू करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देकर भारत में सतत पर्यटन की खोज में इन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है।

उल्लेखनीय प्रयास/पहल:

सरकार पर्यटन क्षेत्र की क्षमता को सतत रूप से साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन स्थलों और वन्यजीव-संवेदनशील स्थानों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जाए। इस दिशा में सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं:

- भारतीय पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए अधिक लचीला, समावेशी, कार्बन-तटस्थ और संसाधन-कुशल पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2022 में राष्ट्रीय पर्यटन रणनीति तैयार की गई थी।
- व्यापक रणनीति दस्तावेज ने भारत को सतत और जिम्मेदार पर्यटन के क्षेत्र में एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए सात रणनीतिक स्तंभों की पहचान की जिनमें पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना, जैव विविधता की रक्षा करना, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता को बढ़ावा देना, सतत पर्यटन के प्रमाणीकरण के लिए योजना, आईईसी तथा क्षमता निर्माण और शासन शामिल हैं।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2022 में इकोटूरिज्म के लिए राष्ट्रीय रणनीति भी तैयार की गई थी। इस रणनीति में देश में इकोटूरिज्म विकसित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग सहित 8 मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाने पर जोर दिया गया था।
- उद्योग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य मूल्यांकन और रैंकिंग, इकोटूरिज्म के लिए राज्य रणनीति, आईईसी, क्षमता निर्माण व प्रमाणन, विपणन और संवर्धन, गंतव्य तथा उत्पाद विकास, सार्वजनिक-निजी और सामुदायिक भागीदारी में इन स्तंभों की पहचान की गयी।
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा भारत के पर्यटन को एक वैश्विक अवसर के रूप में मान्यता देता है और देश में पर्यटन क्षेत्र के सतत एवं जिम्मेदार विकास की वकालत करता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं पर पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव को कम करके, सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करके पर्यटन के लिए एक अग्रणी गंतव्य बनाना है। यह नीति वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र के 1 ट्रिलियन डॉलर के योगदान को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करेगी।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2021 में CNA-ST के सहयोग से ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य भारत में 300 मिलियन घरेलू पर्यटकों को यात्रा के दौरान जिम्मेदार व्यवहार और सावधानीपूर्वक संसाधन उपभोग की ओर प्रोत्साहित करना है।
- स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को देश में सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। संशोधित योजना में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाने, स्थानीय समुदायों के लिए स्व-रोजगार सहित नौकरियां पैदा करने, पर्यटन और आतिथ्य में स्थानीय युवाओं के कौशल को बढ़ाने, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- भारत के लिए सतत पर्यटन मानदंड और संकेतक (एसटीसीआई) का लक्ष्य एसटीसीआई प्रमाणन के लिए विभिन्न पर्यटन व्यवसाय उद्यमों, मुख्य रूप से आवास इकाईयों एवं टूर ऑपरेटरों के लिए स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बेंचमार्क करना है।
- भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत विकसित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के आसपास बनाया गया है:
  - हरित पर्यटन
  - डिजिटलीकरण
  - कौशल
  - पर्यटन आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एमएसएमई)
  - गंतव्य प्रबंधन
- **राज्य-स्तरीय प्रयास:** उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न पर्यटन पर निर्भर राज्यों ने समृद्ध जैव विविधता तथा प्राकृतिक संपदा की रक्षा करते हुए सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई हैं।
- सतत पर्यटन आवास संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। पर्यटक खर्च से होने वाले राजस्व को अक्सर संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु स्थानीय समुदायों के लिए प्रकृति संरक्षण या क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में वापस भेज दिया जाता है। इसके अलावा पर्यटन हर साल दुनिया भर में यात्रा करने वाले लाखों लोगों के बीच जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने में एक बेहतर साधन हो सकता है।

वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती और सक्रिय होता एनजीटी

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कई राज्यों को वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने हेतु तत्काल कार्यवाही करने तथा इस सन्दर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा यह निर्देश इन राज्यों में उच्च प्रदूषण स्तर दर्ज होने के बाद दिया गया।

परिचय:

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को अपने राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने के त्वरित उपाय करने और इस संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय इन राज्यों में गिरती वायु गुणवत्ता तथा उस पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान के आधार पर लिया गया है।

वायु प्रदूषण की हालिया चुनौती:

- 20 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में जारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वायु गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार उपरोक्त सात राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र) के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत खराब (Very Poor) से गंभीर (Severe) की श्रेणी में चला गया।
- दिल्ली एनसीआर में यह दैनिक औसत एक्यूआई 400 के लगभग पहुंच गया जो कि विषय की गंभीरता को प्रदर्शित कर रहा है। दिल्ली के 37 स्थानों पर वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब की स्थिति में देखी गई थीं।

वायु प्रदूषण के बारे में:

- पर्यावरण के अजैविक घटक वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसका पर्यावरण तथा जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वायु प्रदूषण कहलाता है।

भारत में वायु प्रदूषण की चिंताजनक वास्तविकता: विस्तार और परिणाम

- वर्तमान में भारत गंभीर वायु प्रदूषण संकट से जूझ रहा है, जैसा कि शिकागो में ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक स्तर पर 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 शहर भारत में स्थित है। यह गंभीर आंकड़ा पूरे देश में एक व्यापक समस्या को रेखांकित करता है।
- सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों सहित वायु प्रदूषण का खतरा अब भारत के तटीय शहरों पर भी मंडरा रहा है जो एक खतरनाक राष्ट्रव्यापी प्रवृत्ति का संकेत देता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मुंबई और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है जहां हाल ही में अत्यधिक असंतोषजनक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तर के कारण वायु गुणवत्ता को "Death by Breath" करार दिया गया था।
- वायु प्रदूषण के कारण भारतीय अपने औसत रूप से जीवन के 5.3 वर्ष खो देते हैं। दिल्ली के निवासी विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हैं जिन्हें औसतन 11.9 वर्षों की जीवन हानि होती है।
- वायु प्रदूषण के कारण भारतीय शहर वासियों के स्वास्थ्य पर दिखने वाले प्रभाव गंभीर रूप से चिंताजनक हैं जो आंखों, नाक और गले में जलन, खांसी, सांस फूलना तथा अस्थमा जैसी बीमारी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसके अलावा, वायु प्रदूषण हृदय संबंधी बीमारियों और इससे जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं की वृद्धि में योगदान देता है। यह देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है।

भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारक:

- **रियल एस्टेट का विस्तार:** भारत में शहरी विकास रणनीतियाँ अक्सर रियल एस्टेट विकास को प्राथमिकता देती हैं जिससे व्यापक निर्माण और बुनियादी ढांचे का विस्तार होता है। नतीजतन, निर्माण गतिविधियों के दौरान निकलने वाली धूल और प्रदूषक हवा की गुणवत्ता को खराब करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **ऑटोमोबाइल सेक्टर में विस्फोटक वृद्धि:** भारत का ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से विकास कर रहा है। 8.1% की पर्याप्त वृद्धि दर के साथ वर्ष 2027 तक इसका बाजार मूल्य लगभग 160 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप सड़कों पर अधिक वाहन दौड़ रहे हैं जो अधिक निजी कार स्वामित्व को प्रोत्साहित करती हैं जिससे यातायात की भीड़ बढ़ जाती है और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।
- **सड़कों की धूल और वाहनों से उत्सर्जन:** सड़क की टूट-फूट से उत्पन्न सड़क की धूल में कई हानिकारक कण होते हैं जो वायु में विस्तारित हो जाते हैं। यह धूल वायु की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन समस्या को और भी बढ़ा देता है जिससे वातावरण में प्रदूषक तत्व फैल जाते हैं। यह स्थिति पीएम पार्टिकल्स की वृद्धि करके वायु प्रदूषण को बढ़ाता है।
- **कंक्रीट बैचिंग और औद्योगिक इकाईयों का प्रभाव:** कंक्रीट बैचिंग, कंक्रीट सामग्री के मिश्रण से जुड़ी एक प्रक्रिया है जो वायु में कणकीय पदार्थ और प्रदूषक मुक्त करती है। इसके अतिरिक्त, शहरों की औद्योगिक इकाईयाँ विभिन्न प्रदूषकों का उत्सर्जन करती हैं जो वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
- **हरित स्थानों की तुलना में ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता:** शहरों के जल निकाय, शहरी वन, सार्वजनिक हरित स्थान और शहरी खेती जैसे प्राकृतिक हरित क्षेत्रों का आकार कम हो गया है। इसके विपरीत ग्रे बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच असंतुलन बढ़ गया है।

उत्तर भारत, विशेषकर एनसीआर में शीतकालीन वायु प्रदूषण:

- **धान की पुआल (पराली) जलाना:** सर्दियों के महीनों के दौरान विशेषकर हरियाणा और पंजाब में धान की पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर के वायु गुणवत्ता की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है। हालांकि यह एक मौसमी समस्या है।

- **निर्माण गतिविधियां:** लगभग हर भारतीय शहर (सर्वाधिक एनसीआर क्षेत्र में लगभग 10%) में व्याप्त निर्माण गतिविधियां, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ प्रभावी निगरानी और नियंत्रण उपायों की कमी है तथा इस सम्बन्ध में कोई मानकीकृत प्रक्रिया नहीं है।
- **त्रुटिपूर्ण शहरी विकास विकल्प:** बिगड़ती वायु गुणवत्ता को संबोधित करने के लिए शहरी नियोजन, परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वर्तमान निम्नस्तरीय शहरी विकास से शहर के निवासियों की भागीदारी सीमित हो गई है और शहरीकरण प्रक्रिया के बीच उनकी भूमिका निष्क्रिय हो गई है।

भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने की रणनीतियाँ: अभी तक किए गए प्रयास

वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981:

इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य थे –

- प्रदूषण में कमी, रोकथाम और नियंत्रण।
- वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना।
- वायु प्रदूषण से बचाव एवं रोकथाम के लिए बोर्ड की स्थापना करना।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम:

भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) के रूप में जाना जाने वाला परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) निम्न उद्येश्यों हेतु चलाया जाता है:

- परिवेशी वायु गुणवत्ता की स्थिति और रुझान निर्धारित करने के लिए।
- NAAQS के अनुपालन के निर्धारण हेतु।
- गैर-प्राप्ति शहरों की पहचान करने के लिए।
- वातावरण में स्वच्छता की प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने के लिए।
- निवारक और सुधारात्मक उपाय करने के लिए।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS):

- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को वर्ष 1982 में अधिसूचित किया गया था जो 1994 में स्वास्थ्य मानदंडों और भूमि उपयोगों के आधार पर विधिवत संशोधित किया गया।
- NAAQS को 12 प्रदूषकों के लिए नवंबर 2009 में संशोधित और संशोधित किया गया है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), पार्टिकुलेट मैटर 10 (PM10), पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (PM 2.5), ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), आर्सेनिक, निकल , बेंजीन तथा अमोनिया बेंजोपाइरीन शामिल हैं।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक:

- देश के बड़े शहरों के प्रदूषण के रियल टाइम मापन के उद्देश्य से इसे 2015 में लांच किया गया था।
- यह आठ प्रदूषणकारी तत्वों पीएम10, पीएम 2.5, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा लेड के आधार पर वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियों में बांटा गया है:
  - अच्छी (0 से 50)
  - संतोषजनक (51-100)
  - सामान्य प्रदूषित (101-200)
  - खराब (201-300)
  - बहुत खराब (301-400)
  - गंभीर (401-500)

आगे की राह:

- **शहरी नियोजन रणनीतियों को नया रूप देना:** सार्वजनिक परिवहन में सुधार, सुरक्षित पैदल यात्री पथ और समर्पित साइकिल लेन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी विकास में एक बुनियादी बदलाव जरूरी है। साइकिल अधिकारियों की नियुक्ति और निर्माण गतिविधियों के लिए मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन इस दिशा में आवश्यक प्रयास हो सकते हैं।
- **सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को बढ़ाना:** इस समय लगभग 10 लाख इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने सहित मजबूत सार्वजनिक परिवहन में निवेश तथा शहरी गतिशीलता मांगों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है, साथ ही जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसी पहल को दोहराया जाना चाहिए जिससे सार्वजनिक परिवहन सुलभ और किफायती हो।
- **निजी वाहनों पर सख्त नियंत्रण करना:** शहर प्रशासन को निजी वाहनों की आवाजाही पर निर्णायक नियम लागू करने चाहिए। पीक आवर्स के दौरान भीड़ कर जैसे उपायों को लागू करने और सम-विषम नंबर प्लेट प्रणाली को अपनाने से प्रदूषण पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। 'नो कार डेज' जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करके भी इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** वायु गुणवत्ता स्तर के आधार पर दिल्ली की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को अन्य शहरों में लागू किया जाना चाहिए। वास्तविक समय में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और शहरी स्थानों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

नागरिकों के लिए इस धारणा को स्वीकार करना अनिवार्य है कि वायु प्रदूषण जैसे कारकों के कारण उनका जीवनकाल कम हो सकता है तथा प्रत्येक नागरिक जीवन की बेहतर गुणवत्ता और प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा का हकदार है। सरकार को शहरी भारतीयों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने, उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का यह निर्णय एक सकारात्मक संदेश दे रहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा मामले स्वत: संज्ञान लेना यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण वायु प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से ले रहा है। कालांतर में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की भूमिका महत्त्वपूर्ण होने वाली है।

1 डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 को मंजूरी दिया है। बदलते मीडिया परिदृश्य में अधिक-से-अधिक दर्शकों तक पहुँच स्थापित करने हेतु नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये इस विधेयक को मंजूरी मिली है।

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के बारे में:

- सीबीसी की डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित करने के साथ प्रतिस्पर्धी भावना जैसी विशेषता भी प्रदान करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित की गई दरें तीन वर्ष तक वैध रहेंगी जो सभी पात्र एजेंसियों पर लागू होंगी।
- यह नीति सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों व संगठनों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी।
- सीबीसी डिजिटल ऑडियो प्लेटफार्म के पैनल के माध्यम से पॉडकास्ट और डिजिटल ऑडियो प्लेटफार्म पर श्रोताओं की बढ़ती संख्या का लाभ उठाने में भी सक्षम होगा।
- इंटरनेट वेबसाइटों को सूचीबद्ध करने की अपनी प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के अलावा, सीबीसी अब पहली बार अपने सार्वजनिक सेवा अभियान संदेशों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी प्रसारित करने में सक्षम होगा।
- यह नीति सीबीसी को विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार भी देती है।
- यह नीति डिजिटल परिदृश्य की गतिशील प्रकृति को भी पहचानती है और सीबीसी को विधिवत गठित समिति की मंजूरी के साथ डिजिटल स्पेस में अभिनव संचार प्लेटफार्मों पर शामिल होने का अधिकार देती है।

इस नीति का महत्त्व:

- यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य तथा मीडिया उपयोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसारण एवं जागरूकता उत्पन्न करने के सीबीसी के मिशन में एक महत्त्वपूर्ण अभियान को प्रदर्शित करती है।
- यह नीति डिजिटल दुनिया में विशाल ग्राहक (Subscriber) आधार, डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ लक्षित नागरिक केंद्रित संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी जिसके परिणामस्वरूप जन उन्मुख अभियानों का संचालन लागत दक्षता के साथ किया जा सकेगा।
- हाल के वर्षों में दर्शकों द्वारा किये जाने वाले मीडिया उपयोग को देखते हुए यह डिजिटल क्षेत्र की ओर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।
- भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण देश में उन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो अब इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों से जुड़े हुए हैं।
- ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार, मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक नागरिकों के पास है, जबकि मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक हो गयी है।

आगे की राह:

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है जो भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने व जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। सीबीसी बदलते मीडिया परिदृश्य को अपनाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते मीडिया प्रयोग को ध्यान में रखते हुए जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

2 निजी क्षेत्र में आरक्षण का औचित्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की गारंटी दी गई थी। न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 असंवैधानिक और संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कानून 'प्रभावी होने की तारीख से ही अप्रभावी' हो गया है।

हरियाणा निजी क्षेत्र कोटा कानून के बारे में:

- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 राज्य सरकार द्वारा मार्च 2021 में अधिनियमित किया गया।
- इस कानून में 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 10 वर्षों तक 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम में कंपनियों, समाजों, ट्रस्ट, साझेदारी फर्मों और बड़े व्यक्तिगत नियोक्ताओं सहित विभिन्न संस्थाओं को शामिल किया गया है।
- इसमें 10 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को शामिल किया गया, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार को छूट दिया गया है।
- इसमें नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत करने और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- हरियाणा राज्य का निवासी अर्थात स्थानीय उम्मीदवार एक निर्दिष्ट

ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करके आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

- इस कानून का उद्देश्य स्थानीय युवाओं, विशेष रूप से अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

हरियाणा निजी क्षेत्र कोटा कानून से सम्बंधित मुद्दे:

- हरियाणा सरकार ने कानून बनाकर निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन या संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है।
- निजी क्षेत्र की नौकरियाँ पूरी तरह से कौशल और अनुभव पर आधारित होती है तथा कर्मचारियों को भारत के किसी भी हिस्से में काम करने का मौलिक अधिकार है।
- नियोक्ताओं को स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए मजबूर करने के लिए सरकार का निर्णय संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन है क्योंकि इसने सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य करके केवल एक वर्ग को लाभ पहुंचाया है।

सरकार की प्रतिक्रिया:

- हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि उसके पास संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत इस तरह के आरक्षण देने की शक्ति है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने से नहीं रोकता है जिसका राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो।
- हरियाणा सरकार ने कहा कि राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका के अधिकार तथा उनके स्वास्थ्य, रहने की स्थिति और रोजगार के अधिकार की रक्षा के लिए कानून आवश्यक है।

आगे की राह:

यह आरक्षण अनुच्छेद 19(1)(जी) में वर्णित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन था क्योंकि इसने योग्य नियोक्ताओं पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए अनुचित प्रतिबंध लगा दिया था। इससे सभी राज्यों में अपने नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक अधिनियम बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा जिससे ऐसी बाधाएं पैदा हो सकती हैं जो भारत की भावना के खिलाफ हो।

3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। ओडिशा, बिहार तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पिछले कुछ वर्षों से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं।

विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में:

- विशेष राज्य का दर्जा भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि होती है।
- संविधान एससीएस के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, बल्कि यह वर्गीकरण 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। इसके तहत जम्मू-कश्मीर, असम और नागालैंड को पहली बार 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।
- असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित ग्यारह राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा विशेष स्थिति (संवैधानिक स्थिति) से अलग है जो उन्नत विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है।

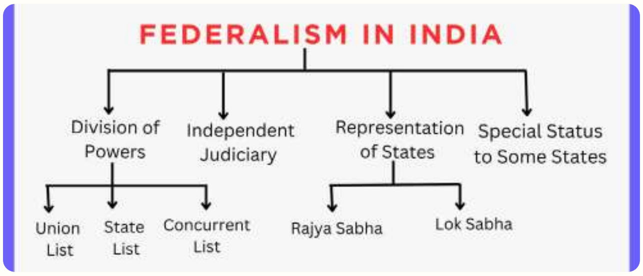

गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति:

- वह राज्य जहां संसाधनों की कमी होना।
- प्रति व्यक्ति कम आय होना।
- राज्य का वित्त व्यवहार्य न होना।
- आर्थिक और संरचनात्मक रूप से अविकसित होना।
- एक बड़ी जनजाति का होना।
- रणनीतिक व सीमावर्ती रूप से स्थित होना।
- विरल आबादी वाला क्षेत्र होना।

विशेष राज्य का दर्जा मिलने से लाभ:

- केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को भुगतान करता है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह 60% या 75% है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।
- इसके तहत प्राप्त वित्त यदि एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया जाता है, तो पैसा लैप्स नहीं होता, बल्कि अगले वित्त वर्ष में हस्तांतरित हो जाता है।
- इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क सहित आयकर व कॉर्पोरेट कर में महत्त्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है।

विशेष श्रेणी का दर्जा संबंधी चिंताएं:

- इससे केंद्रीय वित्त पर बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है।
- किसी भी नए राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने से मौजूदा राज्यों में इसकी मांग बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार राज्यों से मांगें होना।

आगे की राह:

पूर्वोत्तर क्षेत्र और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा 14वें वित्त आयोग द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय इसने केंद्र को कर प्राप्तियों में राज्य की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की सलाह दी जो 2015 से लागू है। सभी राज्यों एवं केंद्र सरकार को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए ताकि बिना भेदभाव को बढ़ाये विकास कार्य को गति प्रदान किया जा सके।

4 व्यभिचार को पुनः अपराध घोषित करने पर विचार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मामलों की संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 को बदलने के लिए प्रस्तावित कानून 'भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023' में व्यभिचार को एक अपराध के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। व्यभिचार से तात्पर्य एक विवाहित व्यक्ति और उस व्यक्ति के वर्तमान जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बीच स्वैच्छिक यौन संबंध से होता है।

समिति द्वारा सुझाए गये महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- समिति ने कहा कि व्यभिचार को एक अपराध के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए, लेकिन इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए अर्थात पुरुषों और महिलाओं दोनों को इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए।
- पूर्व में यह धारा केवल विवाहित पुरुष को दंडित करती थी और विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति बना देती थी। समिति का मानना है कि भारतीय समाज में विवाह संस्था को पवित्र माना जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को भेदभाव के आधार पर रद्द कर दिया गया था और इसे जेंडर न्यूट्रल बनाने से इस कमी को दूर किया जा सकेगा।

व्यभिचार पर वर्तमान कानूनी स्थिति:

- वर्ष 2018 तक आईपीसी में धारा 497 शामिल थी जो व्यभिचार को एक अपराध के रूप में परिभाषित करती थी जिसमें पांच साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते थे। हालाँकि धारा 497 के तहत केवल पुरुषों को ही सजा दी जा सकती थी, महिलाओं को नहीं।
- **धारा 497:** यदि कोई पुरूष एक ऐसी महिला के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है, उस पुरुष की सहमति या मिलीभगत के बिना, ऐसा शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा और ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी।
- जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (27 सितंबर, 2018) मामले में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 को उन आधारों पर रद्द कर दिया जिनमें भेदभाव शामिल था।

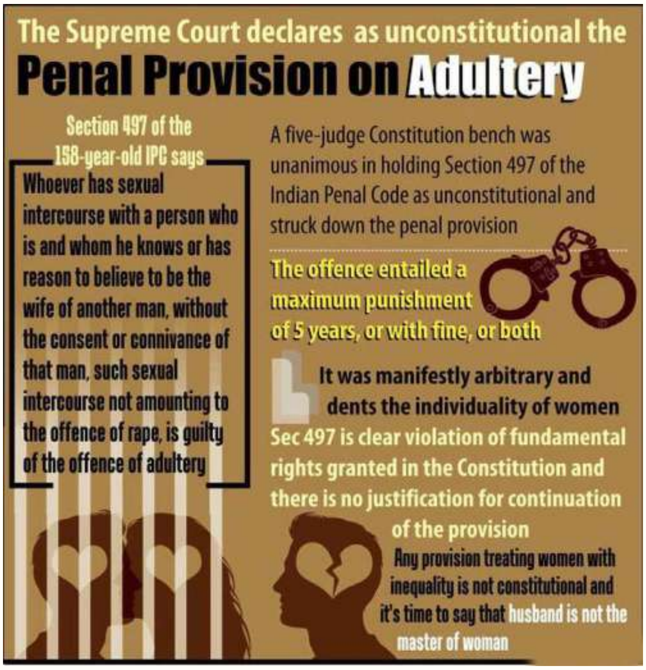

कोर्ट द्वारा इस प्रावधान को रद्द करने का कारण:

- धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 (जो क्रमशः समानता, गैर-भेदभाव और जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं) का उल्लंघन था।
- अदालत ने महिलाओं की स्वायत्तता को मानवीय गरिमा के एक पहलू के रूप में रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा कि पति न तो अपनी पत्नी का मालिक है, न ही उस पर उसकी कानूनी संप्रभुता है और किसी महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करने वाली कोई भी प्रणाली संविधान के उल्लंघन का परिचायक होती है।

आगे की राह:

धारा 497 जैसे प्रावधानों को संसद द्वारा अपनी विधायी जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में बहस और चर्चा के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए था। हालाँकि, जरूरत इस बात की है कि जीवन के अधिकार और विवाह की पवित्रता के बीच संतुलन बनाकर व्यभिचार को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए जिससे बिना भेदभाव के समानतापूर्ण समाज की स्थापना हो सके।

5 गोद लेने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर याचिका की सुनवाई में, भारत में गोद लेने की

प्रक्रिया में तेजी लाने और सरल बनाने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नये निर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

- जिन बच्चों के माता-पिता एक वर्ष से अधिक समय से उनसे मिलने नहीं आए हैं, उन बच्चों की पहचान होनी चाहिए।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी संस्थानों में बच्चों की पहचान के लिए द्विमासिक अभियान शुरू करना होगा।
- जिले के सभी अनाथ बच्चों का CARINGS पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा।
- न्यायालय ने 'अयोग्य अभिभावक' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो 'माता-पिता बनने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं।'

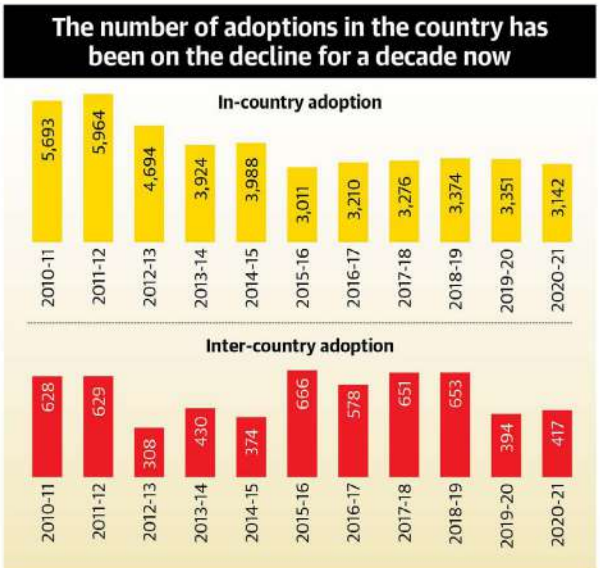

वर्तमान गोद लेने के प्रावधान और आँकड़े:

- सीएआरए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4,000 बच्चों को गोद लिया जाता है, जबकि ऐसा अनुमान है कि 2021 तक लगभग 3 करोड़ से अधिक अनाथ बच्चे गोद लेने के लिए उपलब्ध थे।
- गोद लेने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध बच्चों की संख्या और संभावित दत्तक माता-पिता (पीएपी) की संख्या के बीच बहुत बड़ी असमानता है। जैसा कि सीएआरए के ऑनलाइन पोर्टल, CARINGS द्वारा दर्शाया गया है।
- अक्टूबर 2023 तक, सीएआरए के राज्य-वार विश्लेषण से पता चला कि 2,146 बच्चे गोद लेने के लिए उपलब्ध थे, जबकि देश में गोद लेने के लिए 30,669 भावी दत्तक माता-पिता पंजीकृत थे।
- भारत के 760 जिलों में से केवल 390 में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां हैं जो गोद लेने में संभावित भौगोलिक बाधा का संकेत देता है।

भारत में बच्चा गोद लेने की चुनौतियाँ:

- विधायिका के मोर्चे पर भी एक विसंगति है क्योंकि गोद लेना हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है जिसमें कानून तथा न्याय मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे बाद में 2021 में संशोधित किया गया था) के पहलुओं का क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निपटाया जाता है।
- जागरूकता की कमी, जनता के बीच सीमित गोद लेने की साक्षरता और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं से जुड़े मिथक भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

आगे की राह:

जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा सुरक्षा उपायों को ध्यान रखते हुए प्रक्रिया को तेज करने के लिए रिकॉर्ड को डिजिटल एवं अदालती प्रक्रियाओं को बच्चों को गोद लेने के अनुकूल बनाने से इसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। राज्य/जिला स्तरीय औपचारिक नेटवर्क बनाने तथा अधिक विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां की स्थापना से गोद लेने की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सकता है।

6 रैट-होल खनन (Rat Hole Mining)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रैट-होल खनन तकनीक (जिसे 2014 में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था) का उपयोग उत्तराखंड में सिल्क्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए किया गया था।

रैट-होल खनन के बारे में:

- रैट-होल खनन संकीर्ण और क्षैतिज मार्गों के माध्यम से कोयला भंडार खोजने की एक पुरानी विधि है। इसका तात्पर्य जमीन में खोदे गए संकीर्ण गड्ढों से है जो आम तौर पर इतने बड़े होते हैं कि एक व्यक्ति उसमें उतर सके और कोयला निकाल सके। यह नाम संकीर्ण छिद्रों में बिल खोदने वाले चूहों से मिलता जुलता होने के कारण पड़ा।

प्रकार:

साइड-कटिंग प्रक्रिया:

- साइड-कटिंग प्रक्रिया में पहाड़ी ढलानों पर संकीर्ण सुरंगें खोदी जाती हैं और श्रमिक कोयले की परत मिलने तक अंदर जाते हैं।

बॉक्स-कटिंग:

- बॉक्स-कटिंग में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 10 से 100 वर्गमीटर तक होता है जिसके माध्यम से 100 से 400 फीट गहरा एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है।
- एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद, चूहे के बिल के आकार की सुरंगें क्षैतिज रूप से खोदी जाती हैं जिसके माध्यम से श्रमिक कोयला निकाल सकते हैं।

चिंताएं:

- रैट होल खनन से महत्त्वपूर्ण सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे पैदा होते

हैं। खदानें आम तौर पर अनियमित होती हैं जिनमें उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहायता या श्रमिकों के लिए सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त खनन प्रक्रिया से भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण हो सकता है।

- खनन की इस पद्धति को इसकी खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों एवं पर्यावरणीय क्षति के कारण होने वाली कई दुर्घटनाओं में गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा है। अधिकारियों द्वारा ऐसी प्रथाओं को विनियमित या प्रतिबंधित करने के प्रयासों के बावजूद, वे अक्सर आर्थिक कारकों और स्थानीय आबादी के लिए व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका की अनुपस्थिति के कारण बनी रहती हैं।

रैट-होल खनन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2014 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जो वर्ष 2015 तक बरकरार रहा। यह आदेश मेघालय के संबंध में था जहां कोयला खनन के लिए एक प्रचलित प्रक्रिया बनी हुई थी।
- पूर्वोत्तर राज्य में कई दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रैट-होल खनिकों की मौतें हुई हैं।
- हालाँकि खनन राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। मणिपुर सरकार ने एनजीटी के प्रतिबंध को यह तर्क देते हुए चुनौती दी है कि इस क्षेत्र के लिए खनन का कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं है।
- 2022 में मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक पैनल ने पाया कि मेघालय में रैट-होल खनन बेरोकटोक जारी है।

आगे की राह:

रैट होल खनन का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब खनन के लिए अन्य विधि बहुत व्यवहार्य न हो। समय की मांग है कि नीति निर्माता पर्यावरण और राज्यों की आर्थिक जरूरत के बीच संतुलन बनाने का कार्य करें क्योंकि बिना पर्यावरण सुरक्षा किये मानव सभ्यता का अस्तित्व संभव नहीं है।

7 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा की जयंती पर कमजोर आदिवासी समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू किया।

इस योजना के बारे में:

- इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को कई सुविधाएं प्रदान करना है। इनमें आवास, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर शामिल हैं।
- आयुष मंत्रालय के मौजूदा मानदंडों के अनुसार, आयुष कल्याण केंद्र स्थापित किया जायेगा ताकि मोबाइल चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से आयुष सुविधाओं को पीवीटीजी बस्तियों तक बढ़ाया जा सके।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उचित कौशल हेतु पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों तथा छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।
- इस योजना के तहत 2.39 लाख रुपये प्रति घर की लागत से लगभग 4.9 लाख पक्के मकान, 2.75 करोड़ रुपये प्रति यूनिट पर 500 छात्रावास, 2,500 आंगनवाड़ी केंद्र, 3,000 गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना और 8,000 किमी सड़क कनेक्टिविटी आदि उपलब्ध कराया जायेगा।
- इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये है, जबकि राज्य सरकार का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये होगा। इस योजना को अगले तीन वर्षों में बेहतर कार्यान्वयन के लिए कुल नौ मंत्रालय शामिल होंगे।

पीवीजीटी के बारे में:

- 18 राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों के 75 आदिवासी समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा में पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी 8.66 लाख है जिसके बाद मध्य प्रदेश में 6.09 लाख और आंध्र प्रदेश (जिसमें तब तेलंगाना भी शामिल था) में 5.39 लाख है। उल्लेखनीय है कि कुल पीवीटीजी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है।

आगे की राह:

पीवीटीजी के कल्याण हेतु काम करते समय जनजातीय पंचशील के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें अपनी गति से मुख्यधारा में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक सक्षम वातावरण बनाया जाना जरूरी है जिससे ये समुदाय अपने जीवन और आजीविका के विकल्प चुनने तथा विकास के पथ पर बढ़ने के लिए सशक्त हो सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

1 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस संपन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लिया। इस बैठक के दौरान उन्होंने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग की भावना पर भारत की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

इस बैठक से सम्बंधित प्रमुख बिंदु:

- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धताः** अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) 1982 का संदर्भ देते हुए, अंतर्राष्ट्रीय जल में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट तथा निर्बाध वैध वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावाः** हितधारकों के सहयोग और सहमति को प्रतिबिंबित करने वाली परामर्शात्मक तथा विकासोन्मुख क्षेत्रीय सुरक्षा पहल की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए एडीएमएम-प्लस के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **आतंकवाद संबंधी चिंताएँः** आतंकवाद के खतरे को पहचानते हुए भारत ने आतंकवाद पर विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की सह-अध्यक्षता करने का प्रस्ताव रखा। 2021-2024 के वर्तमान चक्र में भारत, इंडोनेशिया के साथ एचएडीआर पर ईडब्ल्यूजी की सह-अध्यक्षता कर रहा है।
- **संवाद और कूटनीतिः** स्थायी शांति और वैश्विक स्थिरता के लिए संवाद व कूटनीति के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। विश्व व्यवस्था में चल रहे गतिरोध और युद्ध को यह कहते हुए समाप्त करने की बात कही गयी कि यह समय युद्ध का नहीं है।

एडीएमएम प्लस क्या है?

- यह क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संघ) तथा उसके आठ संवाद भागीदारों के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि किसी भी मुद्दे का हल सभी के हितों को ध्यान रखकर निकाला जा सके।

एडीएमएम प्लस के उद्देश्यः

- निरंतर संवाद और सहयोग के माध्यम से रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए रक्षा व सुरक्षा में सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ाना।

आगे की राहः

भारत के रक्षा मंत्री ने आसियान की महत्ता की पुष्टि की और क्षेत्रीय संवाद तथा सर्वसम्मति को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। एडीएमएम-प्लस की यह बैठक भारत की प्रतिबद्धताओं एवं बहुपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन में सहयोग, शांति व सुरक्षा के प्रति भारत के समर्पण को दर्शाती है।

2 दक्षिण पूर्व एशिया में एक नये त्रिपक्षीय समीकरण की संभावना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फिलीपींस ने स्थिरता और भूराजनीतिक चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी नेतृत्व वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से हटने का निर्णय लिया है। फिलीपींस ने समान विचारधारा वाले देशों जैसे जापान तथा भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। इस साझेदारी को दक्षिण पूर्व एशिया में एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी माना जा रहा है।

फिलीपींस और चीन के बीच उत्पन्न हुए मुद्दे क्या हैं?

- दक्षिण चीन सागर को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। क्षेत्रीय दावों और फिलीपींस जलक्षेत्र में चीनी जहाजों की मौजूदगी सहित चीन की व्यापक समुद्री गतिविधियों से तनाव बढ़ गया है। फिलीपींस ने अपने संप्रभु अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंता जताई है और साथ ही समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का पालन करने का आह्वान किया है। चीन के खिलाफ 2016 में आये ट्रिब्यूनल के फैसले का फिलीपींस ने स्वागत किया था।

दक्षिण पूर्व एशिया में जापान और भारत की भागीदारीः

स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत (FOIP):

- इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकना है। जापान की एफओआईपी अवधारणा भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) अवधारणा का पूरक माना जाता है।

बुनियादी ढांचे का विकासः

- जापान, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साझेदारी जैसी पहल

के माध्यम से बंदरगाहों, सड़कों और ऊर्जा सुविधाओं के निर्माण सहित दक्षिण पूर्व एशिया में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में शामिल रहा है।

- भारत ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी रुचि व्यक्त की है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाले त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने में भारत सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

सुरक्षा सहयोग:

- जापान और भारत समुद्री सुरक्षा तथा आतंकवाद-निरोध सहित अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सुरक्षा वार्ता और संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहे हैं।

क्षेत्रीय मंच:

- दोनों देश क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) तथा आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) जैसे क्षेत्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

भारत-फिलीपींस संबंध:

- भारत और फिलीपींस हिंद-प्रशांत को एक स्वतंत्र, खुले व स्थिर क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाते रहे हैं।
- वर्ष 1947 में भारत और 1946 में स्वतंत्र हुए फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को स्थापित हुए।
- वर्ष 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरूआत ने भारत-फिलीपींस संबंधों के विविधीकरण को चिह्नित किया जिसमें राजनीतिक-सुरक्षा सहयोग, व्यापार और उद्योग शामिल हैं।
- 2022 तक भारत, फिलीपींस के लिए पंद्रहवें सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है जिसका व्यापार लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
- भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। इस सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर ब्रह्मोस मिसाइल समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है।

आगे की राह:

विकास और सुरक्षा सहयोग के लिए फिलीपींस का जापान तथा भारत की ओर उन्मुख होता रुख चीन के प्रभाव के बारे में चिंताओं के बीच एक रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है। जापान और भारत के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदारी आर्थिक विकास को भी बहुआयामी सहयोग उपलब्ध कराती है। उल्लेखनीय है कि जापान और भारत इंडो-पैसिफिक के उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में दो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3 भारत और एपेक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) नेताओं की बैठक 11 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुई। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय 'सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना' है।

इस शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

- शिखर सम्मेलन गोल्डन गेट घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।
- एपेक के सदस्य देशों के बीच एक नए जलवायु समझौते पर सहमति बनी है जो दुबई में प्रस्तावित है।
- इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना और कोयला, तेल व गैस के प्रतिस्थापन में तेजी लाना है।
- एपेक देशों ने मुक्त, निष्पक्ष और खुला व्यापार, निवेश तथा क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।

भारत एपेक का सदस्य क्यों नहीं है?

- जिस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण (1991) हुआ था, उसी वर्ष भारत ने APEC में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। इस समूह के अधिकांश सदस्य भारत को इसमें शामिल करने के पक्ष में थे लेकिन कुछ ने इसका विरोध किया था क्योंकि उन देशों का मानना था कि भारत की संरक्षणवादी प्रवृत्ति स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियों का विरोध करती है। उसके बाद भी भारत ने कई बार प्रयास किया परन्तु अभी भी सफलता नहीं मिली है।

एपेक सदस्यता से भारत को होने वाले लाभ:

- घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना।
- व्यापार और निवेश प्रवाह सुविधाजनक होना जिससे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की बाजार पहुंच आसान होना।
- व्यापार प्रक्रियाओं और विनियमों को सरल व सुसंगत बनाकर एपेक के साथ जुड़ने से भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बढ़ना जिससे 'मेक इन इंडिया' जैसी घरेलू पहल को समर्थन मिल सकता है।
- यह सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर सकता है।

आगे की राह:

भारत की स्थिति प्रशांत तटरेखा से दूर होना, APEC में इसकी सदस्यता के पक्ष को कमजोर किया है, लेकिन इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारत को अधिक केंद्रीय स्थान देना है, क्योंकि अमेरिका चीन के आर्थिक प्रभाव के लिए विकल्प और प्रतिकार बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

4 भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) मजबूत करने पर सहमति बनी। पहली वार्ता 20-21 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के बीच हुई थी।

इस वार्ता के मुख्य बिंदु:

- दोनों देशों के मंत्रियों ने संबंधों की सकारात्मक गति का स्वागत किया और निरंतरता तथा व्यापकता के लिए इसके लाभों पर जोर दिया। मार्च 2023 में पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से कूटनीति, रक्षा और विकास गतिविधियों में निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धताओं के साथ उल्लेखनीय प्रगति को स्वीकार किया गया।
- भारत की जी-20 अध्यक्षता के लिए ऑस्ट्रेलिया के मजबूत समर्थन की सराहना की गई और दोनों पक्षों ने वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत द्वारा आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया जो विकासशील दुनिया में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए साझा समर्पण को दर्शाता है।
- दोनों देशों के मंत्रियों ने यूक्रेन में युद्ध के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक, न्यायसंगत व टिकाऊ शांति की आवश्यकता पर बल दिया।
- दोनों देशों के मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, नेविगेशन की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण विवाद समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया।
- क्वाड साझेदारी को क्षेत्रीय और वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में प्रयोग करने पर सहमति बनी। मई 2023 में हिरोशिमा में नेताओं के शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति को 2024 में भारत में आयोजित होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की सफलता पर जोर दिया गया।
- इस वार्ता में ऑस्ट्रेलिया-भारत समुद्री संवाद तथा फ्रांस और इंडोनेशिया के साथ त्रिपक्षीय समूहों के लिए प्रतिबद्धताओं के साथ समुद्री क्षेत्र जागरूकता के महत्त्व पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने हेतु समुद्री डोमेन जागरूकता पहल के लिए इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप पर प्रकाश डाला गया।
- दोनों देशों के मंत्रियों ने संयुक्त अभ्यास, 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद और रक्षा नीति वार्ता पर प्रकाश डालते हुए रक्षा संबंधों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचाना।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) सहित आर्थिक जुड़ाव में प्रगति पर प्रकाश डाला गया। योग्यता आधारित पारस्परिक मान्यता के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

आगे की राह:

भारत विश्व के कुछ ही देशों के साथ यह वार्ता करता है जिसमें अमेरिका, जापान और रूस शामिल हैं। स्वतंत्र, खुले और नियमबद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच यह साझेदारी महत्त्वपूर्ण है। अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही विश्व व्यवस्था में भारत एक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है जोकि भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं, वरन समस्त विश्व के लिए लाभकारी होगा।

5 भारत जाने वाले जहाज का लाल सागर में अपहरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भारत जाने वाले मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को इजरायली जहाज समझकर अपहरण कर लिया। हालाँकि इजरायली सरकार ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि जहाज का स्वामित्व एक ब्रिटिश कंपनी के पास है और इसे एक जापानी फर्म द्वारा संचालित किया जाता है।

समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून:

- 1982 का समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री डकैती के दमन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 100 से 107 और 110 में।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने समुद्री डकैती से निपटने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को अपनाया है जिनमें समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन के लिए कन्वेंशन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (एसओएलए) और अंतर्राष्ट्रीय जहाज तथा बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड (आईएसपीएस कोड) शामिल हैं।

भारत में पायरेसी कानून:

- भारत सरकार ने समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम बनाया है जो समुद्री डकैती से निपटने के लिए एक प्रभावी कानूनी रुपरेखा प्रदान करता है और भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्रों में पाइरेसी रोकने की जिम्मेदारी देता है।
- अधिनियम में समुद्री डकैती की रोकथाम से संबंधित अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है। यह भारत के

विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील और उससे आगे भी लागू होता है। यह अधिनियम समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप है।

हूती विद्रोहियों के बारे में:

- हूती, एक ईरान समर्थित समूह है जो उत्तरी यमन और राजधानी सना के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। इसने हाल के वर्षों में इजराइल पर हमले करने और लाल सागर में इजरायली जहाजों को जब्त करने की धमकी दिया है।

लाल सागर के बारे में:

- लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। समुद्र से इसका संबंध दक्षिण में बाब अल मांडेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से है। इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी स्थित है।

आगे की राह:

जहाज की जब्ती या समुद्री डकैती एक वैश्विक मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सभी देशों एवं संस्थाओं को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि खुली एवं स्वतंत्र परिचालन व्यवस्था सुचारू से बिना किसी व्यवधान के चलती रहे।

6 वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक

चर्चा में क्यों?

पिछले एक दशक में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 83वें से फिसलकर 103वें स्थान पर आ गया है। वर्तमान रैंकिंग में भारत को अल्जीरिया (102) और ग्वाटेमाला (104) के बीच रखा गया है। इन तीनों देशों को निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु:

- भारत की वर्तमान रैंक जीटीसीआई में मूल्यांकन किए गए देशों के औसत स्कोर से नीचे है।
- भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले उल्लेखनीय देशों में रवांडा, पैराग्वे, ट्यूनीशिया, नामीबिया, बोलीविया, घाना, अल साल्वाडोर, गाम्बिया, केन्या और मोरक्को शामिल हैं।
- प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल इनसीड द्वारा तैयार जीटीसीआई यह आंकलन करता है कि देश और शहर प्रतिभा को कैसे आकर्षित करते हैं, विकसित करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं।
- सूचकांक दो उप-सूचकांकों का उपयोग करता है: इनपुट और आउटपुट। इनपुट विनियामक और व्यावसायिक वातावरण के साथ-साथ प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा उसे बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों को मापता है, जबकि आउटपुट पक्ष प्रतिभा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है।
- सूचकांक निर्णय निर्माताओं के लिए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता को समझने और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने हेतु एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है।

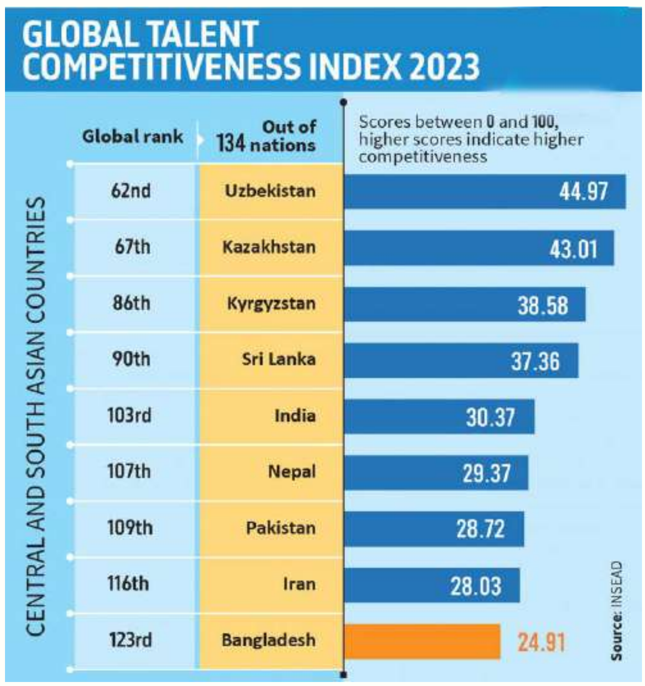

ब्रिक्स समूह का प्रदर्शन:

- ब्रिक्स समूह के भीतर भारत की रैंक सबसे निचले स्थान पर रही है, जबकि चीन 40वें स्थान पर अग्रणी है। इसके बाद रूस (52), दक्षिण अफ्रीका (68) और ब्राजील (69) का स्थान रहा है।
- इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारत अपने ब्रिक्स समकक्षों की

तुलना में प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता में अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत के आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए इन चुनौतियों का विश्लेषण तथा समाधान करना महत्त्वपूर्ण है।

भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारण:

- रिपोर्ट में जीटीसीआई में भारत की गिरावट का कारण व्यापारिक धारणा में गिरावट को बताया गया है जिससे प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- नकारात्मक प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना एवं इन चुनौतियों के मूल कारणों को समझना आवश्यक है।

अन्य उभरते देशों का प्रदर्शन:

- रिपोर्ट में अन्य उभरते देशों में सुधार को स्वीकार किया गया है जिसमें चीन, इंडोनेशिया और मैक्सिको का विशेष उल्लेख शामिल है।
- इन देशों की सफलता की कहानियों का विश्लेषण प्रभावी प्रतिभा विकास रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

जीटीसीआई में शीर्ष देश:

- सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जीटीसीआई में शीर्ष तीन देशों के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं।
- इन अग्रणी देशों की प्रथाओं और नीतियों का अध्ययन उनकी प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का प्रयास करने वाले अन्य लोगों के लिए मूल्यवान सीख बन सकता है।
- इन शीर्ष कलाकारों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रणनीतियों के विकास की जानकारी मिल सकती है।

यूरोपीय वर्चस्व और एशियाई परिवर्तन की भूमिका:

- जीटीसीआई में शीर्ष 25 रैंकिंग में यूरोपीय देशों का दबदबा कायम है।
- जापान का शीर्ष 25 से बाहर होना और उसके स्थान पर दक्षिण कोरिया का आगे बढ़ना प्रतिभा प्रतिस्पर्धा परिदृश्य में विकसित होती गतिशीलता को दर्शाता है।

आगे की राह:

समग्र गिरावट के बावजूद, जीटीसीआई रिपोर्ट वैश्विक ज्ञान कौशल को भारत के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले क्षेत्र के रूप में पहचानती है। यह प्रतिभा प्रतिस्पर्धा के कुछ पहलुओं में भारत की ताकत को प्रदर्शित करते हुए नवाचार और सॉफ्टवेयर विकास पर केंद्रित है। इन शक्तियों का लाभ उठाना समग्र प्रतिभा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

7 सीआईआई इंडिया - नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सीआईआई इंडिया-नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुए इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक बाल्टिक (NB8) के आठ देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जो नवाचार तथा प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति के लिए जाने जाते हैं।

नॉर्डिक बाल्टिक आठ (NB8) के बारे में:

- यह एक क्षेत्रीय सहयोग का फ्रेमवर्क है जिसमें पांच नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन तथा तीन बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। इसकी स्थापना 1992 में नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषताएं:

- **भारतीय उद्योग के लिए सहयोग के अवसर तलाशना:** एनबी8 क्षेत्र भारतीय उद्योगों को साझेदारी, संयुक्त उद्यम (जेवी) स्थापित करने और क्षेत्र में संस्थानों तथा उद्यमों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों में संलग्न होने का एक विशाल अवसर प्रदान करना है।
- **लचीली आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रणाली के साथ सहयोग:** भारत की लॉजिस्टिक्स नीति के अनुरूप कुशल और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता है। कॉन्क्लेव का उद्देश्य यह पता लगाना है कि भारत और नॉर्डिक-बाल्टिक देश तकनीकी प्रगति प्रणाली का उपयोग करके वैश्विक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं।
- **वैश्विक गठबंधन पर जोर:** भारत-नॉर्डिक बाल्टिक संबंध प्राकृतिक और लोकतान्त्रिक तालमेल पर जोर देता है, साथ ही वैश्विक दक्षिण चुनौतियों का समाधान करने तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को आगे बढ़ाने में सहयोग का प्रस्ताव देता है।
- **विशिष्ट क्षेत्रों में अत्याधुनिक नव-प्रौद्योगिकी सहयोग:** एनबी8 देश डिजिटलीकरण, समुद्री समाधान, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई, ई-गतिशीलता और साइबर प्रौद्योगिकियों सहित विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अग्रणी हैं। भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी और स्थिरता तथा डिजिटल साझेदारी जैसी सहयोगी पहल विशिष्ट क्षेत्रों की भागीदारी की गहराई को प्रदर्शित करती हैं।
- **आर्थिक, व्यापार, निवेश और उपस्थिति में सहयोग:** भारत और एनबी8 देशों के बीच वस्तु का व्यापार 2021-22 में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। एनबी8 देशों से संचयी FDI 4.307 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 700 से अधिक एनबी8 देशों की कंपनियां, मुख्य रूप से स्वीडन से, भारत में काम करती हैं और लगभग 150 भारतीय कंपनियों की एनबी8 क्षेत्र में उपस्थिति है।

आगे की राह:

जैसे-जैसे भारत, यूरोप में अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित कर रहा है, वैसे ही बदलते यूरोप के साथ उभरते भारत की स्थिति सामने आ रही है। ऐसी परिस्थितियों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के जुड़ाव की अपार संभावनाएं हैं जिसको बेहतर करने की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय मुद्दे

1 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को रोकने के लिए कॉप 28 पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देती है। यह रिपोर्ट दुबई में होने वाले 28वें सम्मेलन से ठीक पहले प्रकाशित की गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट पेरिस समझौते में उल्लिखित वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए सभी देशों द्वारा वर्तमान कार्य योजनाओं की अपर्याप्तता को रेखांकित करती है।
- पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। हालाँकि रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकतर देश इतने प्रयासों के बावजूद, इन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट कॉप 28 में पहले वैश्विक स्टॉकटेक के महत्त्व को रेखांकित करती है जो राष्ट्रों के लिए सभी क्षेत्रों में अपने जलवायु प्रयासों को बढ़ाने में गति हासिल करने का एक अवसर है। स्टॉकटेक का उद्देश्य 2025 तक प्रस्तुत किए जाने वाले एनडीसी के अगले दौर की रुपरेखा तैयार करना है ताकि त्वरित कार्यवाही के लिए सभी को एक साथ लाया जा सके।
- वैश्विक स्टॉकटेक एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसे पेरिस समझौते के तहत कार्यान्वयन का 'जायजा लेने' और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का आंकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल का हवाला देते हुए चेतावनी दी गई है कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 43% की कटौती की जानी चाहिए। दुनिया भर में सूखे, लू और वर्षा की बढ़ती आवृत्ति व गंभीरता से इस तात्कालिकता पर ध्यान दिए जाने की जरुरत है।

आगे की राह:

साहसिक जलवायु कार्यवाही के कई तात्कालिक लाभ हैं जिनमें अधिक नौकरियाँ, उच्च वेतन, आर्थिक विकास, अवसर, स्थिरता, कम प्रदूषण और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था शामिल हैं। वर्तमान व्यवस्था में व्यापक सुधार करना समय की मांग है जिससे कॉप 28 अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने का एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म बन सके।

2 जलवायु वित्त पर ओईसीडी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओईसीडी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि आर्थिक रूप से विकसित देश 2021 में विकासशील देशों में जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे हैं। रिपोर्ट के निष्कर्ष का सम्पूर्ण प्रकाशन संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले सीओपी 28 जलवायु वार्ता के लिए महत्त्वपूर्ण राह दिखायेगा।

ओईसीडी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- विकसित देशों ने 2021 में जलवायु वित्त में $89.6 बिलियन जुटाए जो कि $100 बिलियन के लक्ष्य से कम है।
- रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तपोषण में 14% की कमी देखी गयी।
- ओईसीडी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में 100 बिलियन डॉलर मिलने की संभावना थी, लेकिन यह डेटा प्रारंभिक और असत्यापित प्रतीत होता है।
- विकासशील देशों को 2025 तक जलवायु निवेश के लिए वार्षिक लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होने का अनुमान है। यह धनराशि 2026 से 2030 तक बढ़कर 2.4 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष हो जाएगी जो 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य की कमी को दिखाता है।

ओईसीडी के बारे में:

- यह लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध 38 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओईसीडी सदस्य आम तौर पर लोकतांत्रिक देश हैं जो मुक्त-बाजार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं।
- OECD की स्थापना 14 दिसंबर 1960 को 18 यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का घोषित लक्ष्य ऐसी नीतियों को आकार देना है जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर तथा कल्याण को बढ़ावा दें।
- ओईसीडी दुनिया भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर रिपोर्ट, सांख्यिकीय डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करता है।
- संगठन दुनिया भर में रिश्वतखोरी और अन्य वित्तीय अपराध को खत्म करने का भी प्रयास करता है। ओईसीडी असहयोगी टैक्स हेवेन समझे जाने वाले राष्ट्रों की एक तथाकथित ब्लैकलिस्ट तैयार करता है।
- भारत उन कई गैर-सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसका ओईसीडी के सदस्य देशों के साथ प्रगतिशील कूटनीतिक संबंध रहा है।

आगे की राहः

जलवायु वित्त पर ओईसीडी रिपोर्ट विकसित देशों द्वारा किए गए वायदों और उनके वास्तविक योगदान के बीच अंतर को उजागर करती है। वर्तमान समय में विकासशील देश बढ़ती जलवायु संबंधी चुनौतियों का जिस तरह से सामना कर रहे हैं, ऐसे में विकसित देशों को आगे बढ़कर जलवायु वित्त और तकनीकी सहयोग करना समय की मांग है।

3 जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती टिटिकाका झील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सैटेलाइट से ली गयी तस्वीर से पता चलता है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार कही जाने वाली टिटिकाका झील जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से सूख रही है। यह झील आंशिक रूप से वर्षा की कमी, उच्च तापमान और चरम जलवायुविक घटनाओं के कारण एंडियन ग्लेशियर के घटने से भी प्रभावित हो रही है।

टिटिकाका झील के बारे में:

- ताजे पानी की यह झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर एंडीज में स्थित है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील माना जाता है। प्रसिद्ध इंकास साम्राज्य की उत्पत्ति भी इसी झील के आसपास हुई थी।
- इस जल निकाय के चारों ओर टिटिकाका राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है जो विशाल मेंढकों जैसे दुर्लभ जलीय वन्यजीवों को आश्रय देता है जिसे 1998 में रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया था।

टिटिकाका झील के सूखने के कारणः

- झील के जल स्तर की निगरानी कर रही कई वैज्ञानिक एजेंसियों ने बताया है कि इसके पीछे मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है।
- मैपबायोमास अगुआ (MapBiomas Agua) के अनुसार, एक निगरानी एजेंसी ने बताया है कि कुल मिलाकर बोलीविया में 1985 से 2022 के बीच नदी और लैगून जैसे प्राकृतिक सतही जल में 39% की गिरावट देखी गई है।

स्थानीय कारकों का कारणः

- स्थानीय कारकों में वनों की कटाई, जंगल की आग, मानवीय गतिविधि तथा बड़े बांधों का निर्माण शामिल है जो नदियों में पानी की मात्रा के स्तर को बदल रहा है।
- लगभग 25 नदियों का जल टिटिकाका झील में मिलता है, सबसे बड़ी रामिस नदी के कुल जल का लगभग दो-पाँचवाँ हिस्सा इस झील जाता है, लेकिन एंडीज ग्लेशियर के कम होने और अपर्याप्त वर्षा के कारण नदियों में पानी की मात्रा कम हो रही है।

वैश्विक कारकः

- वैश्विक संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्य जल विज्ञान चक्र में परिवर्तन स्पष्ट दिख रहा है। अल-नीनो और ला-नीना जैसी घटनाएं भी इस क्षेत्र में वाष्पीकरण की बढ़ी हुई दर का संकेत करती हैं।

टिटिकाका झील में जल स्तर कम होने का प्रभावः

- वर्षा की कमी और वाष्पीकरण में वृद्धि के परिणामस्वरूप नावों के परिचालन में समस्या आ सकती है और तटरेखाओं के सिकुड़ने से मछलियों की आबादी प्रभावित होने की संभावना है। टिटिकाका झील में जलीय वनस्पति और जीव-जंतु भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। कम कृषि उत्पादकता और लंबे समय तक सूखे के कारण इस झील के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई है।

आगे की राहः

यह दुनिया भर की सभी सरकारी एजेंसियों और जलवायु परिवर्तन निगरानी संस्थाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए एक गंभीर चेतावनी है। वनों की कटाई की तर्कसंगत जाँच की जानी चाहिए और वनीकरण उपायों को उच्च स्तर पर लागू किया जाना चाहिए तभी इन बहुआयामी समस्याओं से निजात मिल सकता है।

4 उत्सर्जन (Emission) अंतर रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूएनईपी द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई जिससे पता चलता है कि यदि सभी देशों की वर्तमान जलवायु नीतियां ऐसे ही जारी रहीं, तो इस सदी के अंत तक दुनिया कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगी।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षः

- पेरिस समझौते के तहत वर्तमान प्रतिज्ञाओं ने दुनिया को इस सदी के अंत तक पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2.5-2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की राह पर अग्रसर किया है। पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक पर्यावरण समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को संबोधित करने के लिए 2015 में अपनाया गया था।
- तापमान वृद्धि को 1.5-2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में 28-42% की पर्याप्त कटौती आवश्यक है।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) ने 2022 में 57.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (जीटीसीओ2ई) का एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.2% अधिक है।
- जीवाश्म CO_2 उत्सर्जन वर्तमान GHG उत्सर्जन का लगभग दो तिहाई है।
- 2022 में जीवाश्म CO_2 उत्सर्जन 0.8-1.5% के बीच बढ़ा जो GHG उत्सर्जन में समग्र वृद्धि हेतु मुख्य योगदानकर्ता था।
- जी20 में जीएचजी उत्सर्जन में भी 2022 में 1.2% की वृद्धि हुई है। हालांकि चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्धि के रुझान में व्यापक रूप से भिन्नता है, लेकिन ब्राजील,

यूरोपीय संघ और रूसी संघ में कमी आई है। सामूहिक रूप से G20 देशों का वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन का 76% हिस्सा है।

- 2022 में, ऊर्जा आपूर्ति 20.9 $GtCO_2$ (कुल का 36%) उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत थी। इसके बाद उद्योग (25%), कृषि व भूमि उपयोग और वानिकी (18%), परिवहन (14%) और इमारतें (6.7%) शामिल हैं।
- हालाँकि सभी देशों ने नेट-जीरो का लक्ष्य रखा है, लेकिन G20 देशों में से कोई भी अपने लक्ष्य के अनुरूप गति से उत्सर्जन में कमी नहीं कर रहा है।

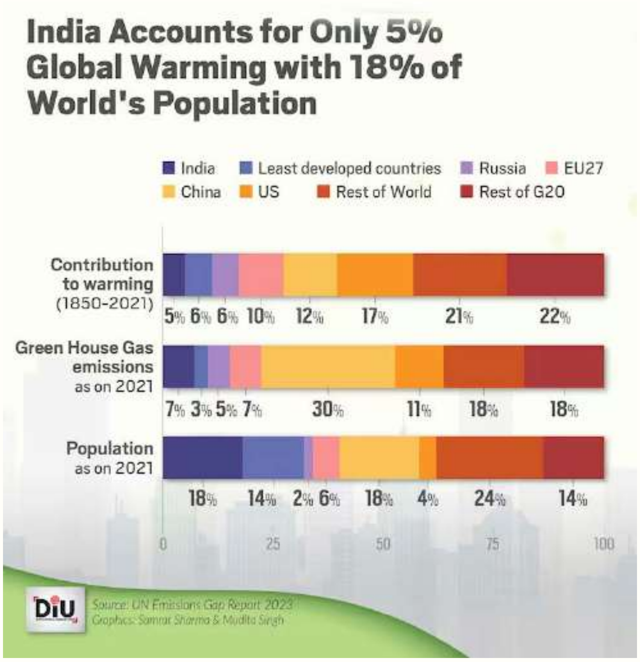

उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा प्रकाशित
- थीम- 'टूटा रिकॉर्ड – तापमान नई ऊंचाई पर पहुंच गया, फिर भी दुनिया उत्सर्जन में कटौती करने में विफल रही'

आगे की राह:

रिपोर्ट के दिए गए रुझानों में वैश्विक स्तर पर निम्न-कार्बन विकास परिवर्तनों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अधिक उत्सर्जन उत्पन्न करने वाले देशों को अधिक महत्त्वाकांक्षी कार्यवाही करने और विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे समयबद्ध तरीके से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

5 स्लेकन (Slacken) तितलियों के प्रवासन पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत के दौरान पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक तितली प्रजातियों का कम पैमाने पर प्रवास हुआ था। कम पैमाने पर प्रवासन विशेष रूप से बाघ और कौवा प्रजातियों के उपपरिवार डेनैने की तितलियों में देखा गया है।

पूर्वी घाट और तितलियाँ:

- पूर्वी घाट में येरकुड पहाड़ियाँ (शेयारॉय पहाड़ियाँ), पंचमलाई, कोली पहाड़ियाँ तथा कलावरम पहाड़ियाँ तमिलनाडु में प्रवास के प्रमुख स्थल हैं। ये तितली समूह प्रमुख रूप से पोन्नुथु हिल्स, कल्लार और अनाइकट्टी हिल्स में देखे जाते हैं।
- इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख तितलियों में ब्लू टाइगर, डार्क ब्लू टाइगर, डबल-ब्रांडेड कौवा और आम कौवा जिन्हें आमतौर पर टाइगर्स व कौवे के नाम से जाना जाता है, शामिल हैं।

कम प्रवासन होने का कारण:

- पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत से पहले, पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र से तितलियां पहाड़ों को छोड़कर पश्चिम की ओर उड़ जाती हैं, लेकिन यह देखा गया है कि कोयंबटूर जैसे तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों में वर्षा की मात्रा में गिरावट ने प्रवासियों के आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन भी प्रवासन को प्रभावित करता है, इसीलिए पश्चिमी घाट क्षेत्र में कठोर जलवायु परिस्थितियों ने प्रवासन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

तितली: एक संकेतक प्रजाति

- तितली एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तितलियों की प्रचुरता किसी भी क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। यह परागण में मदद करके कई प्रजातियों के पौधों के संरक्षण में परागणकर्ता के रूप में भी कार्य करता है।

बदले हुए प्रवासन पैटर्न का प्रभाव:

- औसत से कम प्रवासन भारत के पर्यावरण-संवेदनशील हॉटस्पॉट क्षेत्रों यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बदलते मौसम के पैटर्न को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए पश्चिमी घाट में तितलियों की कम उपस्थिति से उस क्षेत्र के पौधों तथा जैव विविधता के बीच परागण में और कमी आएगी।
- प्रवासन भी तितली के जीवनचक्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है जिससे तितलियों की शीतनिद्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह:

शोधार्थी अन्य संभावित कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति से पहाड़ी क्षेत्रों में वनीकरण जैसे तितली संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस सूचक प्रजाति को संरक्षित करके व्यवहार्य वातावरण प्रदान किया जा सकता है जिसमें सभी जीव जंतुओं को लाभ होगा।

करती हैं।

6 विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा 'वर्ल्ड एनर्जी जॉब्स 2023 रिपोर्ट' जारी की गई। इसमें ऊर्जा क्षेत्र में वर्तमान रोजगार को महामारी से पूर्व स्थिति से तुलना किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक रोजगार महामारी-पूर्व स्तर से 3.4 मिलियन बढ़कर 2022 में 67 मिलियन हो गया।
- "स्वच्छ ऊर्जा सेकटर ने इसी अवधि में वैश्विक स्तर पर 4.7 मिलियन नौकरियां सृजित किया जिससे यह आंकड़ा 35 मिलियन तक पहुंच गया।
- 2020 में छंटनी के बाद जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में रोजगार का सृजन प्रायः कम हुआ जो महामारी-पूर्व रोजगार स्तर से लगभग 1.3 मिलियन नीचे, 32 मिलियन पर बना हुआ है।
- 2019 के पूर्व-महामारी स्तर की तुलना में भारत में स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में नौकरी की वृद्धि सकारात्मक रही।
- भारत में पिछले तीन वर्षों में चौथी सबसे अधिक संख्या में नई स्वच्छ ऊर्जा नौकरियां सृजित हुईं।
- रिपोर्ट में ऊर्जा उद्योग के पांच प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिससे महामारी के बाद अधिकतम रोजगार सृजन हुआ।
- इन क्षेत्रों में सौर पीवी, पवन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और बैटरी विनिर्माण, ताप पंप तथा महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।
- इन पांच क्षेत्रों ने लगभग 9 मिलियन श्रमिकों को रोजगार दिया है। इन सभी क्षेत्रों में सोलर पीवी लगभग 4 मिलियन नौकरियों के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है।
- दूसरी ओर, ईवी और उसकी बैटरियों का विनिर्माण विकास का सबसे बड़ा स्रोत था।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ की विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में पैदा हुई नौकरियों से अधिक था।

रिपोर्ट में भारत:

- स्वच्छ ऊर्जा नौकरियों ने पिछले तीन वर्षों में वैश्विक ऊर्जा नौकरियों में वृद्धि को बढ़ावा दिया लेकिन भारत, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व के कुछ देशों में जीवाश्म ईंधन रोजगार में वृद्धि देखी गई।
- चीन और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाद ऊर्जा श्रमिकों की संख्या में भारत, विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है।

आगे की राह:

रिपोर्ट बदलते ऊर्जा रोजगार परिदृश्य पर प्रकाश डालती है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र रोजगार सृजन में अग्रणी है। क्षेत्रीय विविधताएं और नीतिगत सिफारिशें निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में उचित परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित तथा समावेशी दृष्टिकोण के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

7 आइसलैंड में भूकंप के झटके

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आइसलैंड की मौसम विज्ञान सेवा ने एक चिंताजनक चेतावनी जारी किया है कि पिघला हुआ मैग्मा आइसलैंड की सतह पर आ सकता है जिससे सम्पूर्ण शहर प्रभावित हो सकता है। आइसलैंड के दक्षिण-पश्चिमी रेक्जेन्स प्रायद्वीप में आए 800 भूकंपों के बाद आइसलैंड के अधिकारियों ने आपातकाल की स्थिति जारी किया है।

आइसलैंड: भूकंपीय गतिविधि का केंद्र

- आइसलैंड मध्य-अटलांटिक रिज (Ridge) पर स्थित है जो इसे भूकंपीय गतिविधि का केंद्र बनाता है। आइसलैंड द्वीपीय क्षेत्र में एक वर्ष में लगभग 26000 भूकंप आते हैं। उनमें से अधिकांश की गति रिक्टेल स्केल पर बहुत कम होती है जिससे ये अधिक प्रभावी नहीं होते हैं।
- आइसलैंड दुनिया के कुछ सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों (33) का द्वीप है जिसमें सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी आईजफजल्लाजोकुल (Eyjafjallajokull) है जिसमें 2010 में विस्फोट हुआ था जिससे यूरोप में विशाल राख का बादल फैल गया था।
- वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी किया है कि हाल के भूकंप के झटके फाग्राडल्सफजाल (Fagradalsfjall) ज्वालामुखी में विस्फोट का कारण बन सकते हैं जो रेकजाविक के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 40 किमी दूर स्थित है और दुनिया का सबसे नया ज्वालामुखी है।
- अन्य प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में हेक्ला, ग्रिमवोस्टन, होलुह्रौन और लिटली-ह्रुतुर (फाग्राडल्सफजाल प्रणाली का हिस्सा) शामिल हैं।

भूकंप की तीव्रता और ज्वालामुखी विस्फोट:

- यह क्षेत्र भूकंपों के झुंड (Earthquake Swarms) के रूप में जाना जाता है जहाँ ज्यादातर कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं जिनसे अधिक पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन इसकी लगातार घटना ज्वालामुखी विस्फोट को प्रेरित कर सकती है। तीव्र गर्मी पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान को पिघलाकर मैग्मा बनाती है जो ऊपर की ओर चला जाता है जिसका अधिकांश भाग गहरे भूमिगत मैग्मा कक्षों में रह जाता है। छोटा अंश सतह पर मौजूद छिद्रों और दरारों के माध्यम से फूटता है जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। पृथ्वी की सतह के करीब मैग्मा की गति से आसपास की चट्टान पर बल पड़ता है जो अक्सर भूकंप के झुंड का कारण बनता है।

आगे की राह:

भूकंपीय झुंड और ज्वालामुखी विस्फोट उन प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत आते हैं जिनकी भविष्यवाणी या रोकथाम नहीं की जा सकती है, इसलिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट और परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके।

1 चरम वातावरण में पिकोसिस्टिस सेलिनरम की आणविक निपुणता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की इंस्पायर फैकल्टी फेलो डॉ. ज्योति सिंह द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में आणविक तंत्र का पता लगाया है जो हरे शैवाल पिकोसिस्टिस सेलिनारम (Picocystis Salinarum) को चरम स्थितियों, विशेष रूप से अत्यधिक क्षारीय/हाइपरसॉमिक वातावरणीय स्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाता है। इस खोज ने जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और पौधों में सहनशीलता बढ़ाने के लिए अपार संभावनाएं प्रदर्शित किया है।

शैवाल की तन्यता (Resilient):

- पिकोसिस्टिस सेलिनारम, सबसे छोटे हरे शैवालों में से एक, राजस्थान के हाइपरसैलिन झील सांभर की कठोर परिस्थितियों में प्राप्त किया गया है जिसमें अत्यधिक लचीलापन या तन्यता देखा गया है। डॉ. ज्योति सिंह की खोज को जीव की पॉलीएक्सट्रीम स्थितियों के अनुकूल होने की रहस्यमय क्षमता से प्रेरणा मिली जो अभी तक विश्व के अन्य विभिन्न खारे झीलों में देखी गई है, लेकिन यह पहली बार भारत में सांभर झील में पहचानी गई।

आणविक तंत्रों का अनावरण:

- अनुसंधान टीम ने उच्च-थ्रुपुट (Throughput) लेबल-मुक्त क्वांटिटेशन-आधारित क्वांटिटेटिव प्रोटिओमिक्स विधि का उपयोग करते हुए पी. सेलिनारम के अनुकूलन के आणविक तंत्र का गहराई से अध्ययन किया।
- अध्ययन ने शैवाल के प्रोटिओम में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान किया है। इसने महत्त्वपूर्ण अनुरूप नियामक तंत्र का प्रयोग करके लचीलेपन को समझने के लिए एक आधार प्रदान किया है।

मुख्य निष्कर्ष:

- पी. सैलिनारम पर्यावरण की उच्च लवणता-क्षारीयता के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में इसने चैपरोन प्रोटीन के अपग्रेडेशन के साथ-साथ उन्नत प्रकाश संश्लेषण और एटीपी संश्लेषण प्रदर्शित किया है।
- शैवाल अत्यधिक लवणीय-क्षारीय स्थितियों के तहत बढ़ी हुई प्रकाश संश्लेषक गतिविधि को प्रदर्शित करके मानक की अवहेलना करता है जो हाइपरसॉमिक स्थितियों के तहत अधिकांश प्रकाश संश्लेषक जीवों में देखे गए विशिष्ट स्थिति को चुनौती देता है।

जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग:

- फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी (सेक्शन एक्सट्रीम माइक्रोबायोलॉजी) में प्रकाशित यह अध्ययन पी. सैलिनारम को विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक आशाजनक खोज मानता है।
- शैवाल की अनूठी विशेषताओं का उपयोग बाइकार्बोनेट-आधारित एकीकृत कार्बन कैप्चर और बायोमास उत्पादन के लिए किया जाता है जो टिकाऊ व संसाधन-कुशल जैव-प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

भविष्य के लिए निहितार्थ:

- डॉ. सिंह का शोध न केवल एक्सट्रोफिलिक जीवों के अनुकूलन तंत्र पर प्रकाश डालता है, बल्कि नवीन जैव प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास के रास्ते भी खोलता है। प्राप्त निष्कर्ष माइक्रोएल्गल बायोप्रोडक्ट्स भविष्य के विकास हेतु आशाजनक हैं और पौधों में लवणता बढ़ाने, कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में योगदान दे सकते हैं।

आगे की राह:

डॉ. ज्योति सिंह और उनकी टीम का यह शोध न केवल पी. सेलिनारम के असाधारण लचीलापन को उजागर करता है, बल्कि जैव प्रौद्योगिकी में परिवर्तनकारी अनुप्रयोगों के लिए इसकी क्षमता को भी प्रकट करता है। यह अध्ययन पर्यावरण विज्ञान से लेकर बायोमेडिसिन तक विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ और नवीन समाधानों का उपयोग करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

2 नासा का वायुमंडलीय तरंग प्रयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपग्रह संचार और जीपीएस प्रणालियों में बढ़ते व्यवधानों के बीच नासा ने वायुमंडलीय तरंग प्रयोग (Atmospheric Waves Experiment- AWE) को शुरू किया है जो अंतरिक्ष के मौसम को समझने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। नासा के हेलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम के तहत योजनाबद्ध यह मिशन ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम में पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

वायुमंडलीय तरंग प्रयोग (AWE) के बारे में:

उद्देश्य:

- मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल का निरीक्षण करने हेतु एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करेगा।

इंस्ट्रुमेंटेशन:

- एडब्ल्यूई में मेसोपॉज को स्कैन करने और एयरग्लो पैटर्न को कैप्चर करने हेतु चार समान दूरबीनों के साथ एक उन्नत मेसोस्फेरिक तापमान मैपर (एटीएमटी) की सुविधा है।

माप:

- एटीएमटी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश की चमक को मापेगा और डेटा को तापमान आधारित मानचित्र में परिवर्तित करेगा। यह जानकारी एयरग्लो गतिविधियों और ऊपरी वायुमंडल तथा अंतरिक्ष मौसम में उनकी भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।

अंतरिक्ष मौसम और उसके महत्त्व के बारे में:

- अंतरिक्ष मौसम अंतरिक्ष में पर्यावरणीय परिस्थितियों को संदर्भित

करता है जो सौर ज्वाला और उत्सर्जन सहित सूर्य की गतिविधियों से प्रभावित होती है। यह पृथ्वी पर उपग्रह-आधारित संचार, रेडियो संचार, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड जैसे महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सीधे प्रभावित करता है।

- सौर गतिविधियों के अलावा अंतरिक्ष का मौसम, स्थलीय मौसम से भी प्रभावित होता है जिससे एक गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रणाली का विकास होता है।

गुरुत्वाकर्षण तरंगों के निर्माण में अंतरिक्ष मौसम की भूमिका

- गुरुत्वाकर्षण तरंगें ऊर्ध्वाधर तरंगें होती हैं, विशेष रूप से वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगें (एजीडब्ल्यू) जो चरम मौसम की घटनाओं के दौरान उत्पन्न होती हैं जिससे स्थिर हवा का ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है।
- एक स्थिर वातावरण में गुरुत्वाकर्षण तरंगें तब उत्पन्न होती हैं, जब बढ़ती वायु तथा आसपास के वातावरण के बीच तापमान में अंतर होता है जिससे एक बल उत्पन्न होता है जो वायु को उसके प्रारंभिक स्थान पर पुनः स्थापित कर देता है।

आगे की राह:

ये प्रयोग हमारे ग्रह पर रहने वाले लोगों के लाभ के लिए पृथ्वी, अंतरिक्ष, भौतिक और जैविक विज्ञान में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के नासा के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं पर तेजी से निर्भर हो रही दुनिया में वायुमंडलीय तरंगें, वैज्ञानिक अन्वेषण के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में उभरेगा जो अंतरिक्ष मौसम के रहस्यों और हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया पर इसके गहरे प्रभाव को उजागर करने में सहायता करेगी।

3 चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए नयी वैक्सीन को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन Ixchiq को मंजूरी दी है। यूरोपीय निर्माता वलनेवा द्वारा विकसित इस वैक्सीन का उद्देश्य चिकनगुनिया वायरस से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य खतरे को संबोधित करना है।

चिकनगुनिया का अवलोकन:

- चिकनगुनिया, एडीज मच्छरों द्वारा प्रसारित एक वायरल संक्रमण है जिसमें जोड़ों में तेज दर्द होना, शारीरिक कमजोरी और बुखार होना आदि प्रमुख लक्षण होता है। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में इसकी व्यापकता के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसके प्रकोप की सूचना मिलती रही है। 2004 के बाद से वायरस के अधिक व्यापक होने से एंडीज अल्बोपिक्टस मच्छरों द्वारा आसान संचरण की सुविधा प्रदान करने वाले वायरल अनुकूलन के कारण इसका प्रसार बढ़ रहा है।
- जिन लक्षणों को अक्सर डेंगू या जीका समझ लिया जाता है उनमें जोड़ों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, मतली, थकान और शरीर पर दाने शामिल हैं, जबकि इसमें मृत्यु होने की संभावना कम होती है। अभी तक इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, परन्तु दर्दनाशक दवाओं, ज्वरनाशक दवाओं, आराम और पर्याप्त तरल पदार्थों का उपयोग करके इसमें कुछ राहत मिल सकती है।

निवारण रणनीतियाँ:

- चिकनगुनिया की रोकथाम में मुख्य रूप से मच्छर नियंत्रण गतिविधियाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य आउटरीच और नियमित नागरिक रखरखाव शामिल हैं। इस बीमारी से बचने और इसे प्रसारित होने से रोकने के लिए औषधीय मच्छरदानी का उपयोग करने तथा आसपास पानी के जमाव को खत्म करने की सलाह दी जाती है।

Ixchiq वैक्सीन प्रभावशीलता:

- मांसपेशियों में एकल-खुराक इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली Ixchiq में चिकनगुनिया वायरस का एक जीवित व कमजोर रूप पाया जाता है। यह टीका प्राप्तकर्ताओं में शुरुआत में हल्के लक्षण पैदा कर सकता है जो वास्तविक बीमारी वाले व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए लक्षणों को प्रतिबिंबित करता है। Ixchiq की सुरक्षा का दो उत्तरी अमेरिकी नैदानिक अध्ययनों में कठोरता से मूल्यांकन किया गया था जिसमें 3,500 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया था, जबकि अन्य 1,000 को प्लेसबो दिया गया था। टीका प्राप्तकर्ताओं द्वारा बताए गए सामान्य दुष्प्रभावों में सिरदर्द, थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, बुखार तथा मतली आना शामिल है। हालाँकि ये दुष्प्रभाव आम तौर पर हल्के और क्षणिक थे।

वैक्सीन की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया:

- Ixchiq की प्रभावशीलता एक अमेरिकी नैदानिक अध्ययन से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया डेटा के माध्यम से स्थापित की गई थी जिसमें 266 वैक्सीन प्राप्तकर्ताओं की तुलना 96 प्लेसबो प्राप्तकर्ताओं के

साथ की गई थी। यह मूल्यांकन एंटीबॉडी स्तरों पर केंद्रित था जो गैर-मानव प्राइमेट्स में सुरक्षात्मक साबित हुआ जिन्हें टीका लगाए गए व्यक्तियों से रक्त प्राप्त हुआ था।

आगे की राह:

टीका संभावित रूप से दुर्बल करने वाली बीमारी को रोकने में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए उपचार के विकल्प वर्तमान समय में सीमित हैं। कोविड अनुसंधान के दौरान शुरू किए गए फास्ट-ट्रैक मार्ग से प्रेरित होकर, इस मंजूरी से वैश्विक स्तर पर वैक्सीन रोलआउट में तेजी आने की उम्मीद है। इस अनुसंधान से उच्च प्रसार वाले देशों जैसे 'ब्राजील, पैराग्वे, भारत और पश्चिमी अफ्रीका' के कुछ हिस्सों को अधिक लाभ होगा।

4 पृथ्वी के कोर में एक रहस्यमय ई-प्राइम परत का निर्माण

चर्चा में क्यों?

एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) के विशेषज्ञों सहित शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए अध्ययन में पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी हिस्से में एक नई और रहस्यमय परत के उद्भव पर प्रकाश डाला गया है जिसे 'ई-प्राइम लेयर' कहा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चार मूलभूत परतें आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट शामिल हैं।

ई-प्राइम लेयर का निर्माण:

- कई वर्षों से वैज्ञानिक समुदाय का मानना था कि कोर और मेंटल के बीच सामग्री का आदान-प्रदान न्यूनतम है। हालाँकि, नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित शोध इस धारणा को चुनौती दे रहा है। अध्ययन से संकेत मिलता है कि ई-प्राइम परत का निर्माण सतही जल द्वारा ग्रह में गहराई तक प्रवेश करने का परिणाम है जो धात्विक तरल कोर के सबसे बाहरी क्षेत्र में परिवर्तनकारी कारणों को प्रेरित करता है।

जल की यात्रा: टेक्टोनिक प्लेट्स और कोर-मेंटल सीमा

- अध्ययन से पता चला है कि अरबों वर्षों में सतह के पानी को ले जाने वाली टेक्टोनिक प्लेटों ने इसे पृथ्वी की गहराई तक पहुँचाया है। सतह से लगभग 1,800 मील नीचे कोर-मेंटल सीमा तक पहुंचने पर पानी कोर में सिलिकॉन के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है जिससे सिलिका का विकास होता है।

अत्यधिक दबाव में रासायनिक परिवर्तन:

- शोधकर्ताओं ने देखा है कि उच्च दबाव में अंतर्वाहित पानी मुख्य सामग्रियों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बाहरी कोर पर हाइड्रोजन-समृद्ध और सिलिकॉन-रहित परत का निर्माण होता है जो स्वयं को एक फिल्म जैसी संरचना के रूप में प्रस्तुत करती है।

पृथ्वी के आंतरिक तंत्र के लिए व्यापक निहितार्थ:

- शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि ई-प्राइम परत की खोज से पृथ्वी के आंतरिक तंत्र के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। यह पहले की तुलना में अधिक जटिल वैश्विक जल चक्र प्रस्तुत करता है जो सतही जल चक्रों को गहरे धात्विक कोर से जोड़ने वाली परस्पर जुड़ी भू-रासायनिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है।

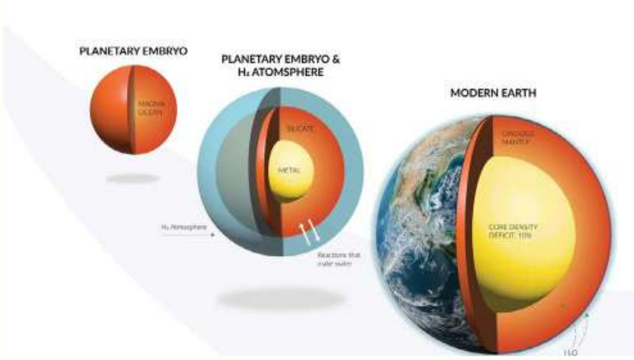

चरम स्थितियों का पुनर्निर्माण:

- भू-वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने जर्मनी में आर्गोन नेशनल लैब के उन्नत फोटॉन स्रोत और डॉयचेस एलेक्ट्रोनन-सिंक्रोट्रॉन के पेट्रा III में परिष्कृत प्रयोगात्मक तरीकों को नियोजित किया। इन तकनीकों का उद्देश्य कोर-मेंटल सीमा पर देखी गई चरम स्थितियों को फिर से बनाना है जो रहस्यमय ई-प्राइम परत को जन्म देने वाली परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

आगे की राह:

यह अध्ययन न केवल पृथ्वी की मूल संरचना के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि सतही जल चक्रों और पृथ्वी ग्रह के गहरे क्षेत्रों के बीच जटिल गतिशीलता को समझने के महत्त्व को भी रेखांकित करता है।

5 नासा का डीएसओसी ब्रेकथ्रू: लेजर संचार

चर्चा में क्यों?

नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस प्रयोग ने चंद्रमा से दूर स्थानों तक लेजर के माध्यम से सफलतापूर्वक डेटा संचारित करके एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल किया है। साइके (Psyche) अंतरिक्ष यान द्वारा भेजे गये इस उपलब्धि ने न केवल ऑप्टिकल संचार के अब तक के सबसे दूर के प्रदर्शन के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, बल्कि यह अंतरग्रहीय संचार में एक अभूतपूर्व सफलता का संकेत है।

पहला प्रकाश क्षण: भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना

- डीएसओसी प्रयोग ने अंतरिक्ष यान संचार में एक नए युग की शुरुआत करते हुए एक अग्रणी 'पहला प्रकाश' क्षण चिह्नित किया। चंद्रमा तक और उससे दूर लेजर के माध्यम से सफलतापूर्वक डेटा संचारित करना, यह उपलब्धि गहरे अंतरिक्ष संचार प्रौद्योगिकियों में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। इस उपलब्धि के निहितार्थ इसकी रिकॉर्ड-सेटिंग प्रकृति से कहीं आगे तक फैले हुए हैं जिससे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के समर्थन के लिए महत्त्वपूर्ण उच्च-डेटा-दर संचार के रहस्य खुल रहे हैं जिसमें मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने

का साहसिक लक्ष्य भी शामिल है।

ऑप्टिकल संचार का अभूतपूर्व प्रदर्शन:

- एन्कोडेड परीक्षण डेटा ले जाने वाले निकट-अवरक्त लेजर ने लगभग 16 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, यह पृथ्वी-चंद्रमा पृथक्करण से लगभग 40 गुना अधिक दूर है। डीएसओसी प्रयोग की अभूतपूर्व क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए लेजर किरण कैल्टेक के पालोमर वेधशाला (कैलिफोर्निया) में हेल टेलीस्कोप में अपने गंतव्य तक पहुंच गई।

मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट की यात्रा:

- अपने दो-वर्षीय मिशन के दौरान पृथ्वी पर उच्च-बैंडविड्थ परीक्षण डेटा भेजने के लिए डिजाइन किया गया डीएसओसी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन ने अपनी यात्रा तब शुरू की, जब साइके अंतरिक्ष यान मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट की ओर आगे बढ़ा। 14 नवंबर को हुए पहला प्रकाश की घटना इस महत्त्वाकांक्षी मिशन में एक उपयोगी कदम है।
-

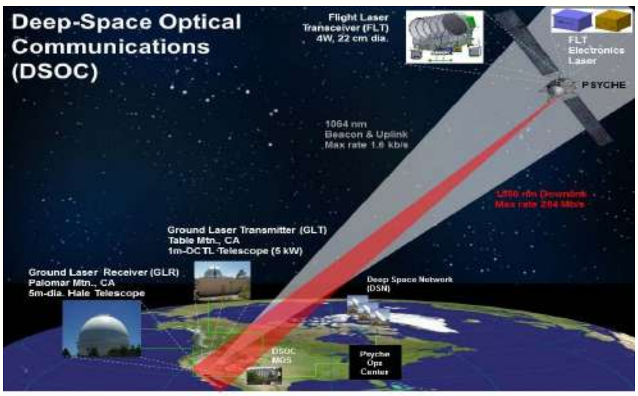

परीक्षण डेटा का एक साथ प्रसारण:

- परीक्षण के दौरान, अपलिंक बीकन ने ट्रांसीवर को निर्देशित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे यह अपने डाउनलिंक लेजर को ठीक से पालोमर पर लक्षित करने में सक्षम हो पाया। ट्रांसीवर और ग्राउंड स्टेशन दोनों पर स्वचालित सिस्टम ने उनके पॉइंटिंग को ठीक किया जिससे प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त हुआ जिसे 'लिंक को बंद करना' कहा जाता है।

उच्च-डेटा-दर संचार के लिए एक पथ:

- पहला प्रकाश की घटना महत्त्वपूर्ण डीएसओसी उपलब्धियों में से एक है। यह उपलब्धि उच्च-डेटा-दर संचार के लिए मार्ग प्रशस्त करती है जो वैज्ञानिक जानकारी, उच्च-परिभाषा इमेजरी और स्ट्रीमिंग वीडियो प्रसारित करने में सक्षम है।

आगे की राह:

नासा के डीएसओसी प्रयोग की हालिया उपलब्धि न केवल एक तकनीकी सफलता है, बल्कि अंतरग्रहीय संचार के परिदृश्य को फिर से आकार देने, मानवता को अंतरिक्ष अन्वेषण में अभूतपूर्व उपलब्धियों की ओर प्रेरित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। ऐसे ही सकारात्मक परिणाम देने वाले अन्वेषण मानव सभ्यता के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

6 ऑर्बिटल रेजोनेंस में 6 ग्रह पाए गए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने छह ग्रहों वाले सौर मंडल की खोज की है जिसमें एक 'सुपर-अर्थ', पांच मिनी नेपच्यून और तारे HD1528259 के चारों ओर एक कक्षा शामिल है जिसका द्रव्यमान लगभग समान है लेकिन सूर्य से थोड़ा बड़ा है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सोफी स्पेक्ट्रोग्राफ और टीईएसएस एक्सोप्लैनेट-हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके ग्रहों की कक्षीय गतिविधियों का मानचित्रण किया। शोधकर्ताओं ने सात वर्षों तक निगरानी करने के बाद पाया कि छह ग्रह पूर्ण कक्षीय अनुनाद में थे।

कक्षीय अनुनाद (Orbital Resonance) के बारे में:

- आकाशीय यांत्रिकी में कक्षीय प्रतिध्वनि तब होती है जब परिक्रमा करने वाले पिंड एक दूसरे पर नियमित तथा आवधिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं।
- यह घटना आम तौर पर तब उत्पन्न होती है जब पिंडों की कक्षीय अवधि छोटे पूर्णांकों के अनुपात से संबंधित होती है।
- इसमें बाइनरी अनुनाद सबसे आम होता है जिसमें संबंधित कक्षीय अवधि अनुपात वाली वस्तुओं की एक जोड़ी शामिल होती है।
- कक्षीय प्रतिध्वनि पिंडों के बीच पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है जिससे एक-दूसरे की कक्षाओं को बदलने या बाधित करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- कई मामलों में कक्षीय अनुनाद के परिणामस्वरूप एक अस्थिर अंत:क्रिया होती है जिससे पिंड गति का आदान-प्रदान करते हैं और तब तक कक्षाओं को स्थानांतरित करते हैं जब तक कि प्रतिध्वनि मौजूद न हो जाए।

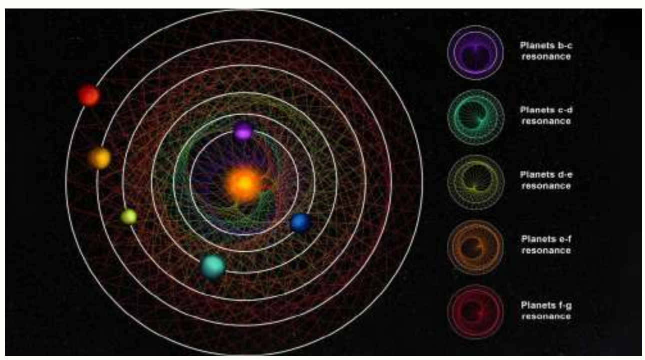

सुपर अर्थ के बारे में:

- सुपर-अर्थ पृथ्वी के समान लेकिन आकार में बड़ा ग्रह होता है जिसकी सतह यूरेनस के समान एक गैस आवरण से घिरी हुई है और सतह की स्थिति या रहने की क्षमता के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देती है।

- टेलीस्कोप तकनीक द्वारा खोजे गए अधिकांश सुपरअर्थ एम श्रेणी के लाल बौने तारों के समीप होते हैं जो हमारे सूर्य या सूर्य के समान जी श्रेणी के तारों से छोटे हैं।

TESS एक्सोप्लैनेट-हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप के बारे में:

- ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) का उपयोग सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की खोज में किया जाता है जिनमें जीवन का समर्थन करने वाले ग्रह भी शामिल हैं।
- TESS को 18 अप्रैल 2018 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।
- TESS का मिशन दृष्टिकोण दो वर्षों के भीतर पूरे आकाश का सर्वेक्षण करना था।

आगे की राह:

यह सौर मंडल बहुत अनोखा है जिसमें सभी छह ग्रह पूरी तरह से सिंक्रनाइज सिम्फनी के समान चलते हैं। तकनीकी शब्दों में, इसे अनुनाद के रूप में जाना जाता है जो 'सटीक एवं बहुत व्यवस्थित' होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, सभी सौर मंडलों की शुरुआत इसी प्रकार हुई मानी जाती है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि 100 में से केवल 1 सिस्टम ने उस समकालिकता को बरकरार रखा है।

7 काइमेरा रिसर्च अंग प्रत्यारोपण में सहायक- स्टडी

चर्चा में क्यों?

प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल (आईपीएससी) तकनीक में हालिया प्रगति ने जानवरों के अंदर मानव अंगों के विकास का दावा किया है। हालिया अनुसंधान में एक जीवित काइमेरिक बंदर का सफल निर्माण होना, इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि प्रत्यारोपण के लिए अंगों की वैश्विक कमी, आज भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।

काइमेरा (Chimaeras) इन नेचर: ए जेनेटिक टेपेस्ट्री

- जैविक संदर्भ में काइमेरा विशिष्ट जीनोटाइप वाली कोशिकाओं से बने जीव होते हैं। इसकी प्रकृति विभिन्न उदाहरणों को प्रदर्शित करती है जिसमें दोहरे रंग के किनारों वाले हाफ साइडर बडगेरिगर (Half-Sider Budgerigar) से लेकर एंगलरफिश में देखी जाने वाली चरम सहजीवी काइमेरिज्म शामिल हैं। यहां तक कि मनुष्यों में भी काइमेरिज्म के उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे कि भ्रूण अवस्था में दो युग्मनजों का संलयन या जुड़वां भ्रूण। रक्त-समूह काइमेरिज्म और माइक्रोकाइमेरिज्म, जहां भ्रूण का डीएनए वर्षों तक मां के ऊतकों में बना रहता है, जीवित जीवों में आनुवंशिक मिश्रण की जटिलता को उजागर करता है।

चिकित्सा साहित्य में काइमेरा का महत्त्व:

- मानव काइमेरा मिथक और प्रकृति तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी तरह से जुड़े हैं। उदाहरणों में दो रक्त प्रकार वाले व्यक्तियों से लेकर अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से गुजरने वाले लोग शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप दाता और प्राप्तकर्ता आनुवंशिक सामग्री का मिश्रण होता है। अंग प्रत्यारोपण से काइमेरिज्म भी होता है जहां प्राप्तकर्ता अपने ऊतकों से अलग आनुवंशिक संरचना वाले अंगों की मदद करता है।

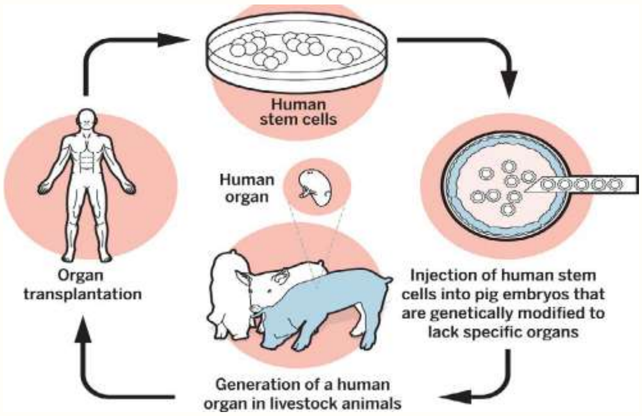

प्रगति और सीमाएँ:

- पिछले प्रयोगों ने चूहों, सूअरों और गायों में काइमेरा को प्रेरित किया है जिसका लक्ष्य बढ़ते मानव अंगों के लिए मॉडल सिस्टम बनाना है। आशाजनक होते हुए भी इन अध्ययनों को विकासवादी मतभेदों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालिया प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन में एक जीवित काइमेरिक बंदर की सफल पीढ़ी की रिपोर्ट दी गई है जो एक गैर-मानव प्राइमेट है और क्रमिक रूप से मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। यह भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए बायोमेडिकल मॉडल के रूप में काइमेरा बनाने हेतु नए रास्ते खोलता है।

काइमेरिक (Chimaeric) बंदरों का निर्माण:

- इस हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने हरे फ्लोरोसेंट प्रोटीन (जीएफपी) के साथ संशोधित भ्रूण स्टेम कोशिकाओं को निकालने के लिए साइनोमोलगस बंदरों या लंबी पूंछ वाले मकाक का उपयोग किया। इन कोशिकाओं को प्राप्तकर्ता भ्रूणों में इंजेक्ट किया गया जिसके परिणामस्वरूप छह पूर्ण-कालिक संतानें पैदा हुई। काइमेरिक बंदर ने व्यापक जीएफपी-चिह्नित ऊतकों को प्रदर्शित किया जो सफल एकीकरण का संकेत देता है। दस दिनों के बाद बंदर की इच्छामृत्यु की नैतिक चिंताओं और सीमाओं के बावजूद यह अध्ययन जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने में गैर-मानव प्राइमेट्स का उपयोग करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करता है।

आगे की राह:

अध्ययन गैर-मानव प्राइमेट्स के साथ काइमेरा बनाने में एक सुखद अनुभूति दिखता है, परन्तु मानव जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों की कल्पना करने से पहले नैतिक विचारों और सीमाओं को संबोधित किया जाना चाहिए। जानवरों के अंदर मानव अंगों को विकसित करने की क्षमता आशाजनक है, लेकिन इस अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रयास के भविष्य के लिए जिम्मेदार और नैतिक अन्वेषण करते रहना आवश्यक है।

1 असुरक्षित उपभोक्ता ऋण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों दोनों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसे असुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार 25 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इस निर्णय से वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को कमजोर करने के लिए ऋण देने की बढ़ती प्रवृत्ति को कम किया जा सकेगा। असुरक्षित ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने का आरबीआई का कदम पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को बढ़ाने का एक तरीका होता है।

पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के बारे में:

- यह किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप होता है जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (जिसे पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के रूप में भी जाना जाता है) का उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा और दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता तथा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

आरबीआई के इस निर्णय का प्रभाव:

- आरबीआई ने उपभोक्ता ऋण, क्रेडिट कार्ड प्राप्य और एनबीएफसी जैसी कुछ श्रेणियों में बैंकों के जोखिम पर जोखिम भार बढ़ा दिया है। बैंकों के असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण और उपभोक्ता टिकाऊ ऋण पर जोखिम-भार 100% से बढ़ाकर 125% तथा क्रेडिट कार्ड पर जोखिम भार 125% से बढ़ाकर 150% कर दिया गया है। इसके अलावा एनबीएफसी के असुरक्षित व्यक्तिगत और उपभोक्ता टिकाऊ ऋण एवं क्रेडिट कार्ड पर जोखिम भार 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया है।
- इसका मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन विशिष्ट ऋण श्रेणियों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे से बचने के लिए बफर के रूप में अधिक पूंजी रखने की आवश्यकता होगी। हालाँकि आरबीआई ने एनबीएफसी द्वारा माइक्रोफाइनेंस ऋणों को जोखिम-भार वृद्धि से छूट दी है।

आरबीआई द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाने का कारण:

- मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के असुरक्षित क्रेडिट कार्ड ऋण और व्यक्तिगत ऋण में वृद्धि क्रमशः 29.9% व 25.5% रही, जबकि कुल ऋण वृद्धि 20% थी। एनबीएफआई वृद्धि में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है।

असुरक्षित ऋण के बारे में:

- असुरक्षित ऋण एक ऐसा ऋण है जिसके लिए किसी भी प्रकार की संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। सुरक्षा के रूप में उधारकर्ता की संपत्ति पर भरोसा करने के बजाय, ऋणदाता उधारकर्ता की साख के आधार पर असुरक्षित ऋण स्वीकृत करते हैं।
- असुरक्षित ऋण के उदाहरणों में व्यक्तिगत ऋण, छात्र ऋण और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। ऋणदाता यह तय कर सकते हैं कि उधारकर्ता की साख के आधार पर असुरक्षित ऋण को मंजूरी दी जाए या नहीं, लेकिन नियम उधारकर्ताओं को भेदभावपूर्ण ऋण देने की प्रथाओं से बचाते हैं।

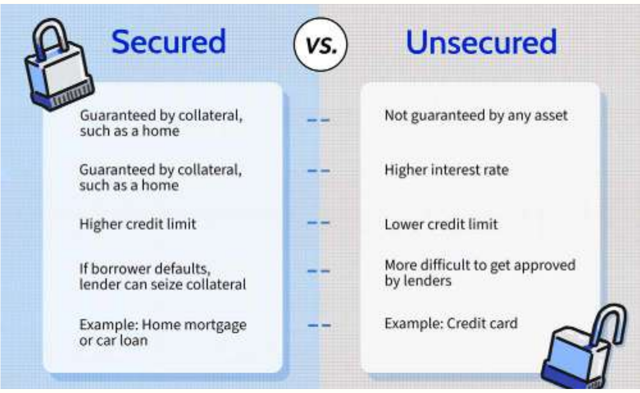

आगे की राह:

बैंकों और एनबीएफसी को असुरक्षित ऋणों के लिए अपने जोखिम मॉडल व ऋण देने की प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उन्हें ऋण पात्रता मूल्यांकन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऋण देना जारी रखते हुए जोखिम प्रबंधन के लिए वैकल्पिक रणनीतियों पर भी विचार करना चाहिए।

2 रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने नई दिल्ली में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन (आरआईएसई) नामक एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम भारत और ऑस्ट्रेलिया में सर्कुलर इकोनॉमी प्रौद्योगिकियों व समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप और छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) का समर्थन करेगा।

रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन के बारे में:

- आरआईएसई एक्सेलेरेटर अटल इनोवेशन मिशन (नीति आयोग) द्वारा देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल व सीएसआईआरओ (ऑस्ट्रेलिया) की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी द्वारा लांच किया गया।

विजन:

- ऑस्ट्रेलिया और भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण साझा राष्ट्रीय चुनौतियों को हल करने, प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचार, सीमा पार सहयोग और पारिस्थितिकी तंत्र एकीकरण के माध्यम से स्थायी प्रभाव पैदा करने वाले स्टार्ट-अप को महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान

करना है।

फोकस थीमः

- पर्यावरण और जलवायु प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के अलावा इस कार्यक्रम को कई क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्ट-अप में तेजी लाने के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें जलवायु स्मार्ट कृषि, स्वच्छता, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन तथा जलवायु स्मार्ट गतिशीलता शामिल है।

सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में:

- सर्कुलर इकोनॉमी उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल होता है जिसमें मौजूदा सामग्रियों तथा उत्पादों को यथासंभव लंबे समय तक साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है। इसके तहत प्रसंस्करण उपरांत उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ाया जाता है। व्यावहारिक रूप में इसका उद्देश्य कचरे को न्यूनतम करके वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तन करना है।

भारत में स्टार्टअप की वर्तमान स्थितिः

- भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 99000 से अधिक स्टार्टअप हैं जिनमें से 49% का आधार टियर 2-टियर और 3 शहरों में स्थित है। ये स्टार्टअप भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 669 जिलों में विस्तारित हैं।
- 31 मार्च 2023 तक भारत में 108 यूनिकॉर्न की संख्या हो गयी थी जिसका कुल बाजार मूल्य $340.80 बिलियन अनुमानित है। यूनिकॉर्न की कुल संख्या में से $93 बिलियन के कुल बाजार मूल्य के साथ 44 यूनिकॉर्न की शुरुआत 2021 में, जबकि $27 बिलियन के कुल बाजार मूल्य के साथ 21 यूनिकॉर्न की शुरुआत 2022 में हुई।

आगे की राहः

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गतिशील परिदृश्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, आर्थिक हितों तथा भू-राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिबद्धता दिखाती है जो दोनों देशों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आरआईएसई एक्सेलेरेटर न केवल राजनयिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयासों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

3 भुगतान संतुलन (बीओपी) में सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (Q1) के लिए भारत के भुगतान संतुलन (BoP) में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। भारत में चालू खाता घाटा (CAD) पहली तिमाही (Q1) 2022-23 में 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2.1%) से घटकर पहली तिमाही (Q1) 2023-24 में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भुगतान संतुलन में सुधार का कारणः

- चालू खाते के घाटे में कमी
- नेट सेवाओं के अधिशेष में वृद्धि
- आय खाते पर शुद्ध व्यय कम होना
- शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि

भुगतान-संतुलन-के-तत्वः

चालू खाताः

- चालू खाता देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्वाह तथा बहिर्वाह को कवर करता है। यह खाता कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के संबंध में की गई सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों को कवर करता है।
- इसमें इंजीनियरिंग, पर्यटन, परिवहन, व्यावसायिक सेवाओं, स्टॉक तथा पेटेंट और कॉपीराइट से रॉयल्टी से प्राप्तियां भी शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत एकपक्षीय स्थानांतरण भी आते हैं।

पूंजी खाताः

- देशों के बीच सभी पूंजी लेनदेन की देखरेख पूंजी खाते के माध्यम से की जाती है। पूंजीगत लेनदेन में भूमि और संपत्तियों जैसी परिसंपत्तियों (गैर-वित्तीय) की खरीद तथा बिक्री शामिल है।
- पूंजी खाते में बाहर/दूसरे देश में जाने वाले प्रवासियों द्वारा करों का प्रवाह, अचल संपत्तियों की खरीद और बिक्री आदि भी शामिल है।

भुगतान संतुलन के मुख्य घटकः

- **ऋण और उधार**- इसमें विदेशों में स्थित निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी प्रकार के ऋण शामिल हैं।
- **निवेश**- ये अनिवासियों द्वारा कॉर्पोरेट शेयरों में निवेश किया गया धन है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार**- विनिमय दर की निगरानी और नियंत्रण के लिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार पूंजी खाते पर प्रभाव डालते हैं।
- कभी-कभी भुगतान संतुलन संतुलित नहीं रहता। यह असंतुलन बीओपी में त्रुटियों और चूक के रूप में दिखाया जाता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने में देश की असमर्थता को दर्शाता है।

भुगतान संतुलन का महत्त्वः

- यह एक निश्चित अवधि के लिए सेवाओं और वस्तुओं के सभी आयात व निर्यात के लेनदेन की निगरानी करता है।
- यह सरकार को किसी विशेष उद्योग की निर्यात वृद्धि क्षमता का विश्लेषण करने और इसे बनाए रखने के लिए नीतियां बनाने में मदद करता है।
- यह सरकार को आयात और निर्यात शुल्कों की विभिन्न श्रेणियों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सरकार को आयात को हतोत्साहित करने और निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिर्भरता के लिए कर बढाने और घटाने के लिए प्रेरित करता है।

आगे की राहः

भुगतान संतुलन में सुधार भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद को दर्शाता है। हालाँकि वर्तमान में एकतरफा हस्तांतरण जैसे कई क्षेत्रों में गिरावट आई है, लेकिन अनुमान है कि आने वाली तिमाही में देश को भुगतान

संतुलन के संबंध में और अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

4 ग्लोबल हेल्थकेयर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में WHO ने ग्लोबल हेल्थकेयर रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसकी रिपोर्ट में सदस्य देशों के स्वास्थ्य आँकड़ों को विस्तृत रूप से शामिल किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- भारत वर्तमान समय में अपनी 1.42 बिलियन की आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक 2 बिलियन वर्ग फुट स्वास्थ्य देखभाल स्थान की कमी का सामना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रति 1000 लोगों पर 3 बिस्तरों के अनुपात की सिफारिश करता है।
- वर्तमान समय में भारत में 1000 जनसंख्या अनुपात पर केवल 1.3 बिस्तर उपलब्ध हैं अर्थात प्रति 1000 पर 1.7 बिस्तरों की कमी है। इसका मतलब है कि भारत को अतिरिक्त 2.4 मिलियन बिस्तरों की आवश्यकता है। यह कमी भारत के स्वास्थ्य सेवा बाजार की तीव्र वृद्धि को देखते हुए चिंताजनक है क्योंकि इसका बजट 2012 के $73 बिलियन की तुलना में 2022 में 372 बिलियन डॉलर होने पहुंचने के बाद भी पर्याप्त बिस्तरों की कमी देखी गई।
- भारत के स्वास्थ्य सेवा बाजार में अस्पताल उद्योग का हिस्सा 80% है।
- रिपोर्ट में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान समय में भारत में अनुमानित 70,000 अस्पताल हैं जिनमें से निजी क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 63% है।
- स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में कमी के बावजूद, भारत स्वास्थ्य सेवा पर्यटन के लिए एक आकर्षक बाजार बना हुआ है। 2014-2019 के बीच मेडिकल वीजा पर विदेशी पर्यटकों का प्रवाह 30% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है।
- इसके अतिरिक्त भारत में चिकित्सा प्रक्रियाओं की लागत इसके एशियाई लोगों की तुलना में काफी कम है जो इसे चिकित्सा पर्यटकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से संबंधित मुद्दे:

- भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत, एकल परिवार प्रणाली के बढ़ने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए नर्सिंग और दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता, गरीबों पर उच्च वित्तीय बोझ, नई बीमारियों का बढ़ता बोझ तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए अपर्याप्त धन के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों में लापरवाही शामिल हैं।

भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से संबंधित प्रमुख योजनाएँ:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में इसके दो उप-मिशन 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)' शामिल हैं। मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, प्रजनन-मातृ नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) व संचारी और गैर-संचारी रोग से सम्बंधित देखभाल शामिल हैं।
- **आयुष्मान भारत:** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना करना जो व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत करना जो लोगों को बीमा प्रदान करेगा।
- **जन औषधि केंद्र:** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र की स्थापना जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है जो कम कीमत पर उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।

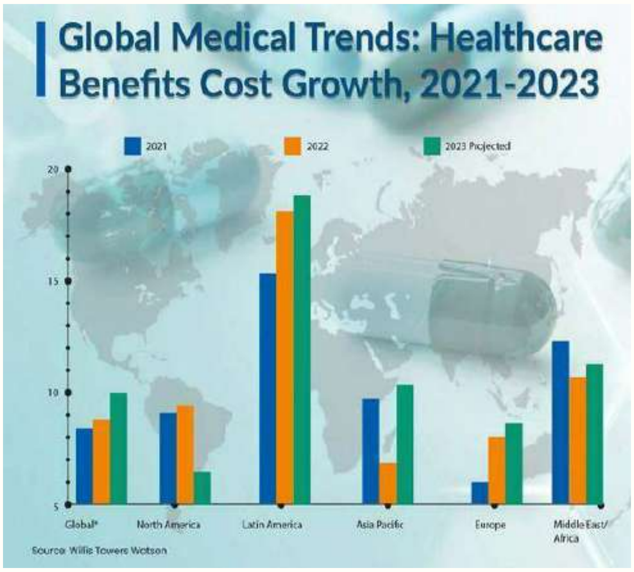

आगे की राह:

इस कमी को दूर करने और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार करने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीति का लक्ष्य सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाना है। स्वास्थ्य सेवा के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 2.1% हो गया है। उम्मीद है कि देश जिस तरह से स्वास्थ्य सुवि की कमी का सामना कर रहा है, उसे WHO की सिफारिश के अनुसार बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाएगा।

5 बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (मार्च 2022-फरवरी 2023) के आधार पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 (दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23) जारी किया।

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की विस्तृत रिपोर्ट:

दूध उत्पादन:

- 2022-23 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 2018-19 के 187.75 मिलियन टन में 22.81% की वृद्धि दिखाता है।
- 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था जिसकी कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% थी। इसके बाद राजस्थान (14.44%), मध्य प्रदेश (8.73%), गुजरात (7.49%), और आंध्र प्रदेश (6.70%) का स्थान रहा।

अंडा उत्पादन:

- देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन अनुमानित है जो 2018-19 के दौरान 103.80 बिलियन संख्याओं की तुलना में 2022-23 में 33.31% की वृद्धि दिखाता है।
- अंडा उत्पादन में प्रमुख योगदान आंध्र प्रदेश का रहा है जिसकी हिस्सेदारी कुल अंडा उत्पादन में 20.13% है। इसके बाद तमिलनाडु (15.58%), तेलंगाना (12.77%), पश्चिम बंगाल (9.94%) और कर्नाटक (6.51%) का स्थान रहा है।

मांस उत्पादन:

- 2022-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन अनुमानित है जो 2018-19 के 8.11 मिलियन टन की तुलना में 20.39% की वृद्धि दिखाता है।
- कुल मांस उत्पादन में 12.20% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है जिसके बाद पश्चिम बंगाल (11.93%), महाराष्ट्र (11.50%), आंध्र प्रदेश (11.20%) और तेलंगाना (11. 06%) का स्थान रहा है।

ऊन उत्पादन:

- 2022-23 के दौरान देश में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है जो 2018-19 के 40.42 मिलियन किलोग्राम की तुलना में 16.84% की गिरावट दिखाता है।
- कुल ऊन उत्पादन में 47.98% की हिस्सेदारी के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है जिसके बाद जम्मू और कश्मीर (22.55%), गुजरात (6.01%), महाराष्ट्र (4.73%) तथा हिमाचल प्रदेश (4. 27%) का स्थान रहा है।

आगे की राह:

देश में दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान देश भर में तीन मौसमों यानी गर्मी (मार्च-जून), बरसात (जुलाई-अक्टूबर) और सर्दी (नवंबर-फरवरी) के दौरान किये जाने वाले वार्षिक एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) के परिणामों के आधार पर लगाया जाता है। इस नतीजे से सरकार को दूध, अंडा, मांस और ऊन क्षेत्र से जुड़ी भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। इससे भविष्य की तैयारियों के लिए आवश्यक रणनीति बनाया जा सकेगा।

6 इंवेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष माधबी पुरी ने इंवेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म सभी स्टॉक एक्सचेंज जैसे 'बीएसई, एनएसई, एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया' द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

इंवेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म के बारे में:

- नाम से ही पता चलता है कि यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। यह प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग सदस्यों को किसी भी धोखाधड़ी और तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में जोखिम को कम करेगा।

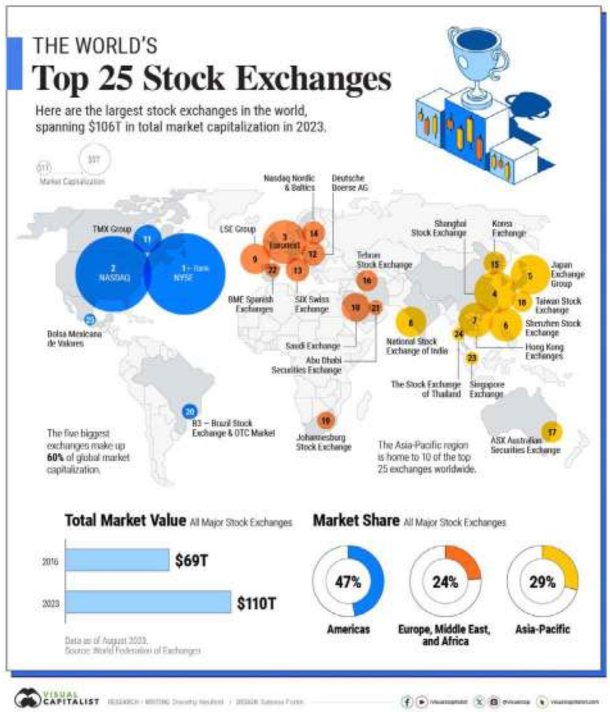

यह कैसे संचालित होगा?

- इसका उद्देश्य निवेशकों को तकनीकी गड़बड़ियों या अप्रत्याशित रुकावटों के मामले में आईआरआरए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी खुली स्थिति को बंद करने और लंबित ऑर्डर को रद्द करने का अवसर प्रदान करना है जो ट्रेडिंग सदस्य की साइट को पहुंच से बाहर कर देता है।

प्लेटफार्म का महत्त्व:

- वे निवेशक जो आईआरआरए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए अधिकृत हैं, वे सभी स्टॉक एक्सचेंजों में लंबित ऑर्डर देखकर और रद्द कर सकते हैं, ऑर्डर बुक बना सकते हैं तथा उन ऑर्डर को रद्द कर सकते हैं जो एक्सचेंजों में लंबित हैं। प्लेटफॉर्म एल्गो ट्रेडिंग और संस्थागत ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है। व्यापार के बदले व्यापार के

आधार पर निपटान के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियां स्क्वायर-ऑफ के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।

प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने की प्रक्रिया:

- प्लेटफॉर्म तक पहुंच एक नए इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (आईबीटी) वेब यूआरएल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ट्रेडिंग सदस्य को अपना खाता आईआरआरए प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना होगा। एक ट्रेडिंग सदस्य बाजार के बाद के सत्र की शुरुआत से पहले आईआरआरए प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होने के लिए ईमेल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज को सूचित कर सकता है।
- ट्रेडिंग सदस्य द्वारा रिवर्स माइग्रेशन का भी अनुरोध किया जाएगा ताकि आईआरआरए सिस्टम सेवाएं बंद हो जाएं जिससे ट्रेडिंग सदस्य मूल ट्रेडिंग सिस्टम से व्यवसाय फिर से शुरू कर सके। एक कारोबारी दिन के दौरान केवल एक रिवर्स माइग्रेशन की अनुमति होगी।

आगे की राह:

यह प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में सभी निवेशकों को सुरक्षा जाल और अंतिम विकल्प प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज कनेक्टिविटी, ऑर्डर फ्लो और सोशल मीडिया पोस्ट जैसे मापदंडों की निगरानी करने में भी सक्षम होंगे तथा आईआरआरए सेवा को सक्षम करने की पहल भी कर सकेंगे।

7 डिजिटल भुगतान पर आरबीआई का पेपर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारत में नकद बनाम डिजिटल भुगतान लेनदेन: मुद्रा मांग विरोधाभास को डिकोड करना' शीर्षक से प्रकाशित होने वाले एक पेपर में, रिजर्व बैंक ने कोविड-19 द्वारा उत्प्रेरित डिजिटल भुगतान में वृद्धि को बनाए रखने में साइबर सुरक्षा, ग्राहक सुरक्षा और लागत-प्रभावशीलता के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

पेपर के मुख्य निष्कर्ष:

- पेपर में कहा गया है कि नकदी के लेनदेन उपयोग में गिरावट दर्ज की गई है। डिजिटल भुगतान के तरीके धीरे-धीरे नकदी लेनदेन की जगह ले रहे हैं, जबकि मूल्य के भंडार के रूप में नकदी की भूमिका बनी हुई है तथा भुगतान के डिजिटल तरीकों की ओर बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। कोविड-19 महामारी ने इस संक्रमण को तेज करने में भूमिका निभाई है।

मुद्रा मांग पर महामारी का प्रभाव:

- वैश्विक रुझानों के समान, महामारी ने भारत में मुद्रा की मांग में अस्थायी वृद्धि को प्रेरित किया। यह वृद्धि मुख्य रूप से एहतियाती उपायों और अनिश्चित समय के दौरान मूल्य के भंडार के रूप में नकदी की धारणा के कारण हुई।

डिजिटल भुगतान में गति बनाए रखना:

महामारी द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान की गति को बनाए रखने के लिए पेपर विभिन्न मोर्चों पर ठोस प्रयासों पर जोर देता है:

लागत-प्रभावशीलता:

- डिजिटल भुगतान मोड और प्रासंगिक स्वीकृति बुनियादी ढांचे की लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें मांग पक्ष (उपभोक्ता) और आपूर्ति पक्ष (व्यापारी व मध्यस्थ) दोनों पर विचार करना शामिल है।

सार्वभौमिक पहुंच:

- डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख समर्थकों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को निर्देशित किया जाना चाहिए।

साइबर सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा:

- साइबर सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए डिजिटल लेनदेन में विश्वास बनाने तथा बनाए रखने में उनके महत्त्व को रेखांकित करती है। जैसे-जैसे व्यक्ति और व्यवसाय डिजिटल भुगतान में संलग्न हो रहे हैं, साइबर खतरों से बचाव तथा ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि हो गया है।

आगे की राह:

सरकारी पहल, इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच तथा ई-कॉमर्स के बढ़ने के कारण हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में काफी वृद्धि हुई है। इसके लाभों को ध्यान रखते हुए ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना समय की मांग है।

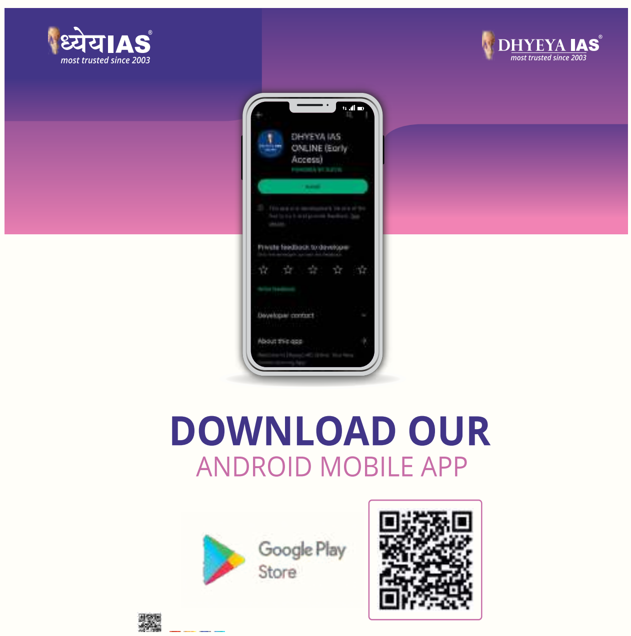

विविध मुद्दे

1 रेड सैंडर्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत को लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के तहत रेड सैंडर्स के लिए महत्त्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा (RST) से हटा दिया गया है।

सीआईटीईएस आरएसटी प्रक्रिया के बारे में:

- सीआईटीईएस आरएसटी प्रक्रिया उन देशों पर व्यापार निलंबन के रूप में अनुशासनात्मक कार्यवाही को सक्षम बनाती है जो अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं।
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीआईटीईएस स्थायी समिति किसी देश से किसी प्रजाति के निर्यात पर जांच करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कन्वेंशन ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं।
- भारत में वर्ष 2004 में रेड सैंडर्स के लकड़ी के अवैध व्यापार तथा कटाई के कारण इसके व्यापार को निलंबित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत के अनुपालन और रिपोर्टिंग के आधार पर रेड सैंडर्स को महत्त्वपूर्ण व्यापार समीक्षा से हटा दिया गया है।

रेड सैंडर्स के बारे में:

- रेड सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटालिनस) एक उच्च बाजार मूल्य वाला पेड़ है जो आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाया जाता है। इस प्रजाति को अवैध कटाई और तस्करी के खतरों का सामना करना पड़ता है जिससे प्राकृतिक जंगलों से उनकी कमी हो गई है।
- अपने समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए प्रसिद्ध रेड सैंडर्स की पूरे एशिया में, विशेष रूप से चीन और जापान में सौंदर्य प्रसाधन व औषधीय उत्पादों के साथ-साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प और संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए मांग अधिक है।

सुरक्षा की स्थिति:

- IUCN लाल सूची: लुप्तप्राय
- उद्धरण: परिशिष्ट II
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची IV

सीआईटीईएस के बारे में:

- सीआईटीईएस (जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों तथा पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो।
- इसे 1963 में IUCN (विश्व संरक्षण संघ) के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था। यह जुलाई 1975 में अस्तित्व में आया था।
- हालाँकि सीआईटीईएस पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सीआईटीईएस का सचिवालय यूएनईपी द्वारा प्रशासित है और जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।
- सीआईटीईएस में पार्टियों का सम्मेलन कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जिसमें इसके सभी सदस्य शामिल हैं। भारत 1976 से सीआईटीईएस का एक पक्षकार रहा है।

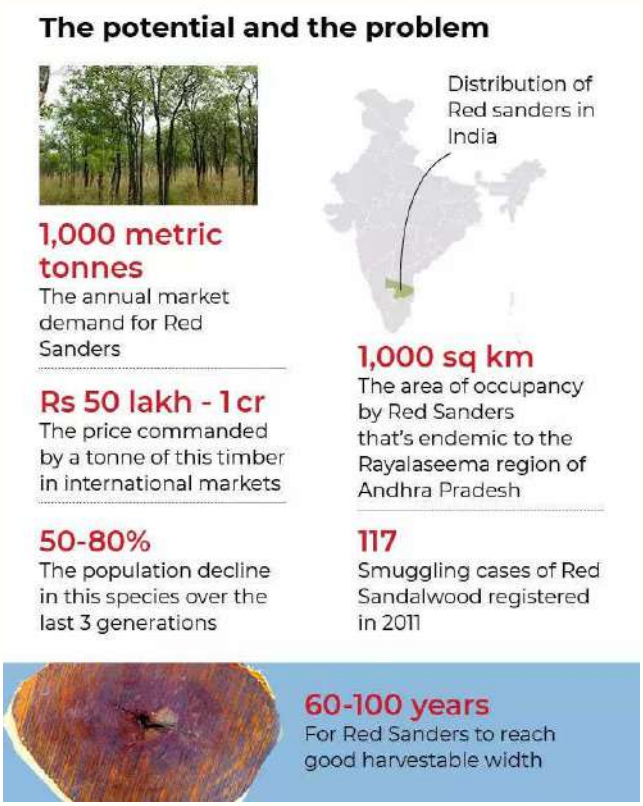

आगे की राह:

आरएसटी प्रक्रिया से लाल चंदन को हटाने से लाल चंदन उगाने वाले किसानों को बागानों से लाल चंदन की खेती और निर्यात के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को स्थायी आय के स्रोत के रूप में अधिक से अधिक लाल चंदन के पेड़ उगाने के लिए प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

2 बोईता बंदना उत्सव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बोईता बंदना ओडिशा के गौरवशाली समुद्री अतीत का उत्सव मनाने के लिए समुद्र में सजी-धजी नाव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन

किया, साथ ही पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय तथा जल उपचार संयंत्र और पारादीप में अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन प्रणाली की आधारशिला भी रखी।

बोईता बंदना क्या है?

- ओडिशा के गौरवशाली समुद्री अतीत का जश्न मनाने के लिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोईता बंदना मनाया जाता है।
- उड़िया नाविक ओडिशा में उत्पादित सामानों को सुदूर देशों जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और इंडोनेशिया के बाली द्वीप में बेचते थे।
- वे मसाले, हाथी दांत की वस्तुएं और अन्य सामान लाते थे तथा उन्हें कटक में महानदी के तट पर बेचते थे।
- साधवों (पारंपरिक व्यापारी नाविकों) के पोशाक में लड़के नाव में सवार होते थे।
- साधवनी पोशाक (सधवों की पत्नियाँ) में लड़कियाँ उन्हें विदा करती थीं। नियत जगह पर अच्छे व्यापार और सुरक्षित वापसी की कामना करती थीं।
- बोईता बंदना हमारे गौरवशाली अतीत की याद में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्यौहार है। प्राचीन काल से मनाया जाने वाला यह त्यौहार ओडिशा के समुद्री व्यापार की समृद्धि का प्रतीक है।
- यह ओडिशा के लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक चेतना को भी उजागर करता है। वैश्विक मानकों के अनुसार बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ कार्य करने के लिए बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।

आगे की राह:

भारत के कुल व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत मात्रा के संदर्भ में और 65 प्रतिशत मूल्य के संदर्भ में परिवहन समुद्री माध्यम से किया जाता है। सागरमाला परियोजना इस दिशा में एक सराहनीय कदम है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार 'समृद्धि के लिए बंदरगाह' और 'प्रगति के लिए बंदरगाह' के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु काम कर रही है। ऐसे त्यौहार लोगों को समुद्री परिवहन के प्रति आकर्षित करते हैं।

3 महिमा धर्म और संत भीमा भोई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'संत कवि भीमा भोई और महिमा पंथ की विरासत' विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे संत बलराम दास के लक्ष्मी पुराण और संत कवि भीमा भोई के दर्शन तथा कविताओं ने समाज में सबसे कमजोर लोगों की समस्याओं को संबोधित किया।

महिमा पंथ के बारे में:

- महिमा धर्म (जिसे महिमा पंथ के नाम से भी जाना जाता है) एक हिंदू धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय है जो मुख्य रूप से ओडिशा और पड़ोसी राज्यों में प्रचलित है।
- इसका उदय 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण काल के दौरान हुआ।
- इसके संस्थापक महिमा गोसाई ने 1826 के आसपास पुरी में इस धर्म की स्थापना की जिसकी शिक्षाएँ पूरे ओडिशा और बाद में अन्य भारतीय राज्यों में फैल गईं।
- महिमा गोसाई को रेत पर सोने की आदत के कारण "धूलिया गोसाई" के नाम से भी जाना जाता है।
- महिमा गोसाई के शिष्य भीमा भोई ने अपने साहित्यिक कार्यों और शिक्षाओं के माध्यम से महिमा धर्म के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद:** महिमा धर्म एकेश्वरवादी है जो अलेखा नामक एकल, निराकार और सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास की वकालत करता है।
- यह शुद्ध अद्वैतवाद पर जोर देता है, जहां ईश्वर को सर्वोच्च आत्मा और सृजन के स्रोत के रूप में देखा जाता है।
- यह पंथ मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का दृढ़ता से विरोध करता है।
- **वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत:** यह सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड को एक ही परिवार के रूप में देखता है। यह निःस्वार्थता और सामान्य कल्याण के लोकाचार को बढ़ावा देता है।
- **विशुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद:** यह पंथ एक ऐसे दर्शन का पालन करता है जो भक्ति और ज्ञान को जोड़ता है तथा परम सत्य व परम ब्रह्म के प्रति शुद्ध मन के आकर्षण पर जोर देता है।

भीमा भोई के बारे में:

- भीमा भोई भारत के ओडिशा राज्य के 19वीं सदी के संत, रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक थे।
- उनका जन्म 1850 में मधुपुर, रायराखोल (ओडिशा) में हुआ था।
- उन्हें सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है।
- वह "कोंध" जनजाति से थे।
- चेचक के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई।
- धार्मिक ग्रंथों को सुनकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
- उन्होंने एकेश्वर ब्रह्मवाद की शिक्षा दी अर्थात एक ईश्वर में विश्वास करना।
- उन्होंने सोनपुर के खलियापाली में एक आश्रम की स्थापना की।
- उनकी मृत्यु 1895 में खलियापाली में हुई।
- उनकी कविता में रहस्यवाद, संगीतात्मकता और बोलचाल की शैली की विशेषता मिलती है।
- उन्होंने संबलपुरी बोली को अपनाया। उनकी शिक्षाएँ महिमा धर्म के अनुयायियों को प्रभावित करती रहती हैं।

आगे की राह:

यह आंदोलन भारत में सामाजिक मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली ताकत बना जिसने जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। महिमा धर्म प्रेम, करुणा और शांति जैसे गुणों को विकसित करने पर महत्त्व देता है। यह गृहस्थों के लिए नैतिक आचरण निर्धारित करता है, सादगी, नैतिक, ब्रह्म दर्शन और त्रिविध शरण जैसी धार्मिक प्रथाओं पर जोर देता है।

4 नम्मा कंबाला भैंस दौड़ प्रतिस्पर्धा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नम्मा कंबाला भैंस दौड़ इस साल बेंगलुरु में पहली बार आयोजित हुआ। तटीय कर्नाटक से शुरू होकर, तुलुनाडु की स्थानीय संस्कृति में गहराई से रची-बसी पारंपरिक भैंस दौड़ परंपरा और उत्साह के अनूठे मिश्रण का रूप है जो प्रतिभागियों और दर्शकों को समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है।

नम्मा कंबाला भैंस दौड़ प्रतिस्पर्धा क्या है?

- यह पारंपरिक स्लश ट्रैक भैंस दौड़ है जो क्षेत्र के ग्रामीण लोगों के मनोरंजन के लिए कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।
- कंबाला के लिए कीचड़युक्त/दलदली धान के खेत के ट्रैक का उपयोग किया जाता है।
- खेल का मौसम आम तौर पर नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है।
- कंबाला दौड़ भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है।
- इसे पारंपरिक रूप से दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक के उडुपी तथा केरल के कासरगोड के तटीय क्षेत्रों में स्थानीय तुलुवा जमींदारों और परिवारों द्वारा समर्थित किया जाता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 2014 में कंबाला पर प्रतिबंध लगा दिया।
- कर्नाटक ने 2017 में पशु क्रूरता निवारण (कर्नाटक संशोधन) अध्यादेश के साथ प्रतिबंध को रद्द कर दिया।
- मुकदमे के समाधान के बाद, पशु क्रूरता निवारण (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2018 ने कंबाला को वैध बना दिया।

कंबाला दौड़ के पीछे ऐतिहासिक संदर्भ:

- पारंपरिक कंबाला गैर-प्रतिस्पर्धी था।
- आधुनिक कंबाला में प्रतिस्पर्धा आमतौर पर भैंसों के दो जोड़े के बीच होती है।
- किसान अपनी भैंसों को बीमारी से बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देने हेतु वंडारो और चोराडी जैसी जगहों पर दौड़ लगाते हैं।
- परंपरागत रूप से, भैंसों की विजेता जोड़ी को नारियल और केले दिए जाते थे, वहीं आज के विजेताओं को सोने व चांदी के सिक्के मिलते हैं।
- कंबाला में भारी ग्रामीण भीड़ उमड़ती रही है, जैसा कि पिछली तीन शताब्दियों से होता आ रहा है। लोग भैंसों पर दांव लगाते हैं और 20,000 से अधिक लोगों को एक सुव्यवस्थित कंबाला में दौड़ पूरी करने के लिए भैंसों को प्रोत्साहित करते देखा जा सकता है।
- रात्रि दौड़ कई क्षेत्रों में फ्लडलाइट के तहत आयोजित की जाती हैं।

कंबाला के विभिन्न प्रकार:

- पुकेरे कंबाला
- बारे कंबाला
- कोरी कंबाला
- अरसु कंबाला
- देवेरे कंबाला
- बाले कंबाला

जल्लीकट्टू और कंबाला में क्या अंतर है?

- कंबाला दौड़ भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है।
- नवंबर से मार्च तक, फसल उत्सव के हिस्से के रूप में यह दौड़ आयोजित की जाती है।
- जल्लीकट्टू तमिलनाडु में आयोजित होने वाला 2,000 साल पुराना खेल है जिसमें एक जंगली बैल को लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है।
- प्रतिभागी बैल के कूबड़ को पकड़कर उस पर सवारी करने या उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यदि वे असफल होते हैं, तो बैल के मालिक को पुरस्कार मिलता है।
- 'जल्लीकट्टू' शब्द 'कैली' (सिक्के) और 'कट्टू' (टाई) से बना है जिसका तात्पर्य बैल के सींगों से बंधे सिक्कों के बंडल से है।

आगे की राह:

यह खेल कृषि का जश्न मनाने और उसका सम्मान करने से संबंधित है। यह भोजन देने वाली प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कुछ कृषक अपने पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देने हेतु अपनी भैंसों की दौड़ कराते हैं। मानवता के सबसे बुनियादी स्तर पर इस तरह के खेल ऊर्जा को प्रसारित करने के महान आउटलेट हैं जो प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देने, सामुदायिक संबंधों को बनाने और मजबूत करने में व्यक्त किया जाता है।

5 प्राचीन काल में पुरूषों के साथ महिलायें भी शिकार में थी संलग्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक नए अध्ययन में यह तर्क दिया गया है कि पुरापाषाण काल में महिलाएं न केवल शिकार करती थीं, बल्कि शिकार में उन्हें कुछ जैविक फायदे भी थे। ये निष्कर्ष पुराने जमाने के सिद्धांत को खारिज करते हैं कि केवल पुरूष ही शिकारी थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस के 2020 के एक अध्ययन में अमेरिका के रिकॉर्ड का विश्लेषण करते समय यह पाया गया कि 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत शिकारी महिलाएं थीं।

अध्ययन के प्रमुख बिन्दु:

- लंबे समय तक इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में कहा गया कि हजारों साल पहले पुरुष जानवरों का शिकार करते थे, जबकि महिलाएं फल और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती थीं तथा अपने बच्चों का पालन-पोषण करती थीं। आम तौर पर स्वीकृत इस दृष्टिकोण को 'मैन, द हंटर' के नाम से भी जाना जाता था।

- टीम ने इस सवाल की जांच की कि क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक अंतर महिलाओं को शिकार करने से रोकते हैं। उन्होंने पाया कि गति और शक्ति की आवश्यकता वाली गतिविधियों (जैसे दौड़ना और हथियारों को चलाने या फेंकने) में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक योग्य माना जाता था, लेकिन हाल ही में किये गये अध्ययन से पता चलता है कि शिकार करने में महिलायें भी पुरुषों की तुलना में कम नहीं थी अर्थात प्राचीन काल में शिकार के लिए महिला-पुरूष दोनों एक एक दूसरे के लिए आवश्यक थे।
- टीम ने उस लाभ को प्रदान करने में एक प्रमुख घटक के रूप में हार्मोन एस्ट्रोजन की भूमिका पर प्रकाश डाला जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक प्रमुख है। एस्ट्रोजन वसा चयापचय को बढ़ा सकता है जो मांसपेशियों को लंबे समय तक चलने वाला ऊर्जा स्रोत देता है और मांसपेशियों के टूटने को नियंत्रित कर सकता है जिससे मांसपेशियों को खराब होने से रोका जा सकता है। यह हार्मोन शिकार करने में बहुत सहायक होता है।
- आधुनिक शरीर विज्ञान प्राचीन लोगों के कंकाल अवशेषों को एकत्रित करके उस पर अनुसंधान करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच आघात के पैटर्न में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे समान गतिविधियां करते रहे हैं। पुरापाषाण युग के दौरान अधिकांश लोग छोटे समूहों में रहते थे।

आगे की राह:

शोध पत्र के अनुसार, 3 मिलियन वर्षों तक पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अपने समुदायों के लिए निर्वाह इकट्ठा करने में भाग लिया क्योंकि शिकार करके प्राप्त मांस पर ही निर्भरता व्याप्त थी। यह सिद्धांत भविष्य के अन्य शोधों का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि प्राचीन काल के रहस्यों को समझा जा सके।

6 रास महोत्सव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप असम के माजुली में वार्षिक रास महोत्सव या रास लीला उत्सव मनाया गया। वार्षिक रास महोत्सव में माजुली के इस दिव्य उत्सव के दौरान भगवान कृष्ण की लीला पर आधारित मंचन होता है।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ:

- **भाओना:** स्थानीय लोगों ने भाओना को परफॉर्म किया जो पंद्रहवीं या सोलहवीं शताब्दी में प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किये गये नाटक का एक पारंपरिक रूप है। इसमें कलाकार विभिन्न पौराणिक चरित्रों को उत्साहपूर्वक चित्रित करते हैं और कथाओं को जीवंत बनाते हैं। रास महोत्सव में औनियाती, दखिनपत, उत्तर कमलाबाड़ी, नतुन कमलाबाड़ी और गार्मुर सत्र जैसे प्रमुख मठों में आयोजित मनमोहक प्रदर्शन देखने के लिए हजारों लोग एकत्र होते हैं।

- **रास लीला:** सदियों से माजुली के लोग इस अवसर पर रास लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें प्रतिभागी भारतीय पौराणिक पात्रों की तरह कपड़े पहनते हैं। स्थानीय रूप से तैयार किए गए मुखौटे नृत्य नाटकों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो विभिन्न पौराणिक प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्वजनिक प्रशंसा के लिए पौराणिक पात्रों की मूर्तियाँ भी स्थापित की जाती हैं।
- मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने रास समितियों को वित्तीय सहायता दी है। समारोह को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में हर साल लगभग 3,000 आयोजकों को 25,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाती है। यह असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आगे की राह:

रासलीला कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी नृत्य रूपों में एक लोकप्रिय विषय रहा है। रासलीला उत्तर प्रदेश के वृन्दावन के क्षेत्रों में लोक रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है। असम में रास महोत्सव के दौरान इस साल कई हजार भक्त पवित्र मंदिरों और सत्रों में शामिल हुए जिसमें माजुली, नलबाड़ी और हाउली का रास महोत्सव उल्लेखनीय रहा।

7 भारतीय लघु चित्रकला परंपरा में बी. एन. गोस्वामी का योगदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय कला इतिहासकार ब्रिजिंदर नाथ गोस्वामी (जो 'भारतीय लघु चित्रकला परंपरा' पर अपनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं) का 90 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में निधन हो गया। भारतीय लघु चित्रकला परंपरा मुख्य रूप से दो प्रकार (पहाड़ी चित्रकला और डेक्कन पेंटिंग) की होती है।

लघुचित्र क्या होती है?

- लघु चित्रकला, कला का एक जटिल रूप है जिसमें छोटे पैमाने पर अत्यधिक विस्तृत पेंटिंग शामिल होती है। चमकीले रंग, जटिल

पैटर्न और विस्तृत विवरण का उपयोग इसकी विशेषता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

- लघु चित्रकला परंपरा की जड़ें पाल राजवंश में मिलती हैं जिन्होंने 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल और बिहार पर शासन किया था।
- इस युग के दौरान पेंटिंग बौद्ध और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के चित्रण के रूप में मौजूद थीं।
- 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच कागज के प्रचलन में आने तक चित्र ताड़ के पत्ते पर बनाए जाते थे।
- लघु चित्रों की परंपरा को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य दरबारी चित्रकला के रूप में सर्वोत्कृष्ट रूप में देखा गया।
- औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल लघुचित्र की परंपरा में गिरावट शुरू हुई।
- इससे कुशल लघुचित्रकारों का राजस्थान के राजसी दरबारों और उत्तर भारत के निचले हिमालयी पहाड़ी राज्यों सहित पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवास होना शुरू हुआ।
- हिमाचल प्रदेश, जम्मू और टेहरी-गढ़वाल जैसे स्थानों में लघु चित्रकला की एक नई परंपरा ने जन्म लिया जिसे पहाड़ी चित्रकला के रूप में जाना जाने लगा। राजस्थान में भी लघु चित्रकला के विभिन्न स्कूलों का उदय हुआ।

आधुनिक भारत के दौरान लघु चित्रकला की स्थितिः

- 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच दक्कन क्षेत्र में लघु चित्रकला विकसित हुई।
- यह 1520 में बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद उभरा।
- डेक्कन पेंटिंग के रूप में इसे जाना गया। यह शैली शुरू में मुगल प्रभावों से स्वतंत्र विकसित हुई जो बाद में यूरोपीय, ईरानी और तुर्की प्रभावों से प्रेरित हुई।

आगे की राहः

पहाड़ी चित्रकला में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों को दर्शाया गया है। महाभारत, रामायण, पुराण और गीता जैसे धार्मिक महाकाव्यों पर आधारित विस्तृत चित्र अक्सर इस शैली में चित्रित किए गए थे। दक्कनी लघु चित्रों में पवित्र कुरान और सूरह के पाठ की रोशनी तथा सजावट का प्रदर्शन किया गया। विश्व कला समुदाय की रिपोर्ट के अनुसार, स्वदेशी कला रूपों व रोमांटिक तत्वों को बाद में इस कला में मिला दिया गया।

ब्रेन बूस्टर

ग्रीनवॉशिंग

चर्चा में क्यों ?

एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल फॉर इंडिया (एएससीआई) ने हाल ही में विज्ञापनों को ग्रीनवॉशिंग से मुक्त बनाने के लिए विज्ञापन में हरित/पर्यावरण अनुकूल दावों के संबंध में मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं।

ग्रीनवॉशिंग के बारे में

- ग्रीनवॉशिंग वह प्रक्रिया है जब कोई संगठन वास्तव में अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की तुलना में खुद को पर्यावरण के अनुकूल विपणन करने पर अधिक समय और पैसा खर्च करता है।
- यह एक कपटपूर्ण विपणन कार्य है जिसका उपयोग कंपनियां अपने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए करती हैं।
- ग्रीनवॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार 1986 में जे वेस्टरवेल्ड द्वारा किया गया था, जो एक अमेरिकी पर्यावरणविद् और शोधकर्ता थे।

ग्रीनवॉशिंग से उत्पन्न मुद्दे

- ग्रीनवॉशिंग किसी भी संगठन की छवि को बढ़ावा देने में मदद करती है, लेकिन वास्तव में वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ नहीं करते हैं।
- यह विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है जैसे अस्पष्टता, यानी प्रक्रियाओं और सामग्रियों को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है और फाइबिंग, जिसमें हरित, नेट-शून्य, पर्यावरण अनुकूल आदि झूठे दावे किए जाते हैं।
- विशाल पेट्रो-उत्पादक, एफएमसीजी कंपनियों सहित कई बहुराष्ट्रीय निगमों को ग्रीनवॉशिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा है।

ग्रीनवॉशिंग से संबंधित पहल

- अंतर्राष्ट्रीय सततता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) की कंपनियों के लिए समान सतत और जलवायु मानकों का 2024 से दुनिया भर में पालन किया जाएगा।
- जलवायु-संबंधी वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग में सुधार के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की जलवायु-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण व्यवस्था।
- एफएसबी एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है (भारत इसका सदस्य देश है) जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उसके बारे में अनुशंसाएँ करता है।
- आरबीआई द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (जीएफआईएन) के ग्रीनवॉशिंग टेकस्पिरिट में शामिल होने का निर्णय।

प्रस्तावित मसौदा दिशानिर्देश

- पर्यावरण-अनुकूल, सतत और ग्रह-अनुकूल जैसे दावों को उच्च स्तर की पुष्टि द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, विज्ञापनदाताओं को यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि पर्यावरण संबंधी दावा संपूर्ण उत्पाद, पैकेजिंग या सेवा को संदर्भित करता है या नहीं।
- उत्पाद के कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकल करने योग्य, गैर विषैले, मुक्त होने के दावों के लिए, विज्ञापनदाताओं को उन पहलुओं को समक्ष करना चाहिए जिनके लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं।
- इसके अलावा इन दावों को 'विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य' द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ताकि यह इंगित किया जा सके कि उत्पाद निपटान के बाद उचित रूप से कम समय के भीतर नष्ट हो जाएगा।
- विज्ञापनदाताओं को यह भी निर्दिष्ट करना चाहिए कि उत्पाद ऐसे तत्वों से मुक्त है जो पर्यावरणीय खतरों का कारण बन सकते हैं।

निष्कर्ष

- ग्रीनवॉशिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने में हासिल की गई प्रगति की गलत धारणा देता है, पृथ्वी को और अधिक आपदाओं की ओर ले जाता है और साथ ही जवाबदेहीता से बचने वाले लापरवाह व्यवहार को प्रोत्साहित करता है।
- सतत निवेश के तेजी से लोकप्रिय होने के साथ, वित्तीय क्षेत्र को उन उत्पादों की मांग पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने और ग्रीनवॉशिंग को रोकने का प्रयास करते हैं।

ब्रेन बूस्टर

कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार देशों को 2015 के पेरिस समझौते के तहत इस शताब्दी के दौरान ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के मौजूदा वादों से आगे बढ़ना चाहिए। ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी में देरी से भविष्य में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने (सीडीआर: कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल) पर निर्भरता और बढ़ जाएगी।

सीडीआर के बारे में

- सीडीआर का उद्देश्य वायुमंडल से सीधे CO_2 प्रदूषण को हटाकर जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करना है।
- कार्बन हटाने की रणनीतियों में पेड़ों को उगाने जैसे उपाय के साथ-साथ डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसी अधिक नवीन तकनीकें शामिल हैं, जो हवा से CO_2 को कम करती हैं और इसे भूमिगत रूप से अलग करती हैं।

कार्बन कैप्चर और भंडारण के बारे में

- सीसीएस में औद्योगिक प्रक्रियाओं, जैसे स्टील और सीमेंट उत्पादन, या बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले CO_2 उत्सर्जन को एकत्रित करना शामिल है।
- इस कार्बन को जहां इसका उत्पादन किया गया था, वहां से जहाज या पाइपलाइन के माध्यम से, ले जाया जाता है और भूवैज्ञानिक संरचनाओं में गहरे भूमिगत संग्रहीत किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में कार्बन निष्कासन का महत्व

- नवीनतम जलवायु मॉडल परिदृश्यों से पता चलता है कि सभी प्रक्रियाएं जो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं, उन्हें कार्बन निष्कासन की आवश्यकता होती है। अनुमान है कि प्राकृतिक और तकनीकी दोनों तरीकों को शामिल करते हुए 2050 तक वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 5 से 16 बिलियन मीट्रिक टन तक का कार्बन निष्कासन किया जाएगा।

वायुमंडल से CO_2 का निष्कासन

वृक्ष और वन:

- वनीकरण या वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना।
- जहां बीमारी या अन्य कारणों से वृक्ष नष्ट हो गए हैं, वहां वनों को फिर से उगाना, या उनका घनत्व बढ़ाना।
- सिल्वोपास्चर, या पशु-कृषि प्रणालियों में वृक्षों को शामिल करना।
- फसल भूमि कृषि वानिकी या पंक्ति फसल कृषि प्रणालियों में वृक्षों को शामिल करना।

खेत और मृदा:

- मृदा स्वाभाविक रूप से कार्बन सोख लेती है, लेकिन बार-बार जुताई और खेती और चराई से कटाव के कारण कृषि मृदा में बड़ी कमी हो रही है, जो सभी संग्रहीत कार्बन को उत्सर्जित करते हैं।
- जब खेत खाली हों तो कवर फसलें लगाने से पूरे वर्ष प्रकाश संश्लेषण बढ़ सकता है।
- कम्पोस्ट के उपयोग से मिट्टी में कम्पोस्ट की कार्बन सामग्री को संग्रहित करते हुए पैदावार में सुधार किया जा सकता है।

बायोमास कार्बन निष्कासन और भंडारण:

- बायोमास कार्बन निष्कासन और भंडारण (BiCRS) में प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है जो हवा से CO_2 को हटाने के लिए पौधों या शैवाल से बायोमास का उपयोग करती है और फिर इसे लंबे समय तक संग्रहीत करती है।
- बायोमास का उपयोग करके कार्बन हटाने की विभिन्न विधियाँ:
  - बायोचार
  - जैव तेल
  - बायोएनर्जी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (बीईसीसीएस)

डायरेक्ट एयर कैप्चर:

- डायरेक्ट एयर कैप्चर परिवेशी वायु से रासायनिक रूप से CO_2 को साफ करने और फिर इसे भूमिगत या कंक्रीट जैसे लंबे समय तक रहने वाले उत्पादों में जब्त करने की प्रक्रिया है।

कार्बन खनिजकरण

- कुछ खनिज स्वाभाविक रूप से CO_2 के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और CO_2 को गैस से ठोस में बदल देते हैं और इसे स्थायी रूप से वायुमंडल से बाहर रखते हैं।
- इस प्रक्रिया को आमतौर पर 'कार्बन खनिजकरण' या 'उन्नत अपक्षय' के रूप में जाना जाता है और यह स्वाभाविक रूप से सैकड़ों या हजारों वर्षों में बहुत धीरे-धीरे होता है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। यह दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का प्रतीक है जो देश में समाचार मीडिया की एक नियामक संस्था है।

थीम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया।

भारतीय प्रेस परिषद

- भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक स्वायत्त निकाय है जिसे पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत स्थापित किया गया था। बाद में इसे 1979 में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत फिर से स्थापित किया गया था।
- इसमें एक अध्यक्ष के साथ 28 सदस्यों की एक परिषद होती है। अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने गए एक सदस्य द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य समाचार मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करके प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना है।
- इसके कार्यों में समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता बनाना और उन विकासों की समीक्षा करना शामिल है जो समाचारों के प्रवाह में बाधा बन सकते हैं।

मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

- मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पत्रकारिता डेटा के विशाल गठजोड़ के पैटर्न को अलग करने और पहचानने में मदद कर सकती है। इस प्रकार, यह बेहतर समाचार स्रोत तैयार करने और सूचित जनमत सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
- एआई बुनियादी डेस्क नौकरियों को प्रबंधित और स्वचालित करने में भी मदद कर सकता है जो समय का एक बड़ा भाग लेता है, जिससे मुख्य पत्रकारिता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- यह जनता के एक निश्चित वर्ग के लिए समाचार बनाने में सहायता कर सकती है तथा वैयक्तिकृत सामग्री बनाने में मदद करती है।

निष्कर्ष

- एआई हालांकि एक वरदान है जो जीवन स्तर को आसान बनाता है लेकिन इसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, नैतिक मानवीय निरीक्षण के साथ जिम्मेदार एआई उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
- एआई की विश्वसनीयता को स्रोत सत्यापन, तथ्य-जांच और यह सुनिश्चित करके बढ़ाया जाना चाहिए कि यह अपने प्रशिक्षण डेटा से पूर्वाग्रहों को नहीं अपनाता है।
- इसके अलावा, सूचना के बेहतर प्रवाह और सूचित जनमत को सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारिता की अखंडता को बरकरार रखा जाना चाहिए।

प्रमुख बाधाएँ

- एआई सामग्री निर्माण की प्रक्रिया को आसान बना सकता है, हालांकि, सामग्री की सटीकता और प्रामाणिकता के संबंध में इसकी विश्वसनीयता अभी भी संदेहास्पद है।
- इसका उपयोग एक इको चैंबर बनाने और अपनी वैयक्तिकृत सामग्री और स्वचालित एल्गोरिदम के माध्यम से गलत सूचना फैलाने के लिए किया जा सकता है। यह मौजूदा पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ कर सकता है और विविध दृष्टिकोणों को बाधित कर सकता है।
- यह अपने स्वचालित सामग्री निर्माण के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों और मीडिया अखंडता को खतरे में डालता है जो लिखित, ऑडियो या दृश्य रूप में हो सकते हैं।
- यह जनता को सूक्ष्म रूप से लक्षित करता है, उनकी राय को प्रभावित करता है और इस प्रकार मूल लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित करता है।

ब्रेन बूस्टर

टैंटलम: एक दुर्लभ धातु

चर्चा में क्यों ?

आईआईटी, रोपड़ के शोध कर्ताओं ने सतलुज नदी की रेत में टैंटलम की पहचान की है। डॉ रेसमी सेबेस्टियन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में धातु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए टीम का नेतृत्व किया है।

टैंटलम के बारे में

- टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है।
- यह धूसर, भारी, बहुत कठोर और अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है जो हवा के संपर्क में आने पर एक टिकाऊ ऑक्साइड परत बनाता है।
- शुद्ध टैंटलम लचीला है, जिसका अर्थ है कि इसे बिना टूटे पतले तार में खींचा जा सकता है, और यह 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमले से लगभग पूरी तरह से प्रतिरक्षित है।
- धातु का नाम ग्रीक पौराणिक व्यक्ति टैंटलस के नाम पर रखा गया है, जिसे जीउस द्वारा दंड देने के लिए जाना जाता है। इसका नाम एसिड में टैंटलम की अघुलनशीलता को दर्शाता है।
- अपने उच्च गलनांक के कारण, टैंटलम का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में प्लैटिनम के विकल्प के रूप में किया जाता है।
- टैंटलम का उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाजों और मिसाइलों के घटकों के उत्पादन में भी किया जाता है।
- टैंटलम कार्बाइड (TaC) और ग्रेफाइट कंपोजिट ज्ञात सबसे कठोर सामग्रियों में से एक है और इसका उपयोग हाई-स्पीड मशीन टूल्स के काटने वाले किनारों पर किया जाता है।

सतलुज नदी में खोज का महत्व

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रोपड़ की एक टीम द्वारा पंजाब में सतलुज नदी की रेत में खोजा गया।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालकों में इसके व्यापक उपयोग के कारण धातु की उपस्थिति पंजाब और भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
- सतलुज में टैंटलम की खोज इसके वैश्विक महत्व विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाती है।

खोज और उत्पत्ति

- 1802 में स्वीडिश रसायनज्ञ एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग द्वारा येटरबी, स्वीडन में खोजा गया था।
- शुरू में इसे नाइओबियम का एक अलग रूप माना जाता था लेकिन बाद में 1866 में स्विस रसायनज्ञ जीन चार्ल्स गैलिसार्ड डी मैरिग्नैक द्वारा एक विशिष्ट तत्व के रूप में इसकी पुष्टि की गई।

उपयोग

- **प्लैटिनम का विकल्प:** इसके उच्च गलनांक के कारण प्लैटिनम के स्थान पर उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाजों और मिसाइलों के घटकों में।
- **चिकित्सा अनुप्रयोग:** शारीरिक तरल पदार्थों के साथ गैर-प्रतिक्रियाशील, सर्जिकल उपकरण और कृत्रिम जोड़ों जैसे प्रत्यारोपण में उपयोग किया जाता है।

नाम उत्पत्ति

- इसका नाम ग्रीक पौराणिक चरित्र टैंटलस के नाम पर रखा गया है।
- टैंटलस जीउस द्वारा दंडित एक अमीर लेकिन दुष्ट राजा था। इसका नाम एसिड में धातु की अघुलनशीलता को दर्शाता है जो टैंटलस के पानी या फल में भाग लेने में असमर्थता के समान है।

ब्रेन बूस्टर

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

इतिहास

रेल मंत्री ने 2005-06 के रेल बजट की संसदीय प्रस्तुति के दौरान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। अप्रैल 2005 में जापान के साथ सहयोग ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की व्यवहार्यता अध्ययन और संभावित वित्तपोषण का मार्ग प्रशस्त किया। अध्ययन के निष्कर्ष अक्टूबर 2007 में प्रस्तुत किए गए।

भविष्य के कॉरिडोर

- ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा)
- ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर (भुसावल से दानकुनी तक, जिसमें राजखरसवां से अंडाल तक स्पर लाइन)
- उत्तर-दक्षिण गलियारा (इटारसी-नागपुर-विजयवाड़ा)

हरित प्रभाव

- डीएफसी का लक्ष्य माल परिवहन को सड़क से रेल पर स्थानांतरित करना है, जिससे सड़क परिवहन के कार्बन-सघन प्रभाव को कम किया जा सके।
- डीएफसी के कार्यान्वयन से 30 वर्षों की अवधि में 450 मिलियन टन से अधिक CO_2 उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगा।
- रेल परिवहन पर डीएफसी का ध्यान और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और एक अधिक सतत माल परिवहन प्रणाली तैयार होगी।
- डीएफसी से जुड़े दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा से कम कार्बन वाली औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार में क्रांति लाने की उम्मीद है।

डीएफसी की जरूरत

- भारतीय रेलवे का स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है, जो यात्री और माल यातायात के अत्यधिक दबाव को संभालता है।
- यह महत्वपूर्ण मार्ग, जो नेटवर्क का केवल 16% हिस्सा है, 52% से अधिक यात्री यातायात और 58% राजस्व-अर्जित माल यातायात का बोझ वहन करता है।
- इस मार्ग का लाइन क्षमता उपयोग 115% से 150% के बीच रहता है, जो अत्यधिक संतृप्त और तनावपूर्ण रेल बुनियादी ढांचे का संकेत देता है।
- निम्नलिखित माल परिवहन में रणनीतिक बदलाव की तत्काल आवश्यकता को जन्म दिया:
  - बढ़ती घरेलू अर्थव्यवस्था।
  - फलती-फूलती बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ।
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि।

डीएफसीसीआईएल की स्थापना

- समर्पित प्रयासों की आवश्यकता को पहचानते हुए, रेल मंत्रालय ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित करने के लिए कदम उठाए।
- यह पहल 30 अक्टूबर 2006 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के रूप में साकार हुई।

विजन

ग्राहक फोकस के साथ कुशल और विश्वसनीय सेवा के माध्यम से रेलवे की बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी बनाना।

डीएफसी के लाभ

- मालगाड़ी परिचालन में तेजी लाने और उत्पादकता बढ़ाने से परिवहन की इकाई लागत में कमी आएगी।
- डीएफसी का लक्ष्य कुशल कार्गो आवाजाही के लिए विशेष और अनुकूलित लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करके माल बाजार में रेल हिस्सेदारी बढ़ाना है।
- डीएफसी माल ढुलाई के बुनियादी ढांचे को अलग करता है, जिससे रेलवे के यात्री और माल ढुलाई दोनों व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
- गारंटीकृत पारगमन समय के साथ समयबद्ध माल ढुलाई सेवाएं माल परिवहन में बेहतर योजना और विश्वसनीयता में योगदान करेंगीं।

ब्रेन बूस्टर

ऑप्टिकल फाइबर केबल

ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में

ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) या फाइबर ऑप्टिक्स केबल कांच के पतले बेलनाकार धागों से बने होते हैं। एक सामान्य फाइबर का व्यास मानव बाल के व्यास के करीब होता है। ये फाइबर डिजिटल सूचना के रूप में एन्कोड की गई जानकारी को लगभग प्रकाश की गति से अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं।

फाइबर ऑप्टिक्स के उपयोग

- कंप्यूटर नेटवर्किंग और प्रसारण
- इंटरनेट और केबल टेलीविजन
- समुद्र के भीतर का वातावरण
- सैन्य और अंतरिक्ष
- चिकित्सा

नुकसान

- फाइबर ऑप्टिक्स अक्सर तांबे के तार से अधिक महंगा होता है।
- तांबे की तुलना में ग्लास फाइबर को बाहरी केबल के भीतर अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- नई केबल लगाना श्रमसाध्य है।
- फाइबर ऑप्टिक केबल अक्सर अधिक नाजुक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि केबल कुछ सेंटीमीटर के दायरे में मुड़ी हुई है तो फाइबर टूट सकते हैं, या सिग्नल खो सकता है।

ओएफसी की कार्य विधि

- फाइबर ऑप्टिक्स डेटा को प्रकाश कणों, या फोटॉन के रूप में प्रसारित करता है जो फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से स्पंदित होता है।
- ग्लास फाइबर कोर और क्लैडिंग में प्रत्येक का एक अलग अपवर्तक सूचकांक होता है जो आने वाली रोशनी को एक निश्चित कोण पर मोड़ता है।
- जब प्रकाश सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नामक प्रक्रिया का पालन करते हुए, जिग-जैग बाउंस की एक श्रृंखला में कोर और क्लैडिंग से प्रतिबिंबित होते हैं।
- सघन कांच की परतों के कारण सिग्नल प्रकाश की गति से यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि प्रकाश की गति से लगभग 30% धीमी गति से यात्रा करते हैं।
- अपनी यात्रा के दौरान सिग्नल को नवीनीकृत करने या बढ़ावा देने के लिए, फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन को कभी-कभी लम्बे अंतराल पर रिपीटर्स की आवश्यकता होती है।

ओएफसी के प्रकार

सिंगल-मोड फाइबर:

- ग्लास फाइबर कोर के छोटे व्यास के कारण सिंगल-मोड फाइबर का उपयोग लंबी दूरी के लिए किया जाता है।
- यह छोटा व्यास क्षीणन की संभावना को कम करता है। क्षीणन, सिग्नल की शक्ति में कमी है।
- कम व्यास प्रकाश को एक किरण में परिवर्तित कर देता है, अधिक सीधा मार्ग प्रदान करता है और सिग्नल को लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाता है।

मल्टीमोड फाइबर:

- मल्टीमोड फाइबर का उपयोग छोटी दूरी के लिए किया जाता है क्योंकि अधिक कोर ओपनिंग प्रकाश संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करता है और रास्ते में अधिक प्रतिबिंबित उत्पन्न करता है।
- अधिक व्यास द्वारा एक समय में केबल के माध्यम से कई प्रकाश पुंजों को भेजा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक डेटा ट्रांसमिशन होता है।

लाभ

- इनमें उच्च बैंडविड्थ क्षमताएं होती है।
- सिग्नल को बूस्ट देने की अधिक आवश्यकता के बिना भी प्रकाश आगे की यात्रा कर सकता है।
- ये विभिन्न इंटरफेरेंस जैसे विद्युत चुम्बकीय इंटरफेरेंस के प्रति कम संवेदनशील होते हैं।
- इन्हें पानी में डुबाया जा सकता है।
- फाइबर ऑप्टिक केबल तांबे के तार वाले केबल की तुलना में अधिक मजबूत, पतले और हल्के होते हैं।
- उन्हें बार-बार रखरखाव या बदलने की आवश्यकता नहीं होती है।

ब्रेन बूस्टर

सीओपी28

सीओपी28 के बारे में

सीओपी28 28वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक है जहां सरकारें इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन को कैसे सीमित किया जाए और उसके लिए तैयारी कैसे की जाए। शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया जा रहा है। सीओपी का अर्थ 'पार्टियों का सम्मेलन' है, जहां 'पार्टियां' वे देश हैं जिन्होंने मूल संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौता दस्तावेज, 1992 पर हस्ताक्षर किए हैं।

सीओपी28 का महत्व

- आशा है कि COP28 दीर्घकालिक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य को बनाए रखने में मदद करेगा। 2015 में पेरिस में लगभग 200 देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की थी।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के सबसे हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए 1.5°C का लक्ष्य महत्वपूर्ण है।
- पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में दीर्घकालिक वार्मिंग वर्तमान में लगभग 1.1°C या 1.2°C है।
- हाल के अनुमानों से पता चलता है कि दुनिया वर्ष 2100 तक लगभग 2.4°C से 2.7°C तक तापमान बढ़ने की राह पर है।
- परिणामस्वरूप, 1.5°C की सीमा को पहुंच में रखने की संभावना 'तेजी से संकीर्ण' होती जा रही है।

हानि एवं क्षति निधि

- हानि और क्षति निधि जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है।
- यह शब्द उस मुआवजे को संदर्भित करता है जो अमीर राष्ट्र, जिनके औद्योगिक विकास के कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई है और ग्रह को जलवायु संकट में डाल दिया है, को उन गरीब देशों को भुगतान करना होगा, जिनका कार्बन पदचिह्न कम है, लेकिन समुद्र के बढ़ते स्तर, बाढ़, भयावह सूखा और तीव्र चक्रवात आदि का खामियाजा भुगत रहे हैं।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम

- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम केवल कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण-सकारात्मक कार्यों के लिए बाजार-आधारित प्रोत्साहन का एक प्रयास है।
- कार्बन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बाजार-आधारित प्रणाली पहले से ही मौजूद है, जो कार्बन क्रेडिट में व्यापार की अनुमति देती है।
- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अन्य पर्यावरणीय कार्यों के लिए इस तंत्र को दोहराने का प्रयास करता है।

विश्व को हानि और क्षति

- शोध के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में 55 कमजोर देशों को जलवायु संकट के कारण संयुक्त रूप से 525 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह संख्या 2030 तक प्रति वर्ष 580 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ग्लोबल वार्मिंग ने विश्व के जीवन के तरीके को बदल दिया है तथा कमजोर समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।
- आईपीसीसी के अनुसार, भविष्य में नुकसान और क्षति बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है।
- यह असमान रूप से वितरित होगा और विकासशील देशों (विशेष रूप से उनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा।

फंडिंग

- प्रारंभिक फंडिंग $475 मिलियन होने का अनुमान है।
- यूएई ने 100 मिलियन डॉलर, यूरोपीय संघ ने 275 मिलियन डॉलर, अमेरिका से 17.5 मिलियन डॉलर और जापान ने 10 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

Prelims Warrior

अब प्रीलिम्स दूर नहीं

UPSC/UPPCS Target Prelims 2024

New Batch (Indian Polity) starting from

18th December 2023

Offline & Online

Key Features

- Complete coverage of UPSC / UPPCS prelims syllabus (500 hrs).
- Daily practice test (25 Questions).
- All India Test Series 2024.
- Regular test & performance evaluation.
- One to one mentorship.
- One year subscription of Perfect-7 magazine.

9219200789 A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

ओनाटुकारा तिल

हाल ही में केरल के अलाप्पुझा जिले में ओनाटुकारा तिल की खेती को विस्तारित करने के प्रयास किए गए हैं।

ओनाटुकारा तिल के बारे में:

- केरल कृषि विश्वविद्यालय (केएयू) ने ओनाटुकारा तिल के लिए तीन साल के व्यापक शोध के बाद जनवरी 2023 में जीआई टैग हासिल किया।
- पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सक गठिया के इलाज में ओनाटुकारा तिल का उपयोग करते हैं।
- इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड तथा पामिटोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है।
- यह अलाप्पुझा और कोल्लम जिलों में फैले 43 स्थानीय निकायों के 600 हेक्टेयर में उगाया जाता है।
- इसके लिए व्यक्तियों, सामूहिकों, कुडुंबश्री समूहों, स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों सहित विभिन्न समूहों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

बीडीएस आंदोलन

हाल ही में भारतीय कवि रंजीत होसकोटे ने यहूदी विरोधी भावना और बीडीएस आंदोलन से संबंधों के आरोपों के बीच डॉक्युमेंटा 16 समिति छोड़ दी। डॉक्युमेंटा समकालीन कला की दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है जो हर पांच साल में जर्मनी के कैसल में आयोजित होती है।

बीडीएस आंदोलन के बारे में:

- बीडीएस (Boycott, Divestment, Sanctions) आंदोलन की शुरूआत 2005 में 170 से अधिक फिलिस्तीनी समूहों द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य अहिंसक तरीकों से फिलिस्तीनी अधिकारों की वकालत करना था।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य यहूदी विरोधी भावना को बढ़ाना और इस्लामोफोबिया सहित भेदभाव का विरोध करना है, साथ ही इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए दबाव डालना है।
- यह वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम, गाजा और गोलान हाइट्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में इजरायल के कब्जे को समाप्त करना चाहता है।
- यह इजराइल में अरब-फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए पूर्ण मौलिक अधिकारों की मान्यता और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अपने घरों में लौटने के अधिकार की वकालत करता है।

सी बकथॉर्न (Sea Buckthorns)

हाल ही में लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया है।

सी बकथॉर्न के बारे में:

- सी बकथॉर्न को लद्दाख पश्मीना, खुबानी (रकत्से कार्पो प्रजाति) और लद्दाखी लकड़ी की मूर्तियों के बाद लद्दाख में चौथा जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
- इसे लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है जो विटामिन सी और विभिन्न अन्य पोषक तत्वों से भरपूर छोटी, तीखी नारंगी या पीली बेरी के रूप में पाया जाता है।
- यह प्राकृतिक रूप से लद्दाख की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगभग 11,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है जो अत्यधिक ठंड (शून्य से 43 से 40 डिग्री सेल्सियस तक) और सूखे के प्रति लचीलापन प्रदर्शित करता है।
- सी बकथॉर्न को इसके अंतर्निहित गुणों के कारण पारंपरिक रूप से ईंधन, दवा और पोषण पूरक के रूप में उपयोग किया जाता रहा है।
- सी बकथॉर्न को विभिन्न नामों से जाना जाता है जिनमें 'वंडर प्लांट', 'लद्दाख गोल्ड', 'गोल्डन बुश' या ठंडे रेगिस्तान की 'सोने की खान' शामिल हैं।

मिरिस्टिका दलदल

हाल ही में यह पाया गया है कि मिरिस्टिका दलदल (जो कई प्रजातियों के लिए स्थानिक हैं) को गंभीर रूप से संरक्षण की आवश्यकता है।

मिरिस्टिका दलदल के बारे में:

- विश्व स्तर पर सबसे पुराने फूल वाले पौधों में से एक, मिरिस्टिकासी परिवार के सदाबहार पेड़ों के वर्चस्व वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में उनकी स्थिति के कारण मिरिस्टिका दलदलों को जीवित जीवाश्म माना जाता है।
- ये दलदल मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिनकी विशेषता सदाबहार पेड़ों से होती है जिनकी गहरी जड़ें जलयुक्त मिट्टी में उगती हैं जो साल भर जलमग्न रहती हैं।
- लाखों वर्षों में विकसित होने वाले इन दलदलों में पुराने-विकसित पेड़ शामिल हैं जो समय के साथ आज भी दिखाई देती हैं।
- भारत में मिरिस्टिका दलदल मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं जिनका वितरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कम है।
- उच्च आर्द्रता, मध्यम तापमान और पर्याप्त मैक्रोहैबिटेट उपलब्धता सहित स्थिर पारिस्थितिक स्थितियों के कारण मिरिस्टिका दलदल विविध कशेरुकी तथा अकशेरुकी प्रजातियों को आश्रय देते हैं।

घोल (The Ghol) मछली

हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित एक वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन में 'घोल मछली' को आधिकारिक तौर पर गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया।

घोल मछली के बारे में:

- घोल मछली (Protonibea Diacanthus) को गुजरात सरकार द्वारा इसके आर्थिक मूल्य और उपलब्धता की कमी के कारण चुना गया।
- घोल मछली फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक इंडो-पैसिफिक में व्यापक रूप से पाई जाती है।
- घोल मछली, खासकर चीन और अन्य एशियाई देशों जैसे बाजारों में अपनी दुर्लभता तथा वाणिज्यिक मूल्य के कारण मछुआरों के लिए एक बेशकीमती मछली है।
- इसका मांस फिललेट्स या पूरी मछली के रूप में यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों में निर्यात किया जाता है, जबकि सूखे एयर ब्लैडर की एशिया में औषधीय इस्तेमाल होने के कारण उच्च मांग है।
- 2021-22 में गुजरात का मछली उत्पादन कुल 8.74 लाख टन और मूल्य 11,221 करोड़ रुपये था। इसका निर्यात 2.3 लाख टन तक पहुंच गया जिससे 5,233 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- घोल को राज्य मछली घोषित करने का उद्देश्य गुजरात की मछली पकड़ने की प्रथाओं में इस प्रजाति के संरक्षण उपायों को शामिल करना है।

मडिगा समुदाय

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति के भीतर मडिगा समुदाय के उप-वर्गीकरण का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया।

मडिगा समुदाय के बारे में:

- मडिगा एक तेलुगु जाति समुदाय है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटक में निवास करता है। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी इसकी आबादी पाई जाती है।
- मडिगा समुदाय में बिंदला, चिंदु, दक्कली और मष्टी जैसी विविध उपजातियाँ पाई जाती हैं। यह समुदाय 1994 से उप-वर्गीकरण की मांग कर रहा था।
- मडिगा समुदाय में तेलंगाना में 50% से अधिक अनुसूचित जाति (एससी) शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति राज्य की आबादी का केवल 15% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। पुरोहित वर्ग को मडिगा दसारी के नाम से जाना जाता है।
- मडिगा डंडोरा आंदोलन की शुरुआत 1994 में मंदा कृष्णा मडिगा और डंडू वीरैया मडिगा ने किया था।
- '1940 लो ओका ग्रामम' और 'पलासा 1978' जैसी वृत्तचित्र तथा फिल्में मडिगा समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली जाति-आधारित सामाजिक गतिशीलता और संघर्षों को दर्शाती हैं।

ए(एच1एन2)वी फ्लू स्ट्रेन

हाल ही में ब्रिटेन ने सूअरों में पाए जाने वाले वायरस के समान ए(एच1एन2)वी फ्लू स्ट्रेन के पहले मानव मामले की पुष्टि की।

ए(एच1एन2) वायरस के बारे में:

- अगस्त 2023 में, अमेरिका के मिशिगन में इन्फ्लुएंजा ए(एच1एन2) वायरस के एक नए प्रकार की आधिकारिक पुष्टि की गई।
- यह इन्फ्लूएंजा ए वायरस (इन्फ्लूएंजा का सबसे आम प्रकार) का एक उपप्रकार है जिसे बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है।
- यह मुख्य रूप से दुनिया भर में सूअर की आबादी में पाया जाता है।
- यह स्ट्रेन उस वायरस के समान है जो वर्तमान में सूअरों में फैल रहा है।
- इन्फ्लूएंजा वायरस के चार प्रकार ए, बी, सी और डी हैं। इन्फ्लूएंजा ए और बी वायरस मौसमी महामारी का कारण बनते हैं।
- **लक्षण:** बुखार, खांसी, छींक आना, सांस लेने में कठिनाई, आंखें लाल होना या सूजन, खाना न खाना आदि हैं।

ललिताम्बिका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला

- हाल ही में, वी. आर. ललिताम्बिका को भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष सहयोग पहल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला।
- ललितांबिका (जन्म: 1962)
- डॉ. वी.आर. ललितांबिका एक भारतीय वैज्ञानिक, लेखिका और इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए काम करती हैं।
- वह 1988 में लॉन्च वाहन ऑटोपायलट डिजाइन इंजीनियर के रूप में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में शामिल हुई।

योगदान:

- इन्होंने इसरो और फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 2018 में, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के निदेशक के रूप में, इन्होंने भारत की गगनयान परियोजना के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) के साथ निकटता से समन्वय किया।

पुरस्कार और सम्मान:

- इन्हें 2001 में स्पेस गोल्ड मेडल, 2013 में इसरो इंडिविजुअल मेरिट अवॉर्ड और इसरो परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
- प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा भी सम्मानित किया गया।

'वज्र प्रहार 2023'

- भारत-अमरीका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास 'वज्र प्रहार 2023' का 14वां संस्करण उमरोई के संयुक्त प्रशिक्षण स्थल में सम्पन्न हुआ। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारतीय सेना और अमरीका की सेना की विशेष टुकड़ियों के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य संयुक्त कार्यक्रम योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों तथा उत्कृष्ट अनुभवों को साझा करना है।

- इस युद्धाभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2010 में भारत में किया गया था। भारत-अमरीका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास का 13वां संस्करण बकलोह (हिमाचल प्रदेश) के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र (एसएफटीएस) में आयोजित किया गया था। वर्तमान संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक मेघालय में स्थित उमरोई छावनी में संचालित किया गया है। वज्र प्रहार अभ्यास दोनों देशों की विशेष सैन्य टुकड़ियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान करने और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के लिए एक तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। यह भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाने तथा रक्षा सहयोग को सशक्त करने का एक बड़ा अवसर रहा है।

शहरी सुधार एजेंडा के लिए भारत ने एडीबी से 400 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए

- भारत सरकार ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के तहत शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास

बैंक (एडीबी) के साथ 400 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, सेवा वितरण में सुधार करना और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम शहरी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सरकार की शहरी क्षेत्र की रणनीति का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य शहरों को रहने योग्य और आर्थिक विकास का केंद्र बनाना है।

- कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण और सामुदायिक जागरूकता के साथ-साथ कानूनी, नियामक तथा संस्थागत सुधारों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के माध्यम से नियोजित शहरीकरण की भी परिकल्पना की गई है।

अंकोरवाट मंदिर को दुनिया का आठवां अजूबा किया गया घोषित

- कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर को दुनिया का आठवां अजूबा घोषित किया गया है। यह मंदिर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर दुनिया का आठवां अजूबा बना है। अंकोरवाट मंदिर 162.6 हेक्टेयर (1,626,000 वर्ग मीटर; 402 एकड़) में फैला हुआ है जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी के पास है।

अंकोरवाट मंदिर के बारे में:

- अंकोरवाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर 800 साल पुराना है। मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद बने हुए हैं जो माउंट मेरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था लेकिन बाद में यह बदल कर एक बौद्ध मंदिर बन गया।

एसएंडपी ने जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6% से 6.4% किया

- एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान से कहीं अधिक तेज गति से बढ़ेगी।
- वित्तीय वर्ष 2024 के लिए रेटिंग एजेंसी ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को पहले के 6% से संशोधित करके 6.4% किया है। एसएंडपी का मानना है कि भारत के ब्याज दर चक्र को बदलने में कुछ समय लगेगा।
- एसएंडपी (स्टैंडर्ड एंड पूअर्स) ग्लोबल रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) है जो स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी पर वित्तीय अनुसंधान तथा विश्लेषण प्रकाशित करता है।

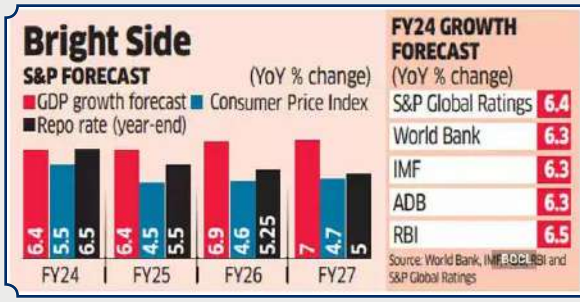

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2023

- हाल ही में 14 अलग-अलग कैटेगरी में न्यूयॉर्क में आयोजित 51वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड में पुरस्कार वितरित किये गए। इनमें से दो कैटेगरी में भारतीयों को एमी अवॉर्ड्स प्रदान किए गये। बेस्ट यूनिक कॉमेडी के लिए भारत के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास को 'वीर दास: लैंडिंग शो' के लिए पुरस्कार मिला। बालाजी टेलीफिल्म्स की सह-संस्थापक एकता कपूर को इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए डायरेक्टरेट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार 'मरियोपोल: द पीपल्स स्टोरी' को मिला है। बेस्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार: जर्मन वेब सीरीज द इंप्रेस ने अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी और मिनी सीरीज के लिए 'ला कैडा' को एमी पुरस्कार मिला है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. 1 दिसंबर को एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने डायरेक्टर जनरल (Inspection and Security) का पदभार संभाला। उन्होंने 30 नवंबर 2023 को रिटायर्ड हुए एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह ली है।
2. सीपीआई (एम) के संस्थापक सदस्यों में से एक एन. शंकरैया का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शंकरैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के 32 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों में से एक थे। वह 1946 में मदुरै षड्यंत्र मामले में दूसरे आरोपी थे।
3. सलमान रुश्दी को पहला 'लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवॉर्ड' मिला। अक्टूबर में, उन्हें 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला।
4. शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काइडाइविंग करने वाली पहली महिला बनीं।
5. भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) 2023 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में 17-20 जनवरी, 2024 तक किया जाएगा। यह आईआईएसएफ का नौवां संस्करण है जिसका विषय 'अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक आउटरीच' है।
6. कैरीबियाई समुदाय (कैरिकॉम) में भारतीय राजदूत और सेंट किट्स एंड नेविस तथा एंटीगुआ और बारबुडा फेडरेशन के उच्चायुक्त के रूप में अमित एस तेलंग को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनिल कुमार राय को इथियोपिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।
7. भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा। एसबीआई सिंगापुर में योनो ग्लोबल ऐप को पेनाउ (PayNow) के साथ एकीकृत कर रहा है। वर्तमान में एसबीआई 9 देशों में योनो ग्लोबल सेवाएं प्रदान करता है। सितंबर 2019 में इसकी शुरुआत यूके ऑपरेशंस से हुई।
8. हाल ही में न्यूजीलैंड में रूढ़िवादी गठबंधन के नेता क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे न्यूजीलैंड में छह वर्षों से चली आ रही वामपंथी सरकारों का अंत हो गया।
9. हाल ही में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर उज्ज्वला (एक गौरैया) नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। यह छोटी गौरैया दिल्ली के गौरव का प्रतीक है जो इसकी विशिष्ट दृढ़ संकल्प एवं सहानुभूति को दर्शाती है।
10. हॉर्नबिल फेस्टिवल का 10 दिवसीय 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश और असम भागीदार राज्य है।
11. 30 नवंबर को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सकल घरेलू उत्पाद डेटा साझा किया गया है जिसमें चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.6% की दर से बढ़ा। 2022 की इसी अवधि में जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही थी।
12. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का विषय 'स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियाँ और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद' रहा।
13. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कस्टमर सर्विस पॉइंट्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 'अमा बैंक' लॉन्च किया। ओडिशा सरकार छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 'अमा बैंक' योजना की शुरुआत की है। इस वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत 4,373 बैंक रहित ग्राम पंचायतों को कवर किया जायेगा।
14. हाल ही में अमेरिकी राजनयिक और नोबेल विजेता हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। अमेरिकी विदेश नीति में कई दशकों तक इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
15. अब्दुल्लाही मिरे को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। इन्होंने शरणार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के विषय में जागरूकता और पुस्तक दान को बढ़ावा देने के लिए शरणार्थी युवा शिक्षा केंद्र की स्थापना की। इस संगठन ने शिविरों में 1 लाख से अधिक किताबें वितरित करने के अलावा तीन पुस्तकालय खोले हैं।
16. एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को WISE 11 शिखर सम्मेलन (शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन) में प्रतिष्ठित WISE पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार अपनी तरह का पहला वैश्विक पुरस्कार है जो शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करता है।

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

गिनी की खाड़ी

हाल ही में भारतीय नौसेना ने अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी (जीओजी) में अपनी दूसरी एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग पूर्ण किया।

गिनी की खाड़ी के बारे में:

- **स्थान:** गिनी की खाड़ी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है जो उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तर पूर्वी भाग है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा (0°0'E) और भूमध्य रेखा (0°0'N) के चौराहे पर स्थित है।
- **तटीय देश:** सोलह तटीय देश गिनी की खाड़ी की सीमा पर स्थित हैं जिनमें अंगोला, बेनिन, कैमरून, कोटे डी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी-बिसाऊ, गैबॉन, नाइजीरिया, घाना, साओ टोमे और प्रिंसिपे, टोगो तथा सियरा लिओन शामिल हैं।
- **लवणता:** नदी के प्रवाह और अधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र के पानी में अपेक्षाकृत कम लवणता है।
- **प्रमुख नदियाँ:** वोल्टा और नाइजर नदियाँ गिनी की खाड़ी की प्राथमिक सहायक नदियाँ हैं।

लेस्बोस द्वीप

हाल ही में ग्रीस द्वीप लेस्बोस के पास तूफानी समुद्र में एक मालवाहक जहाज डूब गया।

- **स्थान:** लेस्बोस (जिसे लेसवोस के नाम से भी जाना जाता है) उत्तरपूर्वी एजियन सागर में स्थित ग्रीस का एक द्वीप है। यह ग्रीस का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
- लेस्बोस की सीमा उत्तर और पूर्व में तुर्की तट से लगती है जो एशिया माइनर से मायटिलिनी जलडमरूमध्य द्वारा अलग होती है। इसके दक्षिणी तट पर कल्लोनी और गेरा की खाड़ी स्थित है।

भौतिक विशेषताएं:

- माउंट लेपेटिमनोस (968 मीटर/3,176 फीट) और माउंट ओलंपस (967 मीटर/3,173 फीट) द्वीप के उत्तरी तथा मध्य क्षेत्रों में कई चोटियाँ हैं।
- यह बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य के साथ-साथ काला सागर तथा मरमरा सागर सहित कई जलमार्गों से जुड़ा हुआ है।
- यह द्वीप अंतिम हिमयुग के अंत से पहले पुरापाषाण/मेसोलिथिक काल के दौरान अनातोलियन मुख्य भूमि से जुड़ा था।

एजियन सागर:

- एजियन सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक लम्बा तटबंध साझा करता है। यह बाल्कन और अनातोलिया को जोड़ने वाले एक महत्त्वपूर्ण समुद्री कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। एजियन सागर उत्तरी क्षेत्र में मरमरा सागर और काला सागर से जुड़ा हुआ है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. रैट होल खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. रैट-होल खनन संकीर्ण और क्षैतिज मार्गों के माध्यम से कोयला भंडार निकालने की एक आदिम विधि है।

2. रैट होल खनन से महत्वपूर्ण सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं। खदानें आम तौर पर अनियमित होती हैं, जिनमें उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहायता या श्रमिकों के लिए सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव होता है।

सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों D. कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पेरिस समझौते में उल्लिखित वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए देशों द्वारा वर्तमान कार्य योजनाओं की अपर्याप्तता को रेखांकित करती है।

2. पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

3. संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट COP28 में पहले वैश्विक स्टॉकटेक के महत्व को रेखांकित करती है, जो राष्ट्रों के लिए सभी क्षेत्रों में अपने जलवायु प्रयासों को बढ़ाने में गति हासिल करने का एक अवसर है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

3. रास महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में, असम के माजुली में वार्षिक रास महोत्सव या रास लीला उत्सव मनाया गया।

2. इसमे स्वयंसेवकों द्वारा बनाए गए नाटकों के माध्यम से भगवान कृष्ण की रास लीला मनाई जाती है।

सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों D. कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में 'भारत में नकद बनाम डिजिटल भुगतान लेनदेन' शीर्षक वाले एक पेपर में डिजिटल भुगतान में वृद्धि को बनाए रखने में साइबर सुरक्षा, ग्राहक सुरक्षा और लागत-प्रभावशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

2. पेपर के अनुसार नकदी के लेनदेन के उपयोग में गिरावट दर्ज की गई है, डिजिटल भुगतान के तरीके धीरे-धीरे नकदी लेनदेन की जगह ले रहे हैं।

3. कोविड-19 महामारी ने डिजिटल भुगतान को तेज करने में भूमिका निभाई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गृह मामलों की संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में व्यभिचार को एक अपराध के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए।

2. व्यभिचार का कार्य एक विवाहित व्यक्ति और उस व्यक्ति के वर्तमान जीवनसाथी या साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बीच स्वैच्छिक यौन संबंध है।

3. समिति ने कहा कि व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे लिंग-तटस्थ बनाया जाना चाहिए यानी, पुरुषों और महिलाओं दोनों को इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

6. दूध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. 2022-23 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 430.58 मिलियन टन होने का अनुमान है।

2. 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% थी।

सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों D. कोई नहीं

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में WHO ने ग्लोबल हेल्थकेयर रिपोर्ट प्रकाशित की जो सदस्य देशों में स्वास्थ्य आँकड़े प्रदान करती है।

2. भारत वर्तमान में अपनी 1.42 बिलियन की आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 बिलियन वर्ग फुट स्वास्थ्य देखभाल स्थान की कमी का सामना कर रहा है।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रति 1000 लोगों पर 3 बिस्तरों के अनुपात की सिफारिश करता है, जिसका मतलब है कि भारत को अतिरिक्त 2.4 मिलियन बिस्तरों की आवश्यकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. तीनों D. कोई नहीं

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में, यूएनईपी द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई थी जिसमें पता चला है कि देशों की वर्तमान जलवायु नीतियों के साथ सदी के अंत तक दुनिया कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगी।

2. जीवाश्म CO_2 उत्सर्जन वर्तमान GHG उत्सर्जन का लगभग दो तिहाई है।

3. सामूहिक रूप से, G20 वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन का 46% हिस्सा को उत्सर्जित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड एनर्जी जॉब्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई।

2. ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक रोजगार महामारी-पूर्व स्तर से 3.4 मिलियन बढ़कर 2022 में 67 मिलियन हो गया।

3. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों ने इसी अवधि में वैश्विक स्तर पर 4.7 मिलियन नौकरियां जोड़ीं और 35 मिलियन तक पहुंच गई।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

10. रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप एक्सपेंशन (RISE) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने नई दिल्ली में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन (RISE) नामक एक नया त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया।

2. यह कार्यक्रम भारत और ऑस्ट्रेलिया में सर्कुलर इकोनॉमी प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप और छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) का समर्थन करेगा।

सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल एक B. केवल दो
C. दोनों D. कोई नहीं

11. ओईसीडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध 38 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

2. ओईसीडी सदस्य आम तौर पर लोकतांत्रिक देश होते हैं जो मुक्त-बाजार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं।

3. OECD की स्थापना 14 दिसंबर 1960 को 18 यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा द्वारा की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

12. वायुमंडलीय तरंगें प्रयोग (AWE) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. NASA ने वायुमंडलीय तरंगें प्रयोग लॉन्च किया, जो एक अग्रणी मिशन है जिसका उद्देश्य स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों का अध्ययन करना है।

2. नासा के हेलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया यह मिशन पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों में तरंगों के ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष के मौसम पर प्रभाव को समझने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल एक B. केवल दो
C. दोनों D. कोई नहीं

13. भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) मजबूत हुई।

2. पहली बातचीत 20-21 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों के बीच हुई थी।

सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

14. आईएसएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक संयुक्त परियोजना है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका (NASA), रूस (रोस्कोस्मोस), यूरोप (ESA), जापान (JAXA), और कनाडा (CSA) की अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं।

2. आईएसएस ने एक माइक्रोग्रैविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य किया है, जिसने कई प्रयोगों और अध्ययनों की मेजबानी की है, जिन्होंने मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है।

सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल एक B. केवल दो
C. दोनों D. कोई नहीं

15. डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन

नीति, 2023 को मंजूरी दे दी है।

2. यह नीति केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) को डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए सशक्त बनाती है।

3. सीबीसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है और भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. तीनों D. कोई नहीं

16. निम्नलिखित देशों पर विचार करें।

1. ऑस्ट्रेलिया 2. कनाडा

3. चीन 4. भारत

5. जापान 6. यूएसए

उपरोक्त में से कौन आसियान के 'मुक्त-व्यापार साझेदारों' में से हैं?

A. 1, 2, 4 और 5

B. 3, 4, 5 और 6

C. 1, 3, 4 और 5

D. 2, 3, 4 और 6

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. वर्ष 1997 में नए सदस्यों को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय 2012 तक रहना था, लेकिन उसके बाद इसमें बदलाव नहीं किया गया।

B. शिखर सम्मेलन गोल्डन गेट घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।

C. भारत को वर्तमान में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में 'पर्यवेक्षक' का दर्जा प्राप्त है।

D. सभी कथन सही।

18. टिटिकाका झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

A. टिटिकाका झील पूर्व में पेरू और पश्चिम में बोलीविया के बीच स्थित है।

B. यह एक रामसर साइट है और यूनेस्को द्वारा अंडरवाटर कल्चरल हेरिटेज श्रेणी के तहत संरक्षित भी है।

C. यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा ताजा जलस्रोत है।

D. प्रसिद्ध प्राचीन इंकास साम्राज्य झील से जुड़ा हुआ है।

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच कागज के प्रचलन में आने तक चित्र ताड़ के पत्ते पर बनाए जाते थे।

2. औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल लघुचित्र की परंपरा में गिरावट शुरू हुई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. दोनों D. कोई नहीं

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। बताइए कीजिए कौन सा कथन उपयुक्त सही है?

A. CARA मुख्य रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने का कार्य करता है।

B. न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीसीआई में अनाथ-परित्यक्त-आत्मसमर्पित (ओएएस) श्रेणी में बच्चों की पहचान करने के लिए त्रि-मासिक अभियान शुरू करने का आदेश दिया।

C. 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए CARA को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

D. इनमें से कोई नहीं।

21. हाल ही में समाचारों में रहा "बोईता बंदना" के सन्दर्भ में विचार करें।

1. यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।

2. साधवों (पारंपरिक व्यापारी नाविकों) के वेश में लड़के नाव में सवार होते थे।

3. साधवनी पोशाक (साधवों की पत्नियाँ) में लड़कियाँ उन्हें विदा करती थीं, नियत भूमि में अच्छे व्यापार और सुरक्षित वापसी की कामना करती थीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से सही हैं?

A. केवल 1 और 3

B. 1 ,2 और 3 सभी

C. केवल 1 और 2

D. केवल 2 और 3

उत्तर

1. C	4. C	7. B	10. C	13. C	16. C	19. C
2. C	5. C	8. B	11. C	14. C	17. D	20. A
3. C	6. B	9. C	12. C	15. C	18. A	21. B

कला एवं संस्कृति

विषय सूची

- विश्व हिन्दी सम्मेलन
- कर्नाटक की बिदरी कला
- वैदिक विरासत पोर्टल
- कौशांबी महोत्सव-2023
- शिशुपालगढ़ का किलाबंद प्राचीन शहर
- प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) (संशोधन) विधेयक
- सिक्किम में बुमचू बौद्ध महोत्सव
- पुरातनता
- अम्बेडकर सर्किट पर भारत गौरव ट्रेन
- वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन
- उत्तरमेरुर शिलालेख
- बिहान मेला
- थिरुनेली मंदिर
- बौद्ध लोककथाएँ
- नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट
- कपिलेश्वर मंदिर
- सेंगोल
- दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम
- देवांकनम चारुहरिथम (भगवान का सुंदर हरा निवास)
- मालचा महल
- हमारी भाषा, हमारी विरासत
- गिलगित पांडुलिपियाँ
- गीता प्रेस ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता
- पुरातत्वविदों ने गुंटूर में मध्यपाषाण युग के शैल चित्रों की खोज
- खर्ची पूजा 2023
- हुल दिवस
- लंबानी कढ़ाई पैच
- रुद्रगिरि हिल रॉक कला
- भारत मंडपम
- कालबेलिया नृत्य
- कुवी और देसिया पुस्तकें
- सीताकली लोक कला
- पुलिक्कली नृत्य
- बांग्लार माटी, बांग्लार जोल
- फणीगिरि की बौद्ध कलाकृतियाँ
- ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण
- नुआखाई महोत्सव
- शांतिनिकेतन और होयसल मंदिर
- सरना धार्मिक संहिता
- वाघ नख
- कोंगाली बिहु
- वज्र मुष्टि कलगा

विश्व हिन्दी सम्मेलन

- 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15-17 फरवरी 2023 को नाडी, फिजी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन फिजी सरकार के सहयोग से किया गया था।
- सम्मेलन का मुख्य विषय 'हिंदी: पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक' था।
- सम्मेलन के दौरान भारत और अन्य देशों के हिंदी विद्वानों को हिंदी के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए 'विश्व हिंदी सम्मान' से सम्मानित किया गया।
- इस विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से 270 शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और हिंदी लेखकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था।
- पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था और तब से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इसका 11वां संस्करण 2018 में मॉरीशस में आयोजित किया गया था।

हिन्दी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 344(1) संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश भी प्रदान करता है जिसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्त्तव्य होगा।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, बंगाली (97.2 मिलियन), मराठी (83 मिलियन), तेलुगु (81 मिलियन) और तमिल (69 मिलियन) बोलने वालों की तुलना में 528 मिलियन भारतीय हिंदी बोलते हैं।
- नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर इस संबंध में भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि नीतिगत प्रोत्साहन के कारण हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा अब एक समय की वास्तविकता बन गई है।

कर्नाटक की बिदरी कला

कर्नाटक के प्रसिद्ध बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

बिदरी कला:

- बिदरी आर्ट भारत के हैदराबाद के हस्तशिल्प का एक प्रसिद्ध रूप है जोकि एक लोकप्रिय निर्यात वस्तु है जिसका नाम कर्नाटक के बीदर तालुका के नाम पर रखा गया है।
- बिदरी आर्ट बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं जिनमें कास्टिंग, पॉलिशिंग, उत्कीर्णन, इनलेइंग और मिश्र धातु को काला करना प्रमुख है।
- बिदरी आर्ट में दमिश्क कार्य का उपयोग किया जाता है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर सोना या चांदी लगाना शामिल है।
- ये वस्तुएं चांदी, सोना या पीतल जैसी धातुओं का उपयोग करके तैयार की जाती हैं जिन्हें विस्तृत पैटर्न में जस्ता और तांबे के मिश्र धातु में एम्बेडेड किया जाता है।
- बिदरी आर्ट के उत्पादन के लिए एक अद्वितीय प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है जो इस शिल्प की विशेषता वाली कला के जटिल कार्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

बिदरी कला का इतिहास:

- बिदरी एक प्राचीन धातु कला है जिसकी जड़ें फारस में मिलती हैं जो लगभग 500 वर्ष पुरानी है।
- इसका विकास मूल रूप से बहमनी राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था।
- 14वीं शताब्दी में भारत में बीदर पर शासन करने वाले फारसी शासकों ने क्षेत्र में इस कला को शुरू किया।
- शाही परिवारों के लिए उत्कृष्ट रचनाएँ तैयार करके बीदर के कारीगरों को फारस के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।

बिदरी आर्ट को पुरस्कार:

- अपनी असाधारण शिल्प कौशल और सांस्कृतिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध बिदरी आर्ट को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
- 2006 में इसकी विशिष्ट उत्पत्ति और पारंपरिक शिल्प विधियों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा इसे सम्मानित भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया था।
- बिदरी आर्ट को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता दी गई है जो इसके वैश्विक सांस्कृतिक महत्त्व की पुष्टि करता है।

आईजीएनसीए ने वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। पोर्टल का प्रमुख लक्ष्य वैदिक ज्ञान विरासत की बेहतर समझ को बढ़ावा देना है।

प्रमुख विशेषताएं:

- वैदिक विरासत पोर्टल भारत की वैदिक विरासत का मानचित्रण करने का एक प्रयास है।
- यह प्रकाशित पुस्तकों/पांडुलिपियों और उपकरणों के रूप में मौखिक परंपराओं व पाठ्य परंपराओं पर गहन जानकारी प्रदान करता है।
- पोर्टल का लक्ष्य वेदों को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना, जानकारी एकत्र करना और आगे की चर्चा के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है।
- यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 'वेदों' का रखरखाव करता है। वेद संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के अनुसार मानव जाति की एक अमूर्त विरासत है।
- इस पोर्टल में 550 घंटे से अधिक अवधि वाले चार वेदों के 18

हजार से अधिक मंत्र हैं।

चार वेदः

ऋग्वेदः

- यह सबसे महत्त्वपूर्ण और प्राचीनतम वेद है।
- इसे दस खंडों (जिसे मंडलों के रूप में जाना जाता है) में व्यवस्थित किया गया है जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाले 1028 सूक्त तथा 10580 ऋचायें शामिल हैं। इनमें इंद्र, अग्नि, विष्णु, रुद्र, वरुण और अन्य 'वैदिक देवता' शामिल हैं।
- इसमें सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र और पुरुष शुक्त (प्राइमल मैन्स टेल) प्रार्थना भी शामिल है।

यजुर्वेदः

- यज्ञ (बलिदान) करने के लिए एक पुरोहितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसे दो खंडों में विभाजित किया जाता है।

सामवेदः

- इसमें पूजा और यज्ञ प्रदर्शन के दौरान किए जाने वाले मंत्रों की धुनें शामिल हैं।

अथर्ववेदः

- इसमें ऐसे भजन और मंत्र शामिल होते हैं जो अधिकतर यज्ञ से संबंधित नहीं हैं।

कौशांबी महोत्सव-2023

केंद्रीय गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में कौशांबी महोत्सव-2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान 'संसदीय खेल प्रतियोगिता' के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

कौशांबी का महत्त्वः

- कौशांबी भगवान बुद्ध और महावीर के समय में 16 जिलों में से एक वत्स जिले की राजधानी थी। उस समय मगध जैसे कई बड़े जिलों के विकसित होने के बावजूद कौशांबी को सबसे समृद्ध माना जाता था।
- भगवान श्री राम और कलिंग चक्रवर्ती अपने जीवन के प्रमुख युद्धों पर विजय प्राप्त करने के बाद इस समृद्ध स्थान पर आए थे।
- यह स्थान दुर्गा भाभी से भी सम्बंधित है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

शिशुपालगढ़ का किलाबंद प्राचीन शहर

भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में 2,600 वर्ष से अधिक प्राचीन एक किलेबंद शहर शिशुपालगढ़ की शानदार पुरातात्विक विरासत को भारी मशीनरी के उपयोग से क्षति पहुंची है।

शिशुपालगढ़ किले के बारे में:

- शिशुपालगढ़ स्थल की खुदाई पहली बार 1948 में की गई थी, तब इसे 1904 के प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।
- इसमें 562.681 एकड़ का क्षेत्र शामिल था जिसके तहत 1950 में शिशुपालगढ़, लिंगीपुर, रघुनाथपुर और महाभोइसासन सहित पांच गांवों को कवर किया गया था।
- 2600 साल पुरानी विरासत शिशुपालगढ़ भारत का एकमात्र किलेबंद स्थल है जिसमें आठ प्रवेश द्वार हैं।
- ऐसा माना जाता है कि शिशुपालगढ़ किला 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। यह कलिंग साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था जो प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था।
- किलाबंदी चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी जब राजा खारवेल ने 2,100 साल पहले शहर की मरम्मत का काम शुरू किया था।

एएसआई के बारे में:

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है जो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है।
- इसकी स्थापना 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को 'भारतीय पुरातत्व के जनक' के रूप में भी जाना जाता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन करना, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल हैं।

प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) (संशोधन) विधेयक

भारत सरकार ने प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) (संशोधन) विधेयक को फिर से संसद में पेश किया है। पुरातात्विक व ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों को संरक्षित करने, खुदाई को विनियमित करने तथा मूर्तियों और नक्काशी की सुरक्षा के उद्देश्य से 1958 में संसद द्वारा प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर) पारित किया गया था।

विधेयक के बारे में मुख्य बातें:

- **'निषिद्ध क्षेत्रों' में निर्माण:** यह एक संरक्षित स्मारक के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र को 'निषिद्ध क्षेत्र' के रूप में परिभाषित करता है। केंद्र सरकार प्रतिबंधित क्षेत्र को 100 मीटर से आगे बढ़ा सकती है। यह 'प्रतिबंधित क्षेत्रों' में निर्माण पर प्रतिबंध भी लगाता है, भले ही वह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही हो रहा हो।
- **'सार्वजनिक कार्यों' की परिभाषा:** विधेयक 'सार्वजनिक कार्यों' की परिभाषा प्रस्तुत करता है जिसमें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी भी बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। यह बुनियादी ढांचा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होना चाहिए जो सार्वजनिक सुरक्षा के विशिष्ट उदाहरण पर आधारित हो।
- **सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया:** अधिनियम के अनुसार, संबंधित केंद्र सरकार विभाग (जो निषिद्ध

क्षेत्र में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण करने का इरादा रखता है) को सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए। यदि कोई प्रश्न है कि क्या कोई निर्माण परियोजना 'सार्वजनिक कार्य' के रूप में योग्य है, तो इसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को भेजा जाएगा। यह प्राधिकरण केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें कारण सहित लिखित रूप में देता है जिसमें केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होता है।

सिक्किम में बुमचू बौद्ध महोत्सव

सिक्किम के ताशिदिंग मठ में बुमचू महोत्सव मनाया गया जिसमें भाग लेने के लिए पूरे सिक्किम के साथ-साथ पड़ोसी देशों जैसे भूटान व नेपाल आदि से श्रद्धालु आए।

बुमचू महोत्सव के बारे में:

- बुमचू महोत्सव ताशिदिंग मठ में एक पवित्र जल कलश अनुष्ठान है। यह एक अनोखा और महत्त्वपूर्ण अवसर है जो दुनिया भर से यात्रियों को आकर्षित करता है।
- बुमचू का तिब्बती भाषा में अर्थ 'पवित्र जल पात्र' होता है।
- सिक्किम में, बुमचू महोत्सव बहुत खुशी का समय होता है। इस आयोजन में तीर्थयात्री पूरे भारत के साथ-साथ भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे आसपास के देशों से ताशिदिंग की यात्रा करते हैं।
- यह चंद्र माह की 14 और 15 तारीख को होता है जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ता है।

ताशिदिंग मठ के बारे में:

- यह एक मंदिर परिसर है जो पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करता है।
- सिक्किम का यह मंदिर गंगटोक से 11 किमी की दूरी पर एक अन्य प्रसिद्ध स्थान नाथूला के रास्ते पर स्थित है।
- इसमें गंगटोक शहर के एक छोटे से हिस्से के साथ-साथ आसपास की आकर्षक पहाड़ियाँ और घाटियाँ भी शामिल हैं।
- हनुमान टोक, गंगटोक का सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान है जो हिंदू देवता भगवान हनुमान को समर्पित है।
- गर्मी के महीने (मार्च-जून) कंचनजंगा और अन्य पहाड़ों को देखने के लिए आदर्श होते हैं क्योंकि इस समय मौसम साफ होता है।
- यह रथोंग चू और रंगित नदी के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो ग्यालशिंग से 40 किमी तथा युकसाम के दक्षिण-पूर्व में 19 किमी दूर स्थित है।

पुरातनता

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स एंड फाइनेंस अनकवर्ड के सहयोग से द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में पाया गया है कि न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की सूची में कम से कम 77 वस्तुएं सुभाष कपूर से जुड़ी हैं जो तस्करी के आरोप में जेल में है। हालाँकि तस्करी की गई 16 कलाकृतियाँ भारत वापस लायी गई।

पुरातनता क्या है?

- पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 (जो 1 अप्रैल 1976 को लागू हुआ) ने 'पुरातनता' को 'कोई भी सिक्का, मूर्तिकला, पेंटिंग, शिलालेख, कला या शिल्प कौशल का अन्य कार्य' के रूप में परिभाषित किया। किसी इमारत या गुफा के अलावा कोई भी वस्तु, ऐतिहासिक रुचि की कोई भी वस्तु जो विज्ञान, कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, रीति-रिवाज, नैतिकता या राजनीति का उदाहरण हो और कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में हो, उसे पुरातनता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध:

- सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा रोकने के साधनों पर यूनेस्को 1970 कन्वेंशन ने 'सांस्कृतिक संपत्ति' को देशों द्वारा पुरातत्व, प्रागैतिहासिक, इतिहास, साहित्य, कला या विज्ञान के लिए निर्दिष्ट संपत्ति के रूप में परिभाषित किया है।'
- सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व का अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण ऐसी संपत्ति के मूल देशों की सांस्कृतिक विरासत के कुछ मुख्य कारण हैं जो सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है।
- 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और 2015 तथा 2016 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की थी।

भारतीय कानून के बारे में:

- भारत में संघ सूची की प्रविष्टि-67, राज्य सूची की प्रविष्टि-12 और संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि-40 देश की विरासत से संबंधित हैं।
- 1958 में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम निर्मित किया गया था।
- यूनेस्को सम्मेलन ने सरकार को 1 अप्रैल, 1976 से पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 (एएटीए) लागू करने के लिए प्रेरित किया। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई प्राधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्राचीन कला या खजाने का निर्यात करना वैध नहीं होगा।
- आयात या निर्यात का लाइसेंस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा प्रदान किया जाता है।

अम्बेडकर सर्किट पर भारत गौरव ट्रेन

सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन शुरू किया है जो बीआर अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण बौद्ध विरासत स्थलों को भी कवर करेगी।

अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- 'भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' का संचालन 'देखो अपना देश' पहल के तहत किया जा रहा है जिसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह पर्यटन मंत्रालय और रेलवे के बीच एक संयुक्त सहयोग है। भारत गौरव ट्रेन 'देखो अपना देश' के तहत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी कदम है।

- भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का उद्देश्य सभी यात्रियों को भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की झलक देना है।
- ट्रेन का उद्देश्य घरेलू पर्यटन और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है।

वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन

पहला दो दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें लगभग 30 देशों के बौद्ध भिक्षुओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। IBC एक व्यापक संगठन है जो दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका विषय 'समसामयिक चुनौतियों का जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन' था।

वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य:

- इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य धम्मसेवकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए दार्शनिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार करना था। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और शांतिपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए एक स्थायी मॉडल विकसित करना भी है।

बौद्ध धर्म के बारे में:

- बौद्ध धर्म एक गैर-आस्तिक (भगवान में कोई विश्वास नहीं रखने वाला) धर्म है जिसे एक दर्शन और नैतिक अनुशासन दोनों माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने की थी। मौर्य सम्राट अशोक महान ने न केवल भारत में, बल्कि पूरे मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए कई धम्मसेवकों को भेजा था। बौद्ध धर्म में चार प्राथमिक तीर्थ स्थल हैं जिसमें लुंबिनी (भगवान बुद्ध का जन्मस्थान), बोधगया (जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ), सारनाथ (बुद्ध के पहले उपदेश का स्थान) और कुशीनगर (जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ) शामिल हैं।

बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएँ:

- बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में प्रमुख रूप से लोकप्रिय हुई। इसके तहत बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों को प्रभावित किया जहां बुद्ध पथ पर चलकर कोई भी व्यक्ति बुद्ध के स्तर तक पहुंच सकता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा अधिक लोकप्रिय है जिसे सामान्यत: 'लामावाद' के नाम से भी जाना जाता है।

उत्तरमेरूर शिलालेख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तरमेरूर शिलालेख का जिक्र किया। उत्तरमेरूर में वैकुंड पेरुमल मंदिर की दीवारों पर 10वीं शताब्दी ईस्वी की स्थानीय शासन प्रणाली का खुलासा करने वाले विवरण अंकित हैं।

उत्तरमेरूर शिलालेख:

- उत्तरमेरूर वर्तमान कांचीपुरम जिले में स्थित है जो चेन्नई से लगभग 90 किमी दक्षिण-पूर्व में है। यह पल्लव और चोल शासन के दौरान निर्मित अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है।
- उत्तरमेरूर सदियों से चले आ रहे कई प्रसिद्ध शिलालेखों में से एक है जो परांतका प्रथम (907-953 ईस्वी) के शासनकाल का है। ये गाँव के स्वशासन का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं।

बिहान मेला

कोंध जनजाति (ओडिशा) के सदस्यों ने अपने त्यौहारों के वार्षिक कैलेंडर में एक त्यौहार जोड़ा है जिसका नाम बिहान मेला है। इस त्यौहार को बीज महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है।

बिहान मेले के बारे में:

- इस कार्यक्रम में स्वदेशी बीजों का संग्रह और संरक्षण शामिल है जिसमें दासपल्ला ब्लॉक के 40 गांवों के किसान उत्सव में भाग लेते हैं।
- खरीफ फसलों की कटाई के बाद महिलाएं देशी किस्मों के बीज इकट्ठा करती हैं और उन्हें मिट्टी के बर्तनों में संग्रहित करती हैं।
- दिसंबर में एक निर्दिष्ट दिन पर, वे बर्तनों को लाल और सफेद रूपांकनों से सजाते हैं, उन्हें बांस की टोकरी में रखते हैं और अपने सिर पर उस गांव में ले जाते हैं जहां मेला आयोजित किया जा रहा है।
- पुरुष ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते हुए उनके साथ चलते हैं।

महोत्सव की शुरुआत के कारण:

- हरित क्रांति के बाद से क्षेत्र के किसानों ने स्थानीय फसलों तथा किस्मों को छोड़ दिया है जो प्राकृतिक रूप से कीटों के प्रति प्रतिरोधी हैं और क्षेत्र के पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल हैं।
- इस क्षेत्र के किसान बड़े पैमाने पर निर्वाह किसान हैं जो मानसून वर्षा पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में अप्रत्याशित वर्षा या कीड़ों के संक्रमण के परिणामस्वरूप कई मौकों पर फसल बर्बाद हुई है।
- इससे न केवल उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इससे भूमि भी खराब हो गई है जिससे किसानों को फसल बर्बाद होने का खतरा बढ़ गया है।
- इस प्रकार बीज महोत्सव की स्थापना किसानों को मिश्रित फसल जैसे प्राचीन पारंपरिक तरीकों की ओर लौटने में सहायता करने के लिए की गई थी ताकि वे खुशी से रह सकें।

कोंध जनजाति के बारे में:

- कोंध ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वीरतापूर्ण मार्शल परंपराओं और स्वदेशी मूल्यों के लिए जाने जाते हैं जो प्रकृति के साथ सद्भाव

पर केंद्रित हैं।

- उनकी विभिन्न उप-जनजातियाँ हैं जिनमें डोंगरिया, कोवी, कुटिया, लांगुली, पेंगा, झरनिया तथा राज कोंध आदि शामिल हैं।
- कोंध लोग कुई भाषा बोलते हैं और इसे उड़िया लिपि में लिखते हैं।
- ओडिशा के कंधमाल जिले में कोंध की पचपन प्रतिशत आबादी रहती है जिसका नाम जनजाति के नाम पर रखा गया है।

थिरुनेली मंदिर

इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) ने सरकार से केरल के थिरुनेली में श्री महाविष्णु मंदिर में 600 साल पुराने 'विलाक्कुमाडोम' को संरक्षित करने का आग्रह किया है।

विलाक्कुमाडोम के बारे में:

- विलाक्कुमाडोम एक उत्कृष्ट ग्रेनाइट संरचना है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण 15वीं शताब्दी ईस्वी में केरल के वायनाड जिले के थिरुनेली में श्री महाविष्णु मंदिर में किया गया था।
- ऐसा कहा जाता है कि विलाक्कुमाडोम का कार्य मंदिर के संरक्षक, कोट्टायम राजा की अनुमति के बिना कूर्ग के राजा द्वारा शुरू किया गया था।

थिरुनेली मंदिर के बारे में:

- थिरुनेली मंदिर (जिसे अमलाका या सिद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है) केरल के वायनाड जिले में स्थित एक विष्णु मंदिर है।
- मंदिर का नाम एक घाटी में आंवले के पेड़ पर आराम करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति के नाम पर पड़ा है जिसे भगवान ब्रह्मा ने दुनिया का चक्कर लगाते समय खोजा था।
- थिरुनेली मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक केरल शैली का अनुसरण करती है। मंदिर में एक आंतरिक गर्भगृह है जो खपरैल की छत से घिरा है जिसके चारों ओर एक खुला प्रांगण शामिल है।
- मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार को ग्रेनाइट लैंप पोस्ट से सजाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवार ग्रेनाइट के खंभों से बंधी है जिन्हें क्यूबिकल शैली में काटा गया है जो आमतौर पर केरल में नहीं देखा जाता है।
- इस बात के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं कि चेर राजा भास्कर रवि वर्मा प्रथम (962-1019 ई.) के समय थिरुनेली दक्षिण भारत का एक महत्त्वपूर्ण शहर और तीर्थ केंद्र था।

इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के बारे में:

- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) की स्थापना 1984 में नई दिल्ली में विरासत जागरूकता और संरक्षण की दृष्टि से की गई थी।
- INTACH को देश भर में 190 से अधिक चैप्टर के साथ दुनिया के सबसे बड़े विरासत संगठनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जो विभिन्न प्रभागों के माध्यम से संचालित होता है।
- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज एक गैर-लाभकारी धर्मार्थ संगठन है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
- 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने INTACH को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ एक विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया।

बौद्ध लोककथाएँ

भारत के प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन (1893-1963) द्वारा पहली बार तिब्बत से प्राप्त पांच शास्त्रीय तिब्बती बौद्ध ग्रंथों का लंबे समय से प्रतीक्षित हिंदी अनुवाद अब मुद्रण के लिए तैयार है।

प्राचीन तिब्बती बौद्ध पांडुलिपियाँ क्या हैं?

- पवित्र ग्रंथ-कर्म विभाग सूत्र, प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र, आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान संग्रह व मध्यमकलंगकार कारिका भाष्य सहित अन्य दुर्लभ पांडुलिपियों का वर्गीकरण प्रमुख हैं।
- ये बौद्ध धर्म और उसके दर्शन पर ताड़ के पत्तों पर लिखे गए मूल संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती संस्करण हैं।
- पांडुलिपियों के ये सैकड़ों खंड ज्योतिष, तंत्र, ध्यान, चिकित्सा, दर्शन, न्याय और कानून सहित विभिन्न विषयों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करते हैं।

राहुल सांकृत्यायन:

- राहुल सांकृत्यायन एक भाषाविद् के साथ-साथ एक रचनात्मक बहुज्ञ भी थे।
- उन्हें संस्कृत, पाली और तिब्बती भाषा में पारंगत माना जाता है जो साहित्य, दर्शन, दुर्लभ पुस्तकों तथा कला में पारंगत थे।
- सांकृत्यायन ने 10,000 से अधिक तिब्बती पांडुलिपियों का संग्रह किया।

तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में:

- इसे 8वीं शताब्दी के अंत में तिब्बती राजा ट्रिसोंग डेट्सन के निमंत्रण पर भारत से लाया गया था जिन्होंने दो बौद्ध गुरुओं को तिब्बत में आमंत्रित किया था।
- नालंदा के मठाधीश शांतरक्षित भारत आने वाले पहले व्यक्ति थे, उनके बाद पद्मसंभव (जिन्हें गुरु रिनपोच के नाम से भी जाना जाता है और यहां तक कि निंग्मा-पा संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा उन्हें दूसरा बुद्ध भी माना जाता है) भारत आए थे।
- तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए अद्वितीय टुल्कु (अवतरित लामा) की संस्था है। तिब्बत में ऐसे कई लामा हुए हैं जिनमें से सबसे प्रसिद्ध दलाई लामा हैं।
- तिब्बती बौद्ध धर्म के अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं में शिक्षक या 'लामा' की स्थिति, जीवन और मृत्यु के बीच संबंध, अनुष्ठानों व दीक्षाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका, समृद्ध दृश्य प्रतिमा, तिब्बती धर्मों के तत्व, मंत्र तथा ध्यान अभ्यास शामिल हैं।

तिब्बती बौद्ध धर्म समूह: संस्थापक

- निंगमापा- पद्मसंभव (यह सबसे पुराना समुदाय है)

- काग्युपा - तिलोपा (988-1069)
- सक्यपा- कोंचोक ग्यालपो (1034-1102)
- गेलुग्पा त्सोंग खापा लोबसांग द्रक्पा (1357-1419)

नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट

पूर्वोत्तर भारत में 'नदी तट आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट' विकसित करने हेतु ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सात ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट क्या है?

- इसका उद्देश्य नदी पर्यटन को बढ़ावा देना और असम में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करना है। इसे 'हॉप-ऑन हॉप-ऑफ' मोड पर चलने वाली एक आधुनिक नौका सेवा के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- फेरी टर्मिनल पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय को आरामदायक वातावरण में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
- सर्किट में ब्रह्मपुत्र के तट पर सात ऐतिहासिक मंदिरों-कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वकलंता, डौल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और औनियाती सत्र को जोड़ने का प्रस्ताव है।

साइट का आध्यात्मिक महत्त्वः

- कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है।
- पांडुनाथ भगवान शिव और पार्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है।
- अश्वकलांता भगवान विष्णु और उनके अवतार से संबंधित पवित्र स्थान है।
- भगवान कृष्ण को समर्पित डोल गोविंदा रास लीला उत्सव के लिए जाना जाता है
- उमानंद भगवान शिव को समर्पित उमानंद द्वीप पर स्थित है।

कपिलेश्वर मंदिर

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण (एएसआई) की सूची में शामिल किया गया। कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारक सूची में लाने के लिए 5 मई को राजपत्र अधिसूचना आई थी। मंदिर की संरचना के बेहतर रखरखाव और सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है।

कपिलेश्वर मंदिर के बारे में:

- कपिलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में गजपति कपिलेंद्र देव द्वारा किया गया था जो अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है।
- कपिलेश्वर मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है जो अपनी भव्यता और सादगी के लिए जाना जाता है।
- यह मंदिर क्षेत्र के समृद्ध इतिहास के साथ-साथ ओडिशा के लोगों के गहन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व को परिभाषित करता है।
- कपिलेश्वर (शिव मंदिर है जिसे आमतौर पर 'कपिलेश्वर मंदिर' कहा जाता है) ओडिशा राज्य के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है।
- इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा कपिलेश्वर नाम से की जाती है जो कपिलप्रसाद क्षेत्र में स्थित है। यह भुवनेश्वर के 11वीं शताब्दी पुराने लिंगराज मंदिर से लगभग 1 किमी दूर है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणः

- एएसआई पुरातात्विक अनुसंधान और देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
- एएसआई का प्रमुख कार्य पुरातात्विक स्थलों, प्राचीन स्मारकों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का रखरखाव करना है।
- यह अधिनियम, 1958 के तहत प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के प्रावधानों के अनुसार सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह पुरातनता और कला खजाना अधिनियम, 1972 को भी नियंत्रित करता है।

सेंगोल

नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक एवं पवित्र 'सेंगोल' की स्थापना की गई।

'सेंगोल' के बारे में:

- 'सेंगोल' शब्द तमिल शब्द 'सेम्मई' से लिया गया है जिसका अर्थ 'धार्मिकता' है।

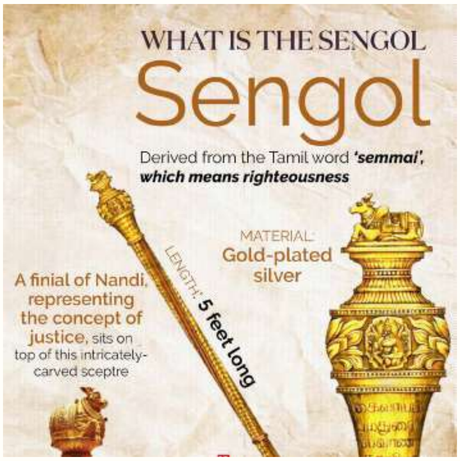

- सेंगोल राजदंड एक लंबी छड़ी जैसी वस्तु (5 फीट) है जो चांदी से बनी है जिसपर सोने की परत चढ़ी होती है।
- राजदंड के शीर्ष पर नंदी नामक बैल की नक्काशी है। यह देश में निष्पक्ष नेतृत्व के महत्त्व के बारे में सभी को याद दिलाने के लिए किया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध तमिलनाडु के प्राचीन साम्राज्य चोल राजवंश से है। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य अधीनम (पुजारियों) का आशीर्वाद प्राप्त है।
- सेंगोल राजदंड को जीवंत बनाने के लिए, चेन्नई स्थित जौहरी वुम्मिडी बंगारू चेट्टी ने इस ऐतिहासिक प्रतीक को तैयार करने का काम संभाला है।

ऐतिहासिक महत्त्वः

- चोल परंपरा में सत्ता हस्तांतरण समारोह के दौरान, राजदंड की प्रस्तुति के अलावा, नए शासक को अनाई (तमिल में 'अनाई') नामक एक आदेश दिया जाता था।
- यह आदेश क्षेत्र में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने, 'धर्म' के सिद्धांतों के प्रति अटूट पालन के साथ शासन करने की जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह लोगों की सेवा के लिए चुने गए लोगों के लिए समर्पित रहने का प्रतीक है।

दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग के सचिव ने वाराणसी में रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 'दिव्य कला शक्ति' कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

- दिव्य कला शक्ति विकलांग बच्चों और युवाओं के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
- दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम 2019 से देश के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है।
- दिव्य कला शक्ति विकलांग लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास करती है तथा माता-पिता और प्रशिक्षकों के योगदान को मान्यता देती है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्य कला शक्ति के आयोजन का प्रभारी है।
- छठा दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम इस बार वाराणसी में आयोजित किया गया जिसमें छह राज्यों 'पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड' के लगभग 100 कलाकारों ने प्रदर्शन किया।
- पांच क्षेत्रीय 'दिव्य कला शक्ति' कार्यक्रम पहले ही विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, चेन्नई, नई दिल्ली तथा गुवाहाटी में दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं।

रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बारे में:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया जिसे 'रुद्राक्ष' के नाम से भी जाना जाता है।
- रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को सांस्कृतिक और आधुनिक समारोहों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।
- 2015 में भारत और जापान के प्रतिनिधियों द्वारा धार्मिक तथा सांस्कृतिक शहर वाराणसी में रुद्राक्ष नामक एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की योजना विकसित किया गया था जो मई 2021 से कार्यात्मक बना हुआ है।
- इस कन्वेंशन सेंटर के मुख्य हॉल में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। हॉल को लोगों की संख्या के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटने की भी व्यवस्था की गई है। कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह से वातानुकूलित है और आधुनिक 'बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम' से सुसज्जित है जिसके माध्यम से सभी प्रबंधन को बारीकी से नियंत्रित किया जा सकता है।

देवांकनम चारुहरिथम (भगवान का सुंदर हरा निवास)

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए केरल सरकार ने पांच देवस्वोम बोर्डों द्वारा प्रबंधित मंदिरों के हरित आवरण में सुधार के लिए देवांकनम चारुहरिथम परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में राज्य में परित्यक्त मंदिर तालाबों का जीर्णोद्धार और पवित्र उपवनों की रक्षा करके जल संसाधनों को संरक्षित करने की भी परिकल्पना की गई है।

परियोजना के बारे में:

- 'देवांकनम चारुहरिथम' (भगवान के सुंदर हरे निवास) परियोजना को राज्य भर के 3,800 से अधिक मंदिरों में लागू किया जाएगा जिनका प्रबंधन पांच देवस्वोम बोर्डों द्वारा किया जाता है।
- परियोजना का प्राथमिक फोकस मंदिरों के आसपास हरित आवरण में सुधार करना है। विचार यह है कि देवस्वोम बोर्ड के पास मौजूद भूमि बैंकों का उपयोग किया जाए और इन भूमियों पर पेड़ उगाए जाएं जिससे राज्य में समग्र हरियाली बढ़े।
- इसके अतिरिक्त परियोजना में मंदिर परिसर के भीतर विभिन्न फूलों वाले पौधे और फल देने वाले पेड़ लगाने की परिकल्पना की गई है। यह न केवल सौंदर्यशास्त्र में योगदान देगा, बल्कि दैनिक उपयोग के लिए फूलों और फलों की स्थायी आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा जिससे मंदिर आत्मनिर्भर बनेंगे।

मालचा महल

दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिकारियों से मालचा महल के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए विभिन्न फूलों वाले पेड़ों का पांच स्तरीय वृक्षारोपण का आदेश दिया। इसके तहतम जकरंदा, गुलमोहर, बोगेनविलिया, अमलतास और चिनार जैसे पेड़ों का रोपण किया गया।

मालचा महल के बारे में:

- मालचा महल दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में स्थित है। इसे 1325 में तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था जिसका इस्तेमाल शिकारगाह के रूप में किया जाता था।
- यह बाद में अवध के नवाबों के वंशजों का निवास स्थान बन गया।
- अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इसे 'विलायत महल' के नाम से जाना जाने लगा जिन्होंने दावा किया था कि वह अवध के शाही परिवार की सदस्या थीं। उन्हें यह महल 1985 में सरकार द्वारा दिया गया था।
- तीन दशकों से अधिक समय तक यह बेगम विलायत महल परिवार का था जिसने दावा किया था कि वह अवध के नवाबों का वंशज है जिसके अंतिम सदस्य, 'प्रिंस' अली रजा की 2017 में मृत्यु

हो गई थी।

फिरोज शाह तुगलक के बारे में:

- यह अपने चचेरे भाई मुहम्मद-बिन तुगलक (जिसने 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किया) की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा।
- फिरोज शाह, तुगलक वंश का तीसरा शासक था जो 1351 से 1388 ई. तक सत्ता में रहा।
- फिरोज शाह ने अपने शासन के दौरान साम्राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम किया। उन्होंने जलाशयों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया तथा कुएं खुदवाए एवं नहरें, विश्राम गृह और अस्पताल भी बनवाए।
- उन्होंने दिल्ली के आसपास कई शहरों की स्थापना की जिनमें जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद शामिल हैं।
- कुतुब मीनार की मरम्मत का कार्य भी उनके शासनकाल में किया गया था।
- उन्होंने अपनी आत्मकथा 'फुतुहत-ए-फिरोजशाही' लिखी।
- उन्होंने सभी प्रकार के कठोर दंड बंद कर दिये।

फिरोज शाह तुगलक से संबंधित महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

- दीवान-ए-खैरात - दान का कार्यालय
- दीवान-ए-बुंदगान - दासों का विभाग
- खराज: भूमि कर के दसवें हिस्से के बराबर

हमारी भाषा, हमारी विरासत

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में 'हमारी भाषा, हमारी विरासत' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से युवाओं को भारत की प्राचीनतम गिलगित पांडुलिपियों से परिचित कराया गया।

प्रदर्शनी का महत्त्व:

- यह प्रदर्शनी एक राष्ट्र के रूप में भारत में भाषाई विविधता की बहुमूल्य विरासत को याद करने का एक प्रयास है।
- 'एक राष्ट्र अनेक भाषा' भारत को असाधारण भाषाई विविधता का वरदान प्राप्त है। विश्व स्तर पर बोली जाने वाली 7,111 भाषाओं में से लगभग 788 भाषाएँ अकेले भारत में बोली जाती हैं।
- प्रदर्शनी देश भर में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से संबंधित अभिलेखों के विशाल भंडार पर प्रकाश डालती है।
- इस प्रकार पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और नाइजीरिया के साथ, भारत दुनिया के चार सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है।

गिलगित पांडुलिपियां:

- राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर 'हमारी भाषा, हमारी विरासत' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- इस दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच लिखी गई गिलगित पांडुलिपि प्रदान किया है जो भारत की पांडुलिपियों का सबसे पुराना संग्रह है।
- यह दुनिया की सबसे पुरानी पांडुलिपियों में से एक है।
- गिलगित पांडुलिपियों की खोज नाऊपुर गांव (गिलगित क्षेत्र) के तीन चरणों में की गई थी, जबकि पहली बार 1931 में पुरातत्वविद् सर ऑरेल स्टीन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
- यह कश्मीर क्षेत्र में बर्च पेड़ों की छाल की आंतरिक परत पर लिखे गए फोलियो दस्तावेजों, तत्त्वार्थ सूत्र, रामायण और श्रीमद्भगवद गीता में विहित तथा गैर-विहित जैन और बौद्ध रचनाएँ प्रस्तुत करता है। आधिकारिक सरकार की फाइलें, औपनिवेशिक शासन के तहत प्रतिबंधित साहित्य और एनएआई लाइब्रेरी में रखे दुर्लभ पुस्तकों के समृद्ध संग्रह इसमें शामिल हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार:

- राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च, 1891 को कलकत्ता में शाही अभिलेख विभाग के रूप में की गई थी।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार की वर्तमान इमारत का निर्माण 1926 में नई दिल्ली में किया गया था।
- इस इमारत का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था।
- कलकत्ता से नई दिल्ली तक सभी अभिलेखों का स्थानांतरण 1937 में पूरा हुआ।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार 1993 के सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम और 1997 के सार्वजनिक रिकॉर्ड नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भी है।

गीता प्रेस ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता

वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, गोरखपुर को प्रदान किया गया। गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसा और अन्य गांधीवादी मूल्यों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार मिला है।

- 1923 में स्थापित गीता प्रेस को दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसने 14 भाषाओं में 41.7 मिलियन पुस्तकें बेची हैं जिनमें 16.21 मिलियन श्रीमद्भगवद गीता पुस्तकें भी शामिल हैं।

गांधी शांति पुरस्कार के बारे में:

- गौरतलब है कि गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी के विचारों को श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाने वाला एक वार्षिक सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी।
- यह पुरस्कार महात्मा गांधी की मान्यताओं को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।
- यह उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है जिन्होंने अहिंसा तथा गांधीवादी तकनीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- गांधी शांति पुरस्कार के तहत एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

पुरातत्वविदों ने गुंटूर में मध्यपाषाण युग के शैल चित्रों की खोज की

पुरातत्वविदों को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मेसोलिथिक युग से संबंधित शैल चित्र मिले हैं। इससे स्थापत्य कला के क्षेत्र में नई जानकारी मिलने का संकेत है।

खोजे गए शैलचित्रों के बारे में:

- प्राकृतिक रूप से निर्मित इन पांच गुफाओं में से दो को गुफाओं की पिछली दीवारों और छत पर शैल चित्रों के विशिष्ट चित्रण से सजाया जाता है जो लगभग 5000 ईसा पूर्व मेसोलिथिक युग के लोगों द्वारा बनाए गए थे।
- ये प्रागैतिहासिक मनुष्यों के आश्रय स्थल होते थे जो इस स्थान पर रहते थे।
- चित्रों में एक आदमी को जमीन के टुकड़े को जोतते हुए दर्शाया गया है। यह अर्ध-व्यवस्थित जीवन शैली का सूचक है जिसमें इस समुदाय के सदस्य फसलों की खेती करते थे।
- अन्य चित्रों में एक आदमी को अपने बाएं हाथ से एक जंगली बकरी को पकड़े हुए और उसे नियंत्रित करने के लिए हुक जैसी डिवाइस का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। दूसरे में दो जोड़ों को हाथ ऊपर उठाकर खड़े दिखाया गया है, जबकि एक बच्चा उनके पीछे खड़ा है।
- पेंटिंग्स 'प्राकृतिक सफेद काओलिन और लाल गेरू रंग' से बनाई गई थीं जिनमें से अधिकांश 'हवा और आंधी' के संपर्क के कारण 'बुरी तरह क्षतिग्रस्त' हो गईं।

मध्यपाषाण काल क्या है?

- मेसोलिथिक काल (जिसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है) की तकनीकी पहचान छोटे पत्थर के औजारों या 'माइक्रोलिथ्स' का उपयोग है।
- नवपाषाण काल अपने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों के लिए जाना जाता था।
- मेसोलिथिक लोगों ने शिकार के लिए धनुष और तीर जैसी कई तकनीकों का आविष्कार किया।

खर्ची पूजा 2023

भारत के प्रधानमंत्री ने खर्ची पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, खर्ची पूजा उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुरा में आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन पृथ्वी देवी की पूजा करना एक बहुत पुराना अनुष्ठान है जो आमतौर पर ईसाई कैलेंडर के अनुसार जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में होता है।

खर्ची पूजा के बारे में:

- यह त्रिपुरा के सबसे महत्त्वपूर्ण उत्सवों में से एक है।
- यह पूरे जुलाई और अगस्त के महीनों में अमावस्या के आठवें दिन आयोजित किया जाता है।
- यह आषाढ़ माह में 'शुक्ल अष्टमी' के दिन होता है।
- पूजा के दिन, चंताई सदस्यों द्वारा चौदह देवताओं को मंदिर से सैदरा नदी तक ले जाया जाता है और मंदिर में लौटने से पहले पवित्र नदी के पानी में स्नान कराया जाता है।
- इस उत्सव के समारोह सच्ची त्रिपुरी परंपराओं से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।

हुल दिवस

प्रधानमंत्री ने साहेबगंज जिले के भोगनाडीह में 1855 के संथाल (हुल) विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बहादुर आदिवासी नेताओं सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव को श्रद्धांजलि दी।

संथाल विद्रोह के बारे में:

- संथाल विद्रोह या हूल क्रांति की शुरुआत 30 जून 1855 को वर्तमान झारखंड में हुई थी।
- यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था।
- विद्रोह शुरू करने में मदद करने वाले प्रमुख नेता भाई सिद्धो, कान्हो, चाँद और भैरव तथा उनकी बहनें फूलो व झानो थे।
- संगठित आंदोलनों, हथियारों और रणनीति के उचित उपयोग व प्रशिक्षित नेतृत्व के कारण संथाल विद्रोह को 'विद्रोहों के खिलाफ संगठित युद्ध' के रूप में जाना जाता है।
- विद्रोह की शुरुआत के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया जो 3 जनवरी, 1856 तक प्रभावी रहा। इसके बाद मार्शल लॉ लागू किया गया और प्रेसीडेंसी सेनाएं विद्रोह को दबाने में सफल रहीं।
- संथाल विद्रोह ने आगामी विद्रोहों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, विशेष रूप से 1857 के विद्रोह में संथाल की भागीदारी।
- यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था जिसने झारखंड में भविष्य के आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया था।

लंबानी कढ़ाई पैच

हम्पी में जी-20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक में, लगभग 450 लंबानी कारीगरों ने एक साथ संदूर कढ़ाई के 1,755 से अधिक अद्वितीय पैच का संग्रह किया था जिसने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया।

लंबानी कढ़ाई के बारे में:

- लंबानी कढ़ाई कपड़ा अलंकरण का एक जटिल रूप है जो रंगीन धागों, सीसों के काम और सिलाई पैटर्न की विशेषता है।
- लंबानी शिल्प परंपरा में एक सुंदर कपड़ा बनाने के लिए फेंके गए कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ सिलना शामिल है।
- यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है जो मुख्य रूप से कर्नाटक के कई गांवों जैसे संदुर, केरी टांडा, मरियम्मनहल्ली, कादिरामपुर आदि में प्रचलित है।

- पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में कपड़ा परंपराओं के साथ लंबानी शिल्प का अंतर्संबंध खानाबदोश समुदायों की साझा कलात्मक संस्कृति तथा ऐतिहासिक प्रवासन को रेखांकित करता है।

रुद्रगिरि हिल रॉक कला

आंध्र प्रदेश में रुद्रगिरि पहाड़ी पर एक शैल चित्र की खोज की गई है जो मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कृतियों के संयोजन का खुलासा करता है।

भित्तिचित्र चित्रकला से संबंधित मुख्य बातें:

- रुद्रगिरि पहाड़ी की पहली गुफा दक्षिणी छोर से शुरू होकर दो वानर भाईयों (बाली और सुग्रीव) के बीच युद्ध का चित्रण करते हुए एक कथात्मक भित्तिचित्र प्रस्तुत करती है। ये दोनों आकृतियां युद्ध के मैदान में गदा लेकर खड़ी हैं जिनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा है।
- इस कथा में भगवान राम को सुग्रीव के पीछे खड़े होकर बाली पर तीर चलाते हुए दिखाया गया है। खतीसरी गुफा में मेसोलिथिक युग के प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्रदर्शित किये गये हैं। इसमें 'अंजलि' मुद्रा में हाथ जोड़े हुए भगवान हनुमान की सुंदर आकृति को दर्शाया गया है।

काकतीय राजवंश के बारे में:

- काकतीय राजवंश के गणपति देव महाराजा (1199-1262 ई.) मुप्पावरम मंदिर के संस्थापक थे जिन्होंने रुद्रगिरि में पाई गई प्राचीन भित्ति विरासत को संरक्षण दिया था।
- रुद्रगिरि के शैलाश्रयों पर बने शानदार भित्तिचित्रों और वारंगल जिले के मुप्पावरम तथा पांडवुलागुट्टा में खोजे गए भित्तिचित्रों के बीच समानता पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि रुद्रगिरि में चित्रित रामायण के दृश्य मुप्पावरम कलाकृतियों से संबंधित हैं।

भारत मंडपम

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री द्वारा 'भारत मंडपम' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर (IECC) परिसर का उद्घाटन किया गया है।

भारत मंडपम से संबंधित मुख्य बातें:

- इसे 2700 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। यह भारत को वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- भारत मंडपम को भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की तर्ज पर बनाया गया है जो सार्वजनिक कार्यों के लिए एक मंडप है। यह परिसर सभी के लिए सुलभ होगा जिसमें देश को एक विकसित और आधुनिक राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक सुविधाएं निहित हैं।

कालबेलिया नृत्य

राष्ट्रीय लोक एवं जनजातीय कला महोत्सव में कालबेलिया नृत्य प्रदर्शित किया गया। इस कला का अपना ऐतिहासिक महत्त्व है।

कालबेलिया नृत्य के बारे में:

- कालबेलिया नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी।
- यह राजस्थान में सपेरों की खानाबदोश जनजाति कालबेलिया के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक जीवंत तथा ऊर्जावान नृत्य है।
- यह एक कामुक नृत्य है जिसमें नर्तक जटिल फुटवर्क करते हैं, साथ ही अपनी बाहों और शरीर को हिलाते हैं।
- कालबेलिया नृत्य अधिकतर महिलाएं ही करती हैं। नृत्य का मुख्य रूप सर्पीन चाल है जिसमें महिलाएं एक विशेष वस्त्र धारण करती हैं।
- इसके अतिरिक्त महिलाएं लहंगा, ट्यूनिक्स और ओढ़नी पहनती हैं जिनमें से सभी पर जटिल कढ़ाई होती है।
- कालबेलिया होली जैसे महत्त्वपूर्ण अवसरों पर विशेष नृत्य करते हैं जिससे उनके सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में अधिक विविधता और महत्त्व जुड़ जाता है।

कालबेलिया जनजाति के बारे में:

- कालबेलिया भारत के राजस्थान के थार रेगिस्तान की साँपों को वश में करने वाली अर्थात सपेरों की एक जनजाति है।
- वे ऋषि कनीफनाथ के भक्त हैं जिन्होंने जहर का कटोरा पीने के बाद जहरीले सांपों और जानवरों पर अधिकार कर लिया था।
- डालीवाल और मेवाड़ा इनके दो प्राथमिक समूह हैं।
- अतीत में कालबेलिया लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बार-बार यात्रा करने का इतिहास रहा है। उनकी पारंपरिक आजीविका सांपों का शिकार करना और सांप के जहर का व्यापार करना था।
- वे विभिन्न प्रकार के जानवर रखते हैं। जैसे-कुत्ते, मुर्गियाँ, घोड़े, गधे, सूअर, बकरी इत्यादि।
- नाग पंचमी का पवित्र दिन कालबेलियाओं द्वारा मनाया जाता है जो सांस्कृतिक हिंदू हैं एवं सांपों, विशेष रूप से नागा और मनसा देवताओं की पूजा करते हैं।

कुवी और देसिया पुस्तकें

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भुवनेश्वर में कुवी और देसिया पुस्तकें लॉन्च किया। यह ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट, डाक विभाग और एनसीईआरटी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है।

कुवी और देसिया पुस्तकों के बारे में:

- कुवी और देसिया पुस्तकें ओडिशा के आदिवासी समुदाय को एक मजबूत व शैक्षिक आधार प्रदान करेंगी, साथ ही सांस्कृतिक, भाषाई विरासत और पहचान को संरक्षित करेंगी।
- ये किताबें छात्रों को उनके इलाके की प्रकृति और संस्कृति पर

आधारित चित्रों, कहानियों व गीतों की मदद से उनके बोलने के कौशल, सीखने के परिणामों और संज्ञानात्मक विकास को बेहतर बनाने में मदद करेंगी।

- ये किताबें विशेष रूप से उन बच्चों के लिए डिजाइन की गई हैं जो ओडिशा के अविभाजित कोरापुट क्षेत्र में आदिवासी भाषाएँ 'कुवी' और 'देसिया' बोलते हैं।

सीताकली लोक कला

विविध पृष्ठभूमि के कलाकारों के एक समूह, पेरिनाड सीताकली संघम ने 2017 में लुप्त हो रही सीताकली लोक कला को पुनर्जीवित किया। इस समूह ने हाल में पहली बार केरल के बाहर प्रदर्शन किया है।

सीताकली लोक कला के बारे में:

- प्रारंभिक समय में सीताकली का प्रदर्शन फसल उत्सव ओणम के हिस्से के रूप में किया जाता था।
- यह एक द्रविड़ नृत्य शैली है जो वनयात्रा (जंगल में निर्वासन) से लेकर सीता के अंधारधनम (पृथ्वी पर अवतरण) तक के हिस्सों को चित्रित करती है।
- यह एक नृत्य नाटक है जो मुख्य रूप से वेद और पुलाया समुदायों से संबंधित दलित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओणम के दौरान हर घर में रामायण के छोटे-छोटे दृश्यों का मंचन किया जाता है।
- यह गाने और कहानी कहने का रूप है, जबकि गंजीरा, मणिकट्टा, चिरट्टा तथा कैमानी संगत हैं।
- इसमें वेशभूषा और मेकअप आकर्षक होता है। राम और लक्ष्मण के पात्र हरे रंग में दिखाई देते हैं, क्योंकि हरे रंग का उपयोग कथकली में देवी-देवताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है।

पुलिक्कली नृत्य

त्रिशूर में पुलिक्कली नृत्य (जिसका इतिहास 200 वर्ष से अधिक पुराना है) ने वैश्विक ख्याति प्राप्त की है।

पुलिक्कली नृत्य के बारे में:

- पुलिक्कली का अनुवाद 'टाइगर प्ले' या 'टाइगर डांस' है जिसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ और तेंदुए की तरह रंगते हैं तथा पारंपरिक ताल वाद्ययंत्रों की धुन पर सड़कों पर नृत्य करते हैं।
- पुलिक्कली (जिसे 'पुली काली' या 'पुली केट्टू' के नाम से भी जाना जाता है) एक मनोरंजक लोक कला है जो केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाले ओणम उत्सव का एक अटूट हिस्सा है।
- इसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में केरल के त्रिशूर जिले में हुई थी। हालांकि इसकी उत्पत्ति का श्रेय राजा राम वर्मा को दिया जाता है जिन्हें कोच्चि के महाराजा सक्तन थंपुरन के नाम से भी जाना जाता है।
- पुलिक्कली में बाघ और शिकारियों की तरह चमकीले पीले, लाल तथा काले कपड़े पहने कलाकार उडुक्कू और थाकिल जैसे वाद्ययंत्रों की धुनों पर नृत्य करते हैं।
- यह प्रदर्शन बाघ के शिकार की थीम के इर्द-गिर्द घूमता है।
- पुलिक्कली नृत्य गतिविधियों के लिए सख्त नियमों का पालन नहीं करती है। प्रत्येक कलाकार अपनी अनूठी शैली बनाता है जिसके परिणामस्वरूप एक गतिशील और व्यक्तिगत प्रदर्शन होता है।

बांग्लार माटी, बांग्लार जोल

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके बंगाली कैलेंडर के पहले दिन पोइला बैशाख (15 अप्रैल) को राज्य का स्थापना दिवस और रवींद्रनाथ टैगोर की 'बांग्लार माटी, बांग्लार जोल' को राज्य गान घोषित किया।

बांग्लार माटी और बांग्लार जोल के बारे में:

- यह गीत टैगोर द्वारा 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के जवाब में लिखा गया था जो राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक विभाजनकारी औपनिवेशिक रणनीति थी।
- 1905 में बंगाल के विभाजन पर कर्जन के निर्णय का उद्देश्य विविध बंगाली भाषी आबादी के बीच विभाजन और संघर्ष पैदा करना था। हालाँकि, इसका विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगालियों को एकजुट करके स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया था जिसने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त किया था।
- टैगोर विभाजन के मुखर आलोचक थे और उन्होंने अपने गीतों तथा कविताओं के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
- 'बांग्लार माटी, बांग्लार जोल' ने बंगाल की सुंदरता, इसके प्राकृतिक परिवेश, भाषा, लोगों और आत्मा का जश्न मनाते हुए बंगालियों के बीच एकता का आह्वान किया।

फणीगिरि की बौद्ध कलाकृतियाँ

फणीगिरी कलाकृतियाँ (जो 200 ईसा पूर्व-400 ईस्वी की हैं और 1942 में खोजी गई थीं) न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित की गई हैं। उन्हें 'द ट्री एंड द सर्पेंट' नामक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था जहां वे बौद्ध धर्म के इतिहास में एक युगांतरकारी बदलाव का वर्णन करते हैं।

फणीगिरी कलाकृतियों के बारे में:

- फणीगिरी बौद्ध स्थल को इस सहस्राब्दी में बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में सबसे महत्त्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है।
- फणीगिरी (जिसे अक्सर 'सांपों की पहाड़ी' कहा जाता है) हैदराबाद से लगभग 150 किमी दूर एक छोटा सा गाँव है जिसका बौद्ध धर्म में ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्त्व है।
- फणीगिरी में खोजे गए थोराना बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सांची के दक्षिण में खोजे गए सबसे पुराने थोराना में से एक हैं।
- थोराना में एक पैनल होता है जो महायान और हीनयान दोनों

विचारधाराओं को दर्शाता है।

- फणीगिरी बुद्ध के देवत्व और बौद्ध प्रथाओं में संतत्व तथा अनुष्ठान की ओर संक्रमण का प्रमाण प्रदान करता है।
- फणीगिरी से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बुद्ध की दिव्यता को दर्शाते हैं जिससे इस परिवर्तन को दिनांकित किया जा सकता है।
- ये कलाकृतियाँ रोमन टोगा पहने हुए बुद्ध की नक्काशीदार चूना पत्थर की मूर्ति को दर्शाती हैं।

नुआखाई महोत्सव

ओडिशा के कालाहांडी जिले के बहादुरपदर, पलकापारा और पाथरला गांवों में नुआखाई नामक कृषि उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। यह चार चरणों में आयोजित होने वाला 40 दिवसीय उत्सव है।

नुआखाई महोत्सव से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- नुआखाई एक संबलपुरी त्यौहार है जो पश्चिमी ओडिशा में अत्यधिक लोकप्रिय है। यह क्षेत्र आदिवासी लोगों से घनी आबादी वाला है।
- इस दिन लोग नई कटी हुई 'नबान्हा' फसल को अपने संबंधित देवताओं को चढ़ाते हैं जिसके बाद संबलपुर में देवी समलेश्वरी की पूजा की जाती है।
- नुआखाई में नुआ अर्थ 'नया' और खाई का अर्थ 'भोजन' होता है।
- यह त्यौहार हमारी संस्कृति में एकता, भाईचारा और जुड़ाव को दर्शाता है।
- त्यौहार का समापन स्थानीय संस्कृति और समाज की विभिन्न परंपराओं को व्यक्त करने वाले लोक गीतों, नृत्यों तथा नाटकों के साथ होता है।

ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। लगभग छह साल पहले संकल्पित 'स्टैच्यू ऑफ वननेस' में शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है।

आदि शंकराचार्य के बारे में:

- वह एक भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री, शंकर (जगतगुरु) तथा प्राचीन हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखने वाले थे।
- उन्होंने गुरु गोविंदभगवतपाद से मार्गदर्शन लिया जिनके अधीन उन्होंने 'गौड़पदीयकारिका', 'ब्रह्म सूत्र', वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया।
- शंकर ने 'अद्वैत वेदांत' और 'दशनामी संप्रदाय' का प्रचार किया।
- **अद्वैत वेदांत-** यह वेदांत का एक संस्करण है जिसका अनुवाद अद्वैतवाद के रूप में किया गया है।

शांतिनिकेतन और होयसल मंदिर यूनेस्को की सूची में शामिल

भारत के शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल (41वें) और कर्नाटक के होयसल मंदिर (42वें) को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया जो भारत के लिए 'बड़े गर्व' की बात है।

शांतिनिकेतन के बारे में:

- इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।
- शांतिनिकेतन जिसका अर्थ 'शांति का निवास' है जो 1901 में बनना शुरू हुआ था, यहीं पर टैगोर ने बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी।
- कवि ने इसका वर्णन 'जहाँ दुनिया घोंसले में अपना घर बनाती है' के रूप में की है।

होयसल मंदिर के बारे में:

- इन मंदिरों का निर्माण होयसल साम्राज्य द्वारा किया गया था जिसने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था।
- ये तीन होयसल मंदिर पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारक हैं।
- होयसल मंदिर मूल रूप से द्रविड़ियन रूपांकनों को दर्शाते हैं जो मध्य भारत में प्रचलित भूमिजा शैली, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ियन शैलियों के प्रभाव को दर्शाते हैं।
- होयसल राजा कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया।

यूनेस्को के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है।
- इसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- यूनेस्को की स्थापना 1945 में राष्ट्र संघ की बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।
- इसमें 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य तथा गैर-सरकारी, अंतर-सरकारी व निजी क्षेत्रों में भागीदार शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय पेरिस में विश्व धरोहर केंद्र में स्थित है।

सरना धार्मिक संहिता

झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासियों के लिए 'सरना धार्मिक कोड' को मान्यता देने की मांग की गई है। झारखंड राज्य में आदिवासी आबादी पिछले आठ दशकों में 38% से घटकर 26% हो गई है। उनकी जनसंख्या में गिरावट से संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास की नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सरना धर्म के बारे में:

- जो लोग सरना धर्म का पालन करते हैं, वे खुद को एक धार्मिक समूह से संबंधित मानते हैं।
- सरना कोड की मान्यता यह सुनिश्चित करेगी कि प्रकृति-पूजक आदिवासी समुदाय अपनी पहचान को संरक्षित कर सके।
- झारखंड की एक बड़ी आबादी सरना धर्म का पालन करती है।
- इस धर्म के जीवंत ग्रंथ जल, जंगल, जमीन और प्रकृति हैं। यहां की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श और मान्यताएं भी सभी प्रचलित धर्मों से भिन्न हैं।
- इस धर्म को मानने वाले समुदाय मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वनों की सुरक्षा में विश्वास करते हैं और पेड़ों तथा पहाड़ों की पूजा करते हैं।
- इसके अनुयायी झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

सरना धर्म कोड क्या है?

- सरना धर्म कोड की मांग का मतलब है कि भारत में जनगणना के दौरान हर व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें अन्य सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का उल्लेख करने के लिए एक अलग कॉलम बनाया जाना चाहिए।
- जिस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग जनगणना प्रपत्र में अपने धर्म का उल्लेख करते हैं, उसी प्रकार आदिवासियों को भी अपने सरना धर्म का उल्लेख करने में सक्षम होना चाहिए।

वाघ नख

महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रसिद्ध 'वाघ नख' को वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्राचीन हथियार को तीन साल की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार को दिया जाएगा। यह तीन वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाएगा।

वाघ नख क्या है?

- वाघ नख (जिसका शाब्दिक अर्थ 'बाघ का पंजा' होता है) एक मध्ययुगीन पंजे जैसा खंजर है जिसका उपयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता था।
- वाघ नख एक पंजे की तरह होते हैं और एक बैंड पर लगे होते हैं। इसमें पहली और चौथी उंगलियों के लिए दो छल्ले होते हैं।
- पोरों पर फिट होने या हथेली के नीचे छिपे रहने के लिए डिजाइन किए गए इस हथियार में चार या पांच घुमावदार ब्लेड होते थे जो एक दस्ताने या पट्टा से जुड़ा होता था।
- यह व्यक्तिगत सुरक्षा या गुप्त हमले के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार था जो आसानी से त्वचा की मांस को काट सकता था।

कोंगाली बिहु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोंगाली बिहू के शुभ अवसर पर असम के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

कोंगाली बिहू के बारे में:

- कोंगाली बिहू भारत के असम राज्य में मनाए जाने वाले तीन बिहू त्यौहारों में से एक है।
- बिहू त्यौहार असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो कृषि चक्र से जुड़े हुए हैं।
- कोंगाली बिहू (जिसे कटी बिहू के नाम से भी जाना जाता है) दूसरा बिहू त्यौहार है और अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जो बुआई के मौसम के अंत तथा कटाई की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है।
- **कृषि महत्त्व:** कोंगाली बिहू मुख्य रूप से एक कृषि त्यौहार है जो फसलों की बुआई के पूरा होने और उनकी वृद्धि की शुरुआत का प्रतीक है।

वज्र मुष्टि कलगा

वाडियार परिवार ने वज्र मुष्टी कलगा का आयोजन किया जो एक मार्शल आर्ट का रूप है। इसका प्रदर्शन प्राय: दशहरे के दौरान होता है।

वज्र मुष्टि कलगा क्या है?

- वज्र मुष्टी कलगा मार्शल आर्ट का एक रूप है।
- इसमें प्रतिद्वंद्वी के हथियार का मुकाबला करते हुए प्रतिद्वंद्वी को निहत्था करना होता है।
- इसमें हाथापाई, कुश्ती और प्रहार जैसी हाथों-हाथ लड़ाई का आयोजन किया जाता है।
- हथियार में नक्कल डस्टर का उपयोग होता है जो एक छोटा धातु हथियार है।
- पोर डस्टर सामग्री जानवरों के सींगों से बनाई जाती है जो सेनानियों के पोर या हथेली पर पहनी जाती है।

विशेषताएँ

- 'वज्र मुष्टी कलगा' पारंपरिक कुश्ती से अलग कुश्ती का एक रूप है जिसमें दो जेट्या एक-दूसरे के सिर पर पोर से वार करते हैं।
- जो सबसे पहले प्रतिद्वंद्वी के सिर से खून निकालता है उसे विजेता घोषित किया जाता है।
- इसमें लड़ाई वास्तविक होती है और जेटी प्रतिद्वंद्वी के सिर से खून निकालने के लिए सभी प्रयास करता है। रेफरी पहली बूंद देखने के बाद हस्तक्षेप करता है। इसमें कभी-कभी लड़ाई कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है।
- यह 14वीं-17वीं शताब्दी के विजयनगर शासकों के दौरान लोकप्रिय था।
- मध्यकालीन पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य में नवरात्रि उत्सव के दौरान कुश्ती के इस रूप को देखा और इसका विस्तृत विवरण दिया।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Offline & Online

लक्ष्यभेद

"JOIN US AND FEEL THE DIFFERENCE"

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

ALL INDIA CIVIL SERVICES EXAMINATION (PRELIMS) TEST SERIES 2024

Phase-II Starting From
7th January, 2024

Total Test-22
(Sectional Test-7 & GS Full Length-10 & CSAT Test-5)

- One to one interaction & doubt clearing session through webinar (Google Meet) / WhatsApp .
- Personal guidance to students for exam related strategy.
- 6 Months subscription of Perfect-7 Current Affairs Magazine (Bi-Monthly).
- For Students who will take admission in Lakshyabhed **UPSC** Prelims Test Series 2024, there will be **50% Off** in UPPCS Test Series 2024 also.
- **50% Off** for those Students who have cleared Prelims and **70% Off** or those Students who have cleared Mains (For both IAS and PCS).
- **100% Off** for those who are finally selected in allied services (for both IAS and PCS).

OFFLINE CENTRE

Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474 Varanasi Ph: 7408098888, 9838529010

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4700+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 70

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029, **Varanasi :** Ph: 7408098888, 9898529010